राष्ट्रीय संस्करण

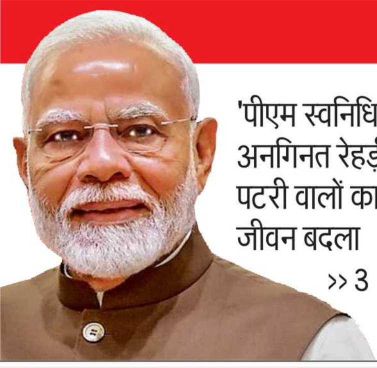

'पीएम स्वनिधि' से अनगिनत रेहड़ी-पटरी वालों का जीवन बदला
>> 3

वर्ष 9 अंक 354

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, मंगलवार, 2 जून, 2026

दैनिक जागरण

www.jagran.com
पृष्ठ 14

जागरण विशेष

नैनोप्लास्टिक : अवसाद की ओर धकेल रहे सूक्ष्म कण

लखनऊ : केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान के अध्ययन में सामने आई जानकारी। हल्दी, तुलसी व ताजे फल दे सकते हैं सुरक्षा। • पेज-7

संपादकीय

रचनात्मक बहस के बजाय सतही नारेबाजी : लोकतंत्र में तीखी आलोचना सत्ता को निरंकुश होने से रोकती है, पर जब आलोचना का स्थान व्यक्तिगत घृणा ले ले, तो संवाद का रास्ता बंद हो जाता है। **रामानंद शर्मा** की टिप्पणी।

अविश्वास से घिरती जा रहीं परीक्षाएं : ऐसी शिक्षा-पद्धति की तलाश करनी होगी, जो केवल ज्ञान और कौशल ही नहीं, बल्कि नैतिकता का भी निर्माण करें। **जगमोहन सिंह राजपूत** का सुझाव। • पेज-8

विमर्श

बदलती व्यवस्था में भारत के लिए अवसर : पिछले तीन दशकों तक परस्पर निर्भरता और नवीन आर्थिकी का मूल सिद्धांत यह था कि उत्पादन वहीं होगा, जहां लागत सबसे कम होगी और मांग ज्यादा हो। **प्रो. एम एल मीणा** का आलेख।

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण : पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की प्राचीन परंपरा रही है। **आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी** का विश्लेषण। • पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

अंतस और अध्यात्म का

सृजनात्मकता का रहस्य विश्राम और जागरूकता

सूर्य से सीखें अनासक्त रहना
• पेज-13

सीमा पर निगरानी से हमले तक, सेना की नई ताकत बनेगा दिव्यास्त्र एमके-1

- स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का जोधपुर में युद्ध स्तरीय परिस्थिति में कई सटीक परीक्षण किए गए
- अब तक निगरानी और हमले के लिए अलग-अलग प्रणालियों पर थी निर्भरता, नया सिस्टम दोनों काम साथ करेगा
- एआइ और सेंसर से लैस ड्रोन मोबाइल लांचर से तुरंत छोड़ा जा सकता है, दिन-रात दे सकता है रियल-टाइम जानकारी

400 किमी प्रति घंटे की गति से 500 किमी तक पांच घंटे तक उड़ान भर सकता है ड्रोन

15 किलो तक का बम भी ले जा सकता है, सटीक निशाना लगाने तक लंबे समय तक मंडरा सकता है

'दिव्यास्त्र एमके-1' लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन। इंटरनेट मीडिया

एएनआइ, नई दिल्ली : भारतीय सेना सीमा पर निगरानी और दुश्मन पर सटीक कार्रवाई की अपनी क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरित के 'दिव्यास्त्र एमके-1' लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन के सफल परीक्षण के रूप में सामने आया है। अब तक सेना को कई परिस्थितियों में खुफिया जानकारी जुटाने, घुसपैठ पर नजर रखने और लक्ष्य पर हमला करने के लिए अलग-अलग संसाधनों का सहारा लेना पड़ता था। दिव्यास्त्र एमके-1 इन सभी क्षमताओं को एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

आपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका-ईरान युद्ध में लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन की सफलता को देखते हुए भारतीय सेना का ज्यादा जोर इस तरह की रक्षा प्रणाली पर है। इसके अलावा सेना विदेशी तकनीक पर आधारित महंगे ड्रोन की बजाय किफायती स्वदेशी ड्रोन को भी बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में जोधपुर में इस ड्रोन ने युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और आधुनिक सेंसरों से लैस यह प्रणाली दिन और रात दोनों समय रियल-टाइम में जानकारी कमांड सेंटर तक पहुंचा सकती है। इससे सीमा पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घुसपैठ की कोशिश का पता पहले से कहीं अधिक तेजी और सटीकता से लगाया जा सकेगा। दिव्यास्त्र एमके-1 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल निगरानी तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर यह अपने साथ 15 किलोग्राम तक का वारहेड ले जाकर लक्ष्य पर सटीक हमला भी कर सकता है। लक्ष्य की पहचान होने तक यह लंबे समय तक हवा में मंडरा सकता है और सही अवसर मिलने पर कार्रवाई कर सकता है। इसी वजह से इसे 'लोइटरिंग म्यूनिशन' श्रेणी का ड्रोन भी कहा जाता है। करीब 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला यह ड्रोन लगातार पांच घंटे तक हवा में रह सकता है और लगभग 500 किलोमीटर तक के क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। एलओसी, एलएसी, रेगिस्तानी इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और घने जंगलों जैसे कठिन भूभागों में भी इसका उपयोग प्रभावी माना जा रहा है।

बहुत कम समय में उड़ान भरता है दिव्यास्त्र एमके-1 ड्रोन पेज>>6

भाजपा में राष्ट्रीय संगठक का नया पद, नागेंद्र नाथ को जिम्मेदारी

नई दिल्ली : पहली बार भाजपा में भी राष्ट्रीय संगठक का पद सृजित किया गया है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के बीच तालमेल और संवाद का यह दायित्व पार्टी ने संगठन के अनुभवी और संघ की पृष्ठभूमि वाले नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को सौंपा है। (पेज-4)

बिहार के शुभम कुमार जेईई एडवांस्ड में अव्वल

नई दिल्ली : जेईई एडवांस्ड-2026 की परीक्षा में आइआइटी दिल्ली जोन के शुभम टापर बने। वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। परीक्षा में कुल 1,87,389 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। जिनमें से 1,79,694 उम्मीदवारों ने 17 मई 2026 को आयोजित परीक्षा के पेपर-1 और पेपर-2 दोनों में भाग लिया। इस परीक्षा में कुल 56,880 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। (पेज-5)

सख्ती ▸ नीट-यूजी पेपर लीक मामले पर संसदीय समिति ने एनटीए पर उठाए सवाल, पूछा

परीक्षा सीबीटी मोड में कराने के दिए थे सुझाव तो फिर क्यों नहीं हुआ अमल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- एनटीए अधिकारियों ने कहा- अगले साल से यह परीक्षा सीबीटी मोड में कराने की तैयारी
- जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक पेपर लीक मानना ठीक नहीं है
- कई सवालों पर साधी चुप्पी, कहा- अभी सिर्फ 21 जून की दोबारा परीक्षा पर फोकस

दिग्विजय सिंह। फाइल

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में संसदीय समिति ने सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से तीखे सवाल किए। समिति ने पूछा कि जब 2024 में नीट-यूजी का पेपर लीक होने के बाद हाई पावर कमेटी ने परीक्षा को सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) मोड में कराने की सिफारिश की थी, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया गया। एनटीए के अधिकारियों ने इस पर कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया लेकिन बताया कि वे 2027 से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में कराने की तैयारी कर रहे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुआई वाली शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति के सदस्यों ने इस दौरान पेपर लीक को लेकर भी एनटीए से सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार, एनटीए ने फिर से दोहराया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ है। हालांकि, समिति के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और पूछा कि जिसे कंप्रोमाइज कहा जा रहा है, उसमें भी पेपर लीक हुआ है। एनटीए ने कहा कि उनका मूल पेपर बाहर नहीं आया, केवल परीक्षा के कुछ प्रश्न लीक हुए हैं। सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही है, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक पेपर लीक मानना ठीक नहीं है।

सूत्रों के अनुसार, इस दौरान सदस्यों के कई सवालों पर एनटीए की चुप्पी भी देखने को मिली। हालांकि, इस सवाल-जवाब के बीच एनटीए ने बताया कि उनका पूरा फोकस 21 जून को नीट-यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को सुरक्षित कराने पर है जो पेन-पेपर मोड में ही कराई जाएगी।

गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने यह बैठक नीट-यूजी परीक्षा को सीबीटी मोड में कराने को लेकर बुलाई थी। समिति ने शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से भी इस मुद्दे पर चर्चा की और इसके फायदे और नुकसान को समझा। समिति ने इससे पहले 21 मई को भी नीट-यूजी पेपर लीक के मुद्दे पर एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया था। (संबंधित खबरें, पेज-5 पर)

बैठक बुलाने पर सत्ता पक्ष व विपक्षी सांसदों के बीच नोकझोंक

संसदीय समिति की बैठक बुलाने पर सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच नोकझोंक की भी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, 15 दिनों के भीतर समिति की बैठक बुलाए जाने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि छात्रों और अभिभावकों से जुड़ा यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है, ऐसे में बार-बार बैठक बुलाकर इस पर राजनीति न की जाए। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोई राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि वे चाहते हैं कि यह व्यवस्था दुरुस्त हो।

समिति आज मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ियों पर सीबीएसई से करेगी सवाल

शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने मंगलवार को मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को भी तलब किया है। इस दौरान मूल्यांकन के लिए अपनाई गई आन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को लेकर भी सीबीएसई के अध्यक्ष से सवाल किए जाएंगे। साथ ही छात्रों के हितों में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। समिति नौवीं और दसवीं कक्षा में लागू किए गए त्रिभाषा फार्मूले को लेकर शिक्षा मंत्रालय से भी सवाल करेगी।

दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी नहीं होगी बर्दाश्त : योगी

जागरण संवाददाता, बिजनौर

- सीएम ने कहा, मौलाना-मौलवी शोहदों को समझाएं नहीं तो ऐसी दुर्गति होगी कि पीढ़ियां याद करेंगी
- गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर योगी बोले, गाय पशु नहीं, हमारी माता है

योगी आदित्यनाथ। फाइल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गाजियाबाद में बकरीद के दिन किशोर सूर्य प्रताप चौहान की हत्या की घटना का उल्लेख करते हुए चेताया कि यदि कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं रहा है तो वह गलती कर रहा है। मौलाना और मौलवी अपने शोहदों को समझाएं नहीं तो ऐसी दुर्गति होगी कि पीढ़ियां याद करेंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन के समय पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 1645 परिवारों को भूमिधरी अधिकार प्रमाणपत्र वितरित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करे हुए कहा कि बकरीद पर गाय के फोटो वाले मैसेज प्रसारित किए गए। मौलाना और मौलवी गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं। गौ तो हमारी माता है। जन्म जन्मांतर का नाता है और यह स्वघोषित है। गाय पशु नहीं है। पशु तो ऐसे लोगों की बुद्धि है, जो ऐसी मांग कर रहे हैं। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उप्र में गोहत्या का मतलब जानते हो क्या होगा? उन्होंने कहा कि मौलाना और मौलवी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार की निंदा तक नहीं करते हैं। जुमे की नमाज तक में घोषणा नहीं करते हैं कि पाकिस्तान गंदा काम कर रहा है। पिछले दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, लेकिन किसी मौलाना के मुंह से कुछ नहीं निकला।

योगी ने कहा कि करुणा और मानवता मनुष्यों के लिए होती है। सामने खरदूषण है है तो शस्त्र उठाना होगा। जब नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया तो उसमें कहीं नहीं लिखा था कि इससे मुसलमानों की संपत्ति ली जाएगी। फिर भी विरोध किया। कांग्रेस और सपा ने भी कभी विस्थापित होकर आए हिंदुओं की बात नहीं की। दशकों तक विस्थापितों की मांग को किनारे किए रखा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भारत नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे।

पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया के घर पर पुलिस का छापा, नहीं आए हाथ

अमृतसर : पंजाब पुलिस ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के घर पर छापा मारा। यह छापेमारी मजीठा थाने से आरोपित को छुड़ाने के प्रयास में दर्ज मामले को लेकर की गई। हालांकि, मजीठिया घर पर नहीं मिले। पुलिस के अनुसार मजीठिया लोगों की उस गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा थे, जिसने मजीठा पुलिस थाने में हिरासत में लिए गए जोबनप्रीत सिंह को छुड़ाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले में मजीठिया व उनके 60 से ज्यादा समर्थकों पर एफआइआर दर्ज की है। उधर, सरकार ने सोमवार देर शाम अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी सोहेल मीर कासिम का तबादला कर दिया। (पेज-6)

असद के पिता के मकान पर बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम

गाजियाबाद : 17 वर्षीय सूर्य प्रताप चौहान उर्फ सूर्या की बकरीद के दिन घर बुलाकर हत्या करने वाले असद के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उसके पिता के मकान पर बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि 50 गज में असद के पिता का अवैध मकान सरकारी भूमि पर बना है। (पेज-2)

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'भूल जाने के अधिकार' को दी मान्यता

नई दिल्ली : इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध न्यायिक रिकार्ड से व्यक्तिगत जानकारी को छिपाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 'भूल जाने के अधिकार' को मान्यता दी है। हाई कोर्ट ने माना कि भूल जाने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद -21 के तहत सूचनात्मक निजता का एक संवैधानिक रूप से संरक्षित पहलू है। (पेज-2)

सीएम शुभेंदु के नाम लेते ही टीएमसी ने निकाले दोनों विधायक

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में समर्थन दिए जाने के पत्र से जुड़ा है मामला
- विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी ने फर्जी हस्ताक्षर को लेकर दर्ज कराई थीं शिकायतें

निष्कासित तृणमूल विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी। इंटरनेट मीडिया

तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अपने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी को सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। इस निष्कासन आदेश से करीब 15 मिनट पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान खुलासा किया था कि राज्य विधानसभा में फर्जी हस्ताक्षर मामले के संबंध में शिकायतें इन दोनों विधायकों ने दर्ज कराई थी। यह मामला तृणमूल कांग्रेस द्वारा शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में समर्थन दिए जाने के पत्र से जुड़ा है।

आरोप है कि विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर तापस राय के सामने जिन विधायकों ने हस्ताक्षर किए थे, उनका मिलान परिषदीय दल के पत्र में मौजूद हस्ताक्षरों से नहीं हो रहा है। विधानसभा में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विरोधी दल नेता घोषित करने के लिए टीएमसी की ओर से यह पत्र जमा कराया गया था। इस मामले में विधानसभा की ओर से हेयर स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। इस शिकायत के आधार पर सीआइडी मामले की जांच कर रही है।

टीएमसी उपाध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दोनों विधायकों को ईमेल और वाट्सएप के जरिये निष्कासन का पत्र भेजा, जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ बोस को भी दे दी गई है। अब ये दोनों विधायक सदन में दलविहीन सदस्य के रूप में बैठेंगे और राज्यसभा चुनाव जैसे मामलों में इन पर पार्टी का व्हिप लागू नहीं होगा। वहीं निष्कासित दोनों विधायकों ने कहा कि पार्टी अनैतिक काम करने वालों का समर्थन कर रही है और नैतिकता की बात करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। वहीं निष्कासित किए जाने के कुछ घंटे बाद ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे नेताओं के चले जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि टीएमसी उनके बिना और मजबूत होगी।

मामले की जांच के लिए में सीआइडी ने किया एसआइटी का गठन

हस्ताक्षर मामले की जांच के लिए में सीआइडी ने पांच सदस्यीय एसआइटी का गठन किया है। विशेष अधीक्षक के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय टीम अब दस्तावेजों, हस्ताक्षरों की जांच के साथ संबंधित विधायकों से पूछताछ करेगी। वहीं इस मामले में सीआइडी ने सोमवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को तलब किया था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वह सीआइडी के समक्ष पेश नहीं हुए। इसके बाद सीआइडी फिर उनके कालीघाट आवास पर पहुंची और उन्हें नोटिस दिया। इसके तहत आठ जून को 12 बजे उन्हें फिर तलब किया गया है।

हिमाचल में एंट्री टैक्स के विरोध में 56 एंट्री प्वाइंट पर चक्का जाम

रूपनगर : हिमाचल प्रदेश द्वारा अन्य राज्यों के वाहनों पर लगाए गए एंट्री टैक्स के खिलाफ सोमवार को पंजाब के 56 एंट्री प्वाइंट पर चक्का जाम किया गया। किसान संगठनों, ट्रांसपोर्टरों, टैक्सी यूनियनों और व्यापारियों के संयुक्त मोर्चे ने सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक प्रदर्शन किया, जिस कारण सीमा पर वाहनों की कतारें लग गईं। (पेज-6)

अगले दो-तीन दिनों में केरलम में दस्तक दे सकता है मानसून

नई दिल्ली : मौसम विभाग ने सोमवार को कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून अगले दो से तीन दिनों में केरलम में दस्तक दे सकता है। आइएमडी ने इस हफ्ते राज्य के सात जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आमतौर पर केरलम में मानसून एक जून के आसपास पहुंचता रहा है। आइएमडी ने पहले 26 मई को राज्य में मानसून पहुंचने की बात की थी। (पेज-6)

परिवर्तन

शुभेंदु कैबिनेट की 'महा-इंजीनियरिंग' में झलका नया जनादेश, 35 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ 'सोनार बांग्ला' का रोडमैप तैयार, 35 मंत्रियों ने ली शपथ, जिनमें 13 कैबिनेट, 3 स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री, कुल संख्या हुई 41

घर-घर बर्तन मांजती थीं कलिता, अब बंगाल में बनी मंत्री

जयकृष्ण वाजपेयी • जागरण

कोलकाता में सोमवार को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आभार व्यक्त करतीं कलिता माझी, पीछे मंच पर बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। आइएएनएस

कोलकाता : बंगाल के राजनीतिक इतिहास में सोमवार को एक ऐसा भावुक और युगांतकारी अध्याय जुड़ गया, जिसने सत्ता के पारंपरिक रसूख और अभिजात्य दावों को दरकिनार कर दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जब पूर्व बर्द्धमान जिले के आउसग्राम विधानसभा क्षेत्र की विधायक कलिता माझी ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली, तो लोकभवन न केवल तालियों से गूंज उठा, बल्कि वहां मौजूद हर शख्स का चेहरा गर्व से दीप्त था।

कभी दूसरों के घरों में चौका-बर्तन कर महज 2,500 से 4,000 रुपये महीना कमाने वाली कलिता माझी ने बूथ कार्यकर्ता से मंत्री पद तक पहुंच भारतीय लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत और जीवंत मिसाल कायम की। 2021 की हार के बावजूद पांच साल तक जमीन पर डटी रहने वाली कलिता ने 2026 में तृणमूल कांग्रेस के अभेद्य किले को ध्वस्त कर जीत दर्ज की है।

सोमवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में राज्यपाल आरएन रवि ने 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद मंत्रिपरिषद का कुल आकार अब 41 हो गया है। इस कैबिनेट में अनुभव, सांगठनिक पैठ और युवा ऊर्जा का एक ऐसा अनूठा सम्मिश्रण तैयार किया गया है, जो सीधे राज्य सचिवालय 'नवान्न' से तृणमूल के 15 साल पुराने शासन के अवशेषों को साफ कर 'सुशासन' की नई नींव रखेगा।

युवा जोश, बौद्धिक कौशल और अनुभव का संगम : प्रशासनिक दक्षता को धार देने के लिए मंत्रियों की उम्र और शैक्षणिक योग्यता का भी एक बेहतरीन संतुलन बिठाया गया है। जहां एक तरफ डा इंद्रनील खां और स्वपन दासगुप्ता जैसे उच्च शिक्षित व बौद्धिक चेहरे नीतिगत फैसलों को वैश्विक दिशा देंगे, वहीं दूसरी तरफ दूध कुमार मंडल और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा जैसे जमीन से जुड़े ऊर्जावान चेहरे हैं।

उत्तर से दक्षिण तक क्षेत्रीय व जातीय संतुलन की अचूक बिसात पेज>>4

दुष्कर्म मामले में आठ दिन में ट्रायल पूरा, दोषी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पुलिस ने जांच कर 34 दिन में दाखिल कर दी चार्जशीट

प्रतीकात्मक

राजधानी की तीस हजारी कोर्ट ने पोक्सो के एक मामले में आठ दिनों में ट्रायल पूरा कर दोषी को उम्रकैद (मृत्यु होने तक कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने महज 34 दिन के भीतर चार्जशीट भी दाखिल कर दी। यानी कुल 42 दिनों में दुष्कर्मी को सजा सुनाई गई है। आठ दिन में ट्रायल पूरा किए जाने का दिल्ली में यह पहला मामला है। इस मामले में दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए पीड़िता के लिए 16.5 लाख रुपये के मुआवजे को भी मंजूरी दी गई है।

बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक निहाल विहार थाना क्षेत्र में 17 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई गई थी। नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके घर के सामने रहने वाले रामशंकर ने जुलाई 2025 में उसे बहाने से घर बुलाया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। डरा धमकाकर आरोपित महीनों तक दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के गर्भवती होने पर स्वजन को पता चला। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर एसीपी राजबीर लांबा की निगरानी और एसएचओ शीश पाल, एसआई मनीषा की टीम ने जांच शुरू की गई।

3 वर्षों में दिल्ली में जून महीने की शुरुआत सबसे ठंडी रही। सोमवार को माह के पहले ही दिन अधिकतम व न्यूनतम दोनों तापमान वर्ष 2023 के बाद सबसे कम रहे। हालांकि, यलो अलर्ट और बादलों की आवाजाही के बीच दिन भर वर्षा का इंतजार भी होता रहा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार, 02 जून, 2026

आज का मौसम

बादल छाए रहेंगे। बिजली चमकने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलेगी। हल्की वर्षा होने के आसार।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
2 जून	37.0	26.0
3 जून	38.0	27.0
नोएडा		
2 जून	37.0	26.0
3 जून	38.0	24.0
गुरुग्राम		
2 जून	37.0	26.0
3 जून	38.0	27.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

फिर महापौर के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली

नई दिल्ली : दनिगम मुख्यालय में महापौर प्रवेश वाही के कार्यालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। महापौर और निगमायुक्त के ई-मेल पर यह धमकी भरा मेल आया। ई-मेल में खालिस्तान नेशनल आर्मी लिखा गया है। खालिस्तानी समर्थक होने का दावा किया गया है। इसमें दिल्ली के साथ हरियाणा पंजाब को खालिस्तान बनाने की बात भी कही है। (राब्यू)

जनवरी से मई तक दिल्ली में रही सबसे साफ हवा : सीएक्यूएम

नई दिल्ली : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा सोमवार को जारी किए आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 प्रभावित वर्ष 2020 को छोड़कर, दिल्ली ने आठ वर्षों में जनवरी से मई की अवधि में अपनी सबसे साफ हवा दर्ज की है। इस साल इस अवधि में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) सुधरकर 211 रहा, जबकि 2018 में यह 243 व पिछले साल 2025 में 214 दर्ज किया गया था। (राब्यू)

कोर्ट ने गैंग्सटर रवि काना की अग्रिम जमानत रद की

ग्रेटर नोएडा : स्क्रैप कारोबारी और गैंग्सटर रवि काना को जिला एवं सत्र न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने 25 मई को उसकी अग्रिम जमानत रद कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपित ने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया और बार-बार मौका देने के बाद भी जांच में सहयोग नहीं किया। गैंग्सटर रवि काना पर नोएडा की सेक्टर-63 कोतवाली में 14 जनवरी को शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। उस पर धमकी व जबरन वसूली का आरोप है। (जासं)

48 घंटे बाद भी जारी है राहत अभियान, मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका

सैदुलाजाब हादसा ▶ घटनास्थल से मलबा हटाने में अभी 24 घंटे से अधिक का लग सकता है समय

पड़ोस के कोचिंग भवन के भी गिरने की आशंका, जैक लगाकर दिया गया सहारा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सैदुलाजाब गांव में शनिवार शाम पांच मंजिला इमारत गिरने के 48 घंटे बाद भी राहत व बचाव अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मलबा पूरी तरह हटाने में अभी 24 घंटे और लग सकते हैं। हादसे के बाद से एनडीआरएफ, दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर मौके पर काम कर रही हैं। मलबे को हटाने के लिए एक हाइड्रा क्रेन और दो बड़ी क्रेनें लगाई गई हैं। अब तक करीब 55 ट्रक मलबा हटाया जा चुका है।

एनडीआरएफ के अधिकारियों के अनुसार हादसे के समय इमारत के पास बनी कैंटीन में लोगों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी वजह से शुरुआती चरण में बचाव दलों की प्राथमिकता कैंटीन वाले हिस्से से जल्द से जल्द मलबा हटाने की रही। कैंटीन वाले हिस्से का मलबा पूरी तरह साफ कर दिया गया है और रविवार शाम के बाद से वहां से कोई व्यक्ति नहीं मिला है। अधिकारियों के मुताबिक राहत कार्य में कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। घटनास्थल पर काफी कम जगह है और हादसे के बाद बगल की कोचिंग संस्थान की इमारत झुक गई है। इसके गिरने की आशंका को देखते हुए जैक लगाकर सहारा दिया गया है। साथ ही अतिरिक्त गार्डर भी मंगवाए गए हैं, ताकि बचाव अभियान के दौरान आसपास की संरचना सुरक्षित रहे। जगह कम होने के चलते एक साथ कई क्रेन काम नहीं कर पा रही है। करीब 250 वर्ग गज क्षेत्र में मलबा फैला हुआ है। जैसे-जैसे मलबा हटाया जा रहा है और जगह बन रही है।

बचाव व राहत कार्य के दौरान घटनास्थल पर गैस कटर से काटे जा रहे लोहे के सरिये। जागरण

कई लोग अब भी लापता, मोबाइल की मिल रही लोकेशन : हादसे में जमींदोज हुई वेस्ट एंड रोड की पांच मंजिला इमारत में कई कार्यालय थे। शनिवार और रविवार को अधिकांश कार्यालय बंद रहते हैं, पर कुछ में कर्मचारियों और अन्य लोगों का आना-जाना बना रहता है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि हादसे के समय भी इमारत में कई लोग मौजूद थे। इससे आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। फारेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. जसवंत सिंह यादव ने बताया कि कई लोग लापता हैं, जिनके मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल की ही दिखा रहा है। वह मलबे में दबे हो सकते हैं।

हादसे के बाद बदल गई इलाके की तस्वीर : पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी, एसएससी, एफएमजीई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सैदुलाजाब गांव एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। साकेत मेट्रो स्टेशन के नजदीक होने और अपेक्षाकृत सस्ते किराये पर कमरे, पीजी और फ्लैट उपलब्ध होने से बड़ी संख्या में छात्र यहां रहते हैं।

इमारत का स्वामी गिरफ्तार, बिल्डर-ठेकेदार अब भी फरार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- एक शिकायतकर्ता ने नियमों की अनदेखी कर बन रहे भवनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी
- शिकायत के बाद पुलिस ने नगर निगम को पत्र भेजकर उचित कदम उठाने का अनुरोध किया था

पांच मंजिला इमारत ढहने की जांच में जुटी पुलिस ने घटना के 48 घंटे बाद इसके मालिक 71 वर्षीय करमवीर जेलदार को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि निर्माण से जुड़े बिल्डर मनीष खत्री और ठेकेदार सिराज अब भी फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम बंगाल भेजी गई है, जबकि दो टीमें उत्तराखंड और हरियाणा में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। हादसे के बाद मालिक, बिल्डर और ठेकेदार फरार हो गए थे। करमवीर जेलदार को पुलिस ने उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया है, जहां वह हादसे के बाद से छिपा हुआ था। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि करमवीर हादसे के बाद मौके पर गया था और फिर फरार हो गया।

जांच में यह भी सामने आया है कि पुलिस ने तीन महीने पहले एमसीडी दक्षिणी जोन को एक पत्र लिखकर क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग की थी। सूत्रों का कहना है कि जिस इमारत में हादसा हुआ, उसका उल्लेख भी उस पत्र में था। पुलिस ने नगर निगम को अवैध निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आगाह किया था। मामले में एक शिकायतकर्ता भी सामने आया है, जिसने पहले दिल्ली पुलिस और नगर निगम दोनों को इलाके में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण की लिखित शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर बनाए जा रहे भवनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

शिकायत के बाद पुलिस ने नगर निगम को पत्र भेजकर उचित कदम उठाने का अनुरोध किया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कई पहलुओं से की जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि अवैध निर्माण के संबंध में पहले मिली शिकायतों और चेतावनी के बावजूद आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अधिकारियों के अनुसार, फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद हादसे की जिम्मेदारी और संभावित लापरवाही की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी। जांच अभी जारी है। वहीं दूसरी ओर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश के बाद सोमवार को दक्षिणी जिले के तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंचे। लगभग आधे घंटे तक वहां रहे और जांच-पड़ताल की।

'धुरंधर' से भड़का दाऊद इब्राहिम, आइएसआइ के साथ मिलकर रची देश में आतंकी साजिश

राकेश कुमार सिंह • जागरण

- उसके गुर्गे झिंगाड़ा को सौंपी जिहादी ब्रिगेड तैयार करने की जिम्मेदारी
- आतंकियों ने तबाही मचाने के लिए मुन्ना झिंगाड़ा से मांगे थे 20 लाख रुपये

नई दिल्ली : धुरंधर फिल्म में पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम को जिस तरह से बेनकाब किया गया है, उससे पाकिस्तान के साथ ही अंडरवर्ल्ड डान दाऊद इब्राहिम भी तिलमिला उठा। इसके बाद अंडरवर्ल्ड डान दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने दिल्ली के साथ ही मुंबई पर आतंकी हमले की साजिश रची थी। इसकी जिम्मेदारी दाऊद के खास गुर्गे मुन्ना झिंगाड़ा को सौंपी गई थी।

इसके बाद मुन्ना पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के अलावा गैंग्सटर शहजाद भट्टी की मदद से नई जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। आतंकियों ने इसके लिए मुन्ना से 20 लाख रुपये मांगे थे। इस पर्दाफाश हाल ही में दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और पंजाब से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ, पाकिस्तानी गैंग्सटर शहजाद भट्टी व अंडरवर्ल्ड डान दाऊद इब्राहिम से जुड़े माड्यूल के आठ आतंकियों से पूछताछ में हुआ है। इसके बाद आइबी के इनपुट पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि कराची में दाऊद के ठिकाने व्हाइट हाउस से महज चार किमी की दूरी पर एक फाइव स्टार होटल के पास मुन्ना ने आइएसआइ के संरक्षण में सेफ हाउस बना रखा है, जहां से वह लगातार इन आतंकियों से वीडियो काल और सिग्नल एप के जरिये बात कर भारत में अंडरवर्ल्ड की नई जेहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। हाल ही में फोटो और टोकन मनी भी पकड़े गए आतंकियों को भेजी थी। आतंकियों की नशा करने की लत को पूरा करने को ड्रोन से हेरोइन, हथियार और हैंड ग्रेनेड गुरदासपुर में गिराए गए थे। गिरफ्तार आतंकी विजय उर्फ शूटर, नितीश पासवान, तौकीर रिजवान, साजिद महबूब शेख, हरविंदर, गगनदीप सिंह, मंजीत सिंह व आंग कामी लामा से स्पेशल सेल समेत तमाम सएजेंसियां पूछताछ कर रही है। इनके मोबाइल की जांच करने पर कुछ से मुन्ना से बातचीत के चैट मिले हैं

मुन्ना झिंगाड़ा। इंटरनेट मीडिया

कौन है मुन्ना झिंगाड़ा : सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की बढ़ती उम्र के मद्देनजर अंडरवर्ल्ड ने मुन्ना झिंगाड़ा पर दांव खेला है। मुंबई के सबसे खतरनाक शूटरों में शुमार मुन्ना झिंगाड़ा उर्फ सैयद मुदस्सर हुसैन छोटा राजन पर बैंकाक में हुए हमले के बाद सुर्खियों में रहा था।

हत्यारोपित असद के पिता के मकान पर बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- गाजियाबाद में सरकारी भूमि पर बना है असद के पिता का अवैध मकान

17 वर्षीय सूर्य प्रताप चौहान उर्फ सूर्या की बकरीद के दिन घर बुलाकर हत्या करने वाले असद के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद भी प्रशासन का रुख सख्त बना हुआ है। उसके पिता के मकान पर बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि 50 गज में असद के पिता का अवैध मकान सरकारी भूमि पर बना है। सोमवार को प्रशासन ने आरोपित के मकान के बाहर ढोल बजवाकर मुनादी कराई और 15 दिन में मकान खाली करने का नोटिस दिया है।

मूलरूप से बुलंदशहर निवासी असद का पिता नवाब बढ़ई का काम करता है। वह परिवार के साथ इस मकान में पिछले 18 साल से रह रहा था। छह माह पहले नवाब ने प्रापर्टी डीलर के माध्यम से 52 लाख रुपये में मकान बेच दिया है, लेकिन अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तहसीलदार रितेश सिंह ने बताया कि असद के मकान ग्राम पंचायत की भूमि पर बना है। मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 15 दिन में नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर अवैध कब्जा हटाया जाएगा। डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि असद मुठभेड़ में मारा गया और तीन आरोपितों को जेल भेज दिया गया। आरोपित शारिक की तलाश की जा रही है। उधर, डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ ने सूर्या के परिवार को प्रदेश सरकार की तरफ से पांच लाख की सहायता राशि का चेक भी दिया है। पता चला है कि नवाब दूसरी पत्नी, असद और दूसरे बेटे-बहू के साथ मकान में रहता था। व्यवहार ठीक नहीं होने से नवाब ने दूसरे बेटे को बेदखल कर दिया था।

खोड़ा में असद के घर पर नोटिस चस्पा करती प्रशासन की टीम।

सांप के बच्चे को दूध पिलाओगे तो काटेगा ही : सोमवार को सरधना के पूर्व विधायक भाजपा नेता संगीत सोम भी स्वजन से मिलने पहुंचे। उन्होंने स्वजन को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद भी दी। उन्होंने कहा कि सांप के बच्चे को दूध पिलाओगे तो काटेगा ही। आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलवाने और सख्त कार्रवाई की बात कही। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डाली शर्मा ने भी हर संभव मदद का वादा किया। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी सूर्या की मां सरोज ठाकुर से मुलाकात की।

डीयू की आपत्ति के बावजूद सेंट स्टीफेंस की प्राचार्या बनी प्रो. एलियास

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- 145 साल के इतिहास में पहली बार महिला प्राचार्य ने संभाला पदभार

डीयू और सेंट स्टीफेंस कालेज के बीच जारी प्रशासनिक विवाद के बीच नवनियुक्त प्रिंसिपल प्रो. सुसान एलियास ने 145 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक महिला प्राचार्य बनी हैं। प्रो. एलियास ने डीयू की आपत्तियों के बावजूद कालेज की 14वीं प्राचार्य के रूप में पदभार संभाल लिया है।

सेंट स्टीफेंस कालेज ने 12 मई को एलियास की नियुक्ति की घोषणा की थी। इसके बाद डीयू ने कालेज को पत्र लिखकर नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। विश्वविद्यालय का कहना था कि नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों का पालन नहीं किया गया है। डीयू ने इस मामले में यूजीसी से भी हस्तक्षेप की मांग की है। डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय पहले ही यूजीसी को पत्र भेज चुका है और अब आगे के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। वहीं कालेज की वेबसाइट पर प्राचार्य का पद अभी भी अपडेट नहीं किया गया है। पूर्व प्राचार्य जान वर्गीज का नाम अंग्रेजी विभाग के संकाय सदस्य के रूप में दर्ज है और उनकी प्रोफाइल में उन्हें अब भी प्राचार्य बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, जान वर्गीज ने रविवार को कालेज समुदाय को विदाई संदेश भेजा था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह कालेज में शिक्षक के रूप में बने रहेंगे या नहीं।

प्रो. सुसान एलियास।

फसल नुकसान पर मिलेगा प्रति हेक्टेयर 75 हजार रुपये क्षतिपूर्ति : रेखा गुप्ता

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : आपदा से फसल को नुकसान होने पर अब दिल्ली के किसानों को पहले से अधिक क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष मानसून में अधिक वर्षा और जलभराव से जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, उन्हें 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति देने की स्वीकृति दी है। इससे दिल्ली के लगभग 10 हजार किसानों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगस्त-सितंबर 2025 के दौरान भारी वर्षा और खेतों में जलभराव के कारण 10,977.44 एकड़ (लगभग 4,442.41 हेक्टेयर) कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ था। वर्ष 2015 में तत्कालीन सरकार द्वारा वर्षा से फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को 49,421 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई थी। दस वर्षों में कृषि लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी है। क्षतिपूर्ति राशि केवल भूमि के अभिलेखित स्वामियों को ही दी जाएगी।

चिराग के ही खाते से रुपये निकालकर खरीदी पिस्टल, फिर कर दी हत्या

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- पुलिस ने यश को हथियार दिलाने में मदद करने वाले अन्य पैरा एथलीट गगन त्यागी को धरा

पैरा एथलीट चिराग त्यागी हत्याकांड में आरोपित यश खटीक ने चिराग के ही बैंक खाते से पैसे निकालकर पिस्टल खरीदी और उसी हथियार से उसे दो गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। यश को हथियार दिलाने में मदद करने वाले अन्य पैरा एथलीट गगन त्यागी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, इस मामले में मुरादनगर के भिकनपुर निवासी अभय उर्फ अभिनव ने पिस्टल मुहैया कराई थी, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस पिस्टल की बरामदगी के प्रयास में भी लगी हुई है।

सोमवार को डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि यश खटीक और चिराग त्यागी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में साथ प्रैक्टिस करते थे। चिराग का चयन एशियन गेम्स के लिए हो गया था, जबकि यश का चयन नहीं हो सका। वह इसलिए क्योंकि उसकी आंखों की मेडिकल रिपोर्ट जर्मनी भेजी जानी थी। इससे पहले ही दो दिसंबर 2025 को पैरालिंपिक कमेटी आफ इंडिया ने दस्तावेजों में खामियों के कारण यश को डिसक्वालीफाइ कर दिया था। यश की रिपोर्ट और फार्म चिराग ने ही भरा था। ऐसे में यश को संदेह था कि चिराग ने जानबूझकर उसके दस्तावेजों में त्रुटियां छोड़ी थीं, जिसके कारण उसे प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा।

पुलिस लाइन में चिराग त्यागी हत्याकांड के आरोपितों की जानकारी देते डीसीपी सिटी धवल जायसवाल। जागरण

डीसीपी सिटी ने बताया कि चिराग लगातार मेडल जीतते जा रहे, जिससे यश को हीन भावना होने लगी। उसने अपने साथी, मुरादनगर के लक्ष्मी एन्क्लेव निवासी गगन त्यागी के साथ मिलकर चिराग की हत्या की योजना बनाई। गगन ने कहा कि उसका साथी प्रापर्टी डीलर अभय पिस्टल लाकर देगा। इसके बाद अभय ने पिस्टल दुहाई में लाकर दी। हैरानी वाली बात ये ही कि पिस्तौल खरीदने के लिए यश ने चिराग के बैंक खाते से 62 हजार रुपये निकाले थे। बंगलुरू से शुक्रवार शाम को इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतकर चिराग घर लौट गए थे। इसके बाद शनिवार सुबह चिराग को यश अपने साथ साईं उपवन लेकर गया। वहां यश ने पीछे से चिराग के सिर में पहली गोली मारी। गोली लगने के बाद चिराग कुछ दूर चला, तो दूसरी गोली पीठ में मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

बीसीडी चुनावों में गड़बड़ियों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट सुनाएगा निर्णय

जासं, नई दिल्ली : बार काउंसिल आफ दिल्ली (बीसीडी) के चुनावों में गड़बड़ियों के आरोपों से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मामले पर निर्णय सुनाया जाएगा, हालांकि इसकी तारीख नहीं दी गई है। कोर्ट ने वोटों की गिनती की प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग की भी जांच की।

गड़बड़ी के संबंध में हुई प्राथमिकी के अनुसार 15 अप्रैल को 80वें उम्मीदवार के मतपत्र संख्या 17 की छंटनी के दौरान यह पाया गया कि कई मतपत्रों में दूसरी वरीयता में हेरफेर किया गया है और मतपत्र संख्या 132 के पक्ष में नई दूसरी वरीयता लिखी गई है। बीसीडी चुनाव में मतगणना वरीयता प्रणाली के माध्यम से की जाती है और प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती के बाद सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार को एक क्रमांक दिया जाता है, जिसे सदस्य वोट डालते समय मतपत्रों पर लिखते हैं।

अहम फैसला

अनुच्छेद 21 के तहत निजता का संवैधानिक रूप से संरक्षित पहलू बताया, अदालती आदेशों में व्यक्तिगत विवरणों को छिपाने के लिए जारी किए दिशानिर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'भूल जाने के अधिकार' को दी मान्यता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध न्यायिक रिकार्ड से व्यक्तिगत जानकारी को छिपाने के लिए एक रूपरेखा तय करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भूल जाने के अधिकार को मान्यता दी है। विभिन्न याचिकाओं पर निर्णय सुनाते हुए हाई कोर्ट ने माना कि भूल जाने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद -21 के तहत सूचनात्मक निजता का एक संवैधानिक रूप से संरक्षित पहलू है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि गूगल जैसे सर्च इंजन को किसी ऐसे मामले के लिए (निजी प्रकृति का हो या जिसका अंत बरी होने, आरोप-मुक्त होने, रद होने या समझौते के रूप में हुआ हो) नाम-आधारित सर्च में न्यायिक रिकार्ड दिखाने की हमेशा के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती।

याचिकाकर्ताओं के एक समूह को राहत देते हुए न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने अधिकारियों, सर्च इंजन आपरेटरों और कानूनी डेटाबेस प्लेटफार्म को आदेश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए निर्णयों, आदेशों और समाचार लेखों के रिकार्ड को एक सप्ताह के अंदर हटाएं। अदालत ने कहा कि क्योंकि सूचनात्मक निजता का मौलिक अधिकार किसी एक भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसलिए रिकार्ड हटाने की प्रक्रिया को वैश्विक स्तर पर लागू होना चाहिए। तीस से अधिक याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर किसी व्यक्ति का नाम न्यायिक रिकार्ड के साथ लगातार जुड़े रहना उसकी प्रतिष्ठा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है।

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल

याचिकाकर्ताओं में वे लोग शामिल थे, जिन्हें वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों में बरी या आरोपमुक्त कर दिया गया था या जिनके नाम न्यायिक रिकार्ड में केवल संयोगवश आ गए थे। इन सभी ने इंटरनेट सर्च परिणामों से संबंधित लिंक हटाने, अपनी पहचान छिपाने या न्यायिक रिकार्ड हटाने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि भूल जाने के अधिकार के तहत व्यक्ति सार्वजनिक डिजिटल मंच से अपनी निजी जानकारी को हटवाने या उस पर रोक लगवाने की मांग कर सकता है, बशर्ते कि वह जानकारी अब प्रासंगिक न रह गई।

पीठ ने दोहराया कि ऐसे मामले में राहत प्रत्येक मामले के आकलन पर निर्भर करेगी। इसमें सूचना की प्रकृति, उसकी निरंतर प्रासंगिकता, जनहित संबंधी विचार और व्यक्ति की गरिमा तथा निजता पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। इन मामलों में विशेष तौर पर बरी-आरोपमुक्त होना, समझौता और पूरी तरह से निजी प्रकृति के विवाद शामिल हैं। इनमें कोई भी कानून गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन को यह अधिकार नहीं देता कि वह न्यायिक रिकार्ड को इस तरह से हमेशा के लिए इंडेक्स और प्रदर्शित करता रहे।

सार्वजनिक हस्ती के अतीत के आचरण को मिटाने का माध्यम नहीं है भूल जाने का अधिकार : यौन उत्पीड़न व नशे से जुड़े मामले में राहत देने से इन्कार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, भूल जाने का अधिकार किसी सार्वजनिक हस्ती के अतीत के आचरण को मिटाने का कोई माध्यम नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता पी.पी. माधवा को राहत देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि माधवा ने खुद को एक सार्वजनिक हस्ती बताया था और अपने खिलाफ यौन अपराध के एक मामले में समझौता हो जाने के बाद, रिकार्ड को हटाने की मांग की थी।

हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन व चौकीदार कर रहे जनगणना, व्यवस्था राम भरोसे

सुमित शिशोदिया • जागरण

- सामान्य मोबाइल में गणना के लिए एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे ये लोग

नोएडा : जनगणना की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यहां जनगणना के प्रथम चरण में हाउस लिस्टिंग ब्लाक (एचएलबी) की गणना विकास प्राधिकरण के चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन और हेल्पर जैसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से कराई जा रही है। इनमें से ज्यादातर कर्मचारियों के पास न तो स्मार्ट फोन है और न ही प्रशिक्षण में पूरी जानकारी दी गई है। आरोप है कि अधूरे प्रशिक्षण और स्मार्ट फोन न होने के चलते शहर में 1096 एचएलबी शुरू नहीं हो पाई है।

गौतमबुद्ध नगर में जनगणना के प्रथम चरण में हाउस लिस्टिंग ब्लाक (एचएलबी) की गणना के लिए केवल हेल्पर या चौकीदारों को ही नहीं, बल्कि बेलदार, इलेक्ट्रिशियन और जल खंड से कर्मचारियों को भी मैदान में उतारा गया है। समस्या यह है कि ये ज्यादातर कर्मचारी एंड्रायड-12 व आइफोन 14 चलाना नहीं जानते हैं। एक अन्य कर्मचारी ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि वह प्राधिकरण में हेल्पर का काम करते हैं। मासिक वेतन 22 हजार रुपये करीब मिलते हैं, लेकिन एचएलबी का काम मिलने की वजह से 19 हजार रुपये में नया स्मार्ट फोन खरीदा है। अब परिवार में पत्नी और चार बेटियों के पालन पोषण का संकट गहरा गया है। मकान की गणना करने में आ रही समस्या पर उन्होंने बताया कि सेक्टर-51 में अधिकांश लोग महत्वपूर्ण जानकारी देने में सहयोग नहीं कर रहे।

9 अरब अमेरिकी डालर तक बढ़ गई है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। आने वाले वर्षों में इसमें पांच से छह गुना वृद्धि होने की उम्मीद है।

'पीएम स्वनिधि' से अनगिनत रेहड़ी-पटरी वालों का जीवन बदला : मोदी

- पीएम बोले-छह वर्षों में 95 प्रतिशत लाभार्थियों को पहली बार संस्थागत ऋण मिला
- सरकार ने 2030 तक योजना बढ़ाई, इसमें 7,332 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ बजट

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि रेहड़ी और पटरी वालों का समर्थन करने वाली पीएम स्वनिधि योजना ने अनगिनत स्ट्रीट वेंडरों के जीवन को बदल दिया है, क्योंकि इसने उन्हें बिना सिक्योरिटी मिले ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित की है। योजना के छह साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि विश्वास, गरिमा, सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक योगदान का प्रतीक है।

कोविड महामारी के दौरान जून, 2020 में शुरू की गई इस योजना को सरकार ने 2030 तक बढ़ा दिया है। इसमें 7,332 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ बजट और उच्च ऋण सीमाएं शामिल हैं। इसका लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच बनाना और यूपीआइ-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जैसे प्रोत्साहनों से आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देना है।

पीएम मोदी ने एक पोस्ट में कहा, "आज हम पीएम स्वनिधि के छह वर्ष का जश्न मना रहे हैं। एक योजना जिसने अनगिनत रेहड़ी और पटरी वालों की जिंदगी को बदल दिया है, जिससे उन्हें बिना किसी पूंजी या संपत्ति को गिरवी रखे ही ऋण मिल जाता है। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर मिले हैं।" उन्होंने कहा, "मेरी शुभकामनाएं सभी लाभार्थियों को जिनकी दृढ़ता और उद्यमिता हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है।"

नरेन्द्र मोदी। फाइल

सरकार के अनुसार, पीएम स्वनिधि से भारत में लगभग 95 प्रतिशत लाभार्थियों ने पहली बार औपचारिक संस्थागत ऋण प्राप्त किया, जबकि 30 प्रतिशत ने पीएम स्वनिधि के ऋण से आगे बढ़कर अतिरिक्त ऋण प्राप्त किया। पीएम स्वनिधि ने लगभग 20 प्रतिशत वार्षिक आय वृद्धि में योगदान दिया। केंद्र ने कहा कि 800 करोड़ रुपये रेहड़ी-पटरी वालों को कैशबैक प्रोत्साहनों और ब्याज सब्सिडी से पहुंचे, जिससे डिजिटल भुगतान को और अधिक लाभकारी बनाया गया और मजबूत वित्तीय आदतें विकसित की गईं। 75 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों ने 112 लाख से अधिक ऋण प्राप्त किए, जिनकी कुल राशि 17,800 करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार ने कहा, "841 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन के साथ स्ट्रीट वेंडर तेजी से विकसित हो रहे।"

भारत के खिलाफ नहीं होगा म्यांमार की धरती का इस्तेमाल : ह्लाइंग

- राष्ट्रपति ह्लाइंग ने पीएम नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक चर्चा की
- मोदी ने म्यांमार में लोकतंत्र की प्रतीक आंग सान सू की एवं लोकतंत्र की बहाली का मुद्दा भी उठाया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चीन के समर्थक माने जाने वाले म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने पीएम नरेन्द्र मोदी को आश्वस्त किया है कि म्यांमार की धरती का प्रयोग कभी भी भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के साथ म्यांमार की 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। म्यांमार की आंतरिक अस्थिरता व वहां चीन का बढ़ता प्रभुत्व लंबे समय से चिंता का विषय रहा है।

सोमवार को दिल्ली में मोदी व ह्लाइंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में इन सभी संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। इसमें व्यापार एवं आर्थिक संबंध, रक्षा एवं सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहायता व सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं। दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और ज्ञापनों पर चल रही चर्चाओं को जल्द पूरा करने की इच्छा जताई।

म्यांमार में फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट और लंबे संघर्ष के बाद, अप्रैल, 2026 में हुए संसदीय चुनावों के जरिये ह्लाइंग ने सत्ता संभाली है। इस चुनाव से वैसे इस देश की आंतरिक स्थिति में बहुत सुधार की संभावना नहीं दिख रही है। एक तरफ म्यांमार की सेना है,दूसरी तरफ लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने वाले दल एवं चिन ब्रदरहुड व आराकान आर्मी जैसी विद्रोही सेना है।

नई दिल्ली में सोमवार को म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग का स्वागत करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एएनआइ

रखाइन प्रांत के अधिकांश हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है। साथ ही, चीन का वर्चस्व भी म्यांमार की सरकार पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ह्लाइंग ने चुनाव में विजयी होने के बाद विदेश दौरे के तौर पर भारत को चुनकर दिल्ली को यह संदेश दिया है कि वह भारत के हितों की रक्षा कर सकते हैं। यह बात उन्होंने मोदी को भी साफ तौर पर बताई है। मोदी ने भी म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के अटूट समर्थन को दोहराया। ह्लाइंग अपने कैबिनेट के पांच वरिष्ठ मंत्रियों और एक बड़े औद्योगिक दल के साथ भारत आये हैं।

मोदी व ह्लाइंग के बीच बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा (रुपया-क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म) के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है।

म्यांमार, चीन के साथ पहले से ही इस तरह की व्यवस्था कर चुका है। वहां चीन बहुत बड़ा निवेशक है, खास तौर पर म्यांमार के दुर्लभ खनिजों के भंडार पर चीनी कंपनियों का अधिकार बढ़ता जा रहा है। भारत एवं म्यांमार के बीच दो अरब डालर का कारोबार होता है। व्यापार व निवेश सहयोग को और गहरा करने के लिए दोनों देश कृषि प्रसंस्करण, पेट्रोलियम, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। यह सहयोग दोनों देशों के संबंधित राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के अनुसार होगा।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी के अनुसार, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने म्यांमार की आंतरिक शांति प्रक्रिया और समावेशी राजनीति पर भी चर्चा की। भारत, म्यांमार की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है तथा दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखते हुए क्षेत्र का दुरुपयोग रोकने पर सहमति जताई।" मोदी ने म्यांमार में लोकतंत्र की प्रतीक आंग सान सू की का मुद्दा भी उठाया। भारत की यह इच्छा दोहराई कि म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जल्द से जल्द बहाली होनी चाहिए। सू की को एक फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने सत्ता से बेदखल कर दिया था व उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन पर कई आरोप लगाए गए और उन्हें सजा सुनाई गई। अब उन्हें जेल से निकालकर घर में नजरबंद कर दिया है। भारत उन्हें रिहा करने की भी मांग करता रहा है।

थक चुकी धरती को फिर से जिंदा करने को 'खेत बचाओ अभियान'

कृषि विशेषज्ञों की 1,650 से अधिक टीमें मैदान में उतरीं, किसानों को करेंगी जागरूक

अधिक खाद से ज्यादा उत्पादन नहीं, बल्कि मिट्टी के साथ ही सेहत को क्षति

अरविंद शर्मा • जागरण

नई दिल्ली: देश में खेती की सबसे बड़ी समस्या अब खाद की कमी नहीं, बल्कि उसका अंधाधुंध और गलत इस्तेमाल है। खेतों में जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने के कारण मिट्टी की सेहत लगातार बिगड़ रही है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सरकार को मिट्टी बचाने के लिए सोमवार से 'खेत बचाओ अभियान' शुरू करना पड़ा। कृषि विशेषज्ञों की 1,650 से अधिक टीमें कम खाद, सही खाद और सही सलाह के नारों के साथ गांव-गांव जाएंगी। किसानों को समझाएंगी कि अधिक खाद से अधिक उत्पादन नहीं, बल्कि मिट्टी के साथ-साथ सेहत का भी नुकसान होता है।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, फसलों को संतुलित पोषण देने के लिए खेतों में नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी) एवं पोटाश (के) का अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 9.3:3.5:1 तक पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब है कि किसान बेतहाशा नाइट्रोजन आधारित उर्वरक खासकर यूरिया डाल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यूरिया की सस्ती उपलब्धता है। केंद्र सरकार यूरिया पर हर साल पौने दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी देती है, जिससे इसकी कीमत काफी कम रहती है। किसान हरियाली एवं फसल की तेज वृद्धि देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। लंबे समय में यही आदत मिट्टी को जहरीला बना देती है। बता दें कि यूरिया में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, डीएपी में फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड में पोटाश होता है।

उर्वरक के साथ किसान। फाइल

कई राज्यों में स्थिति चिंताजनक : पंजाब-हरियाणा में एनपीके अनुपात मानकों से कई गुना अधिक हो चुका है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं राजस्थान में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। रासायनिक उर्वरकों के दबाव से मिट्टी में जैविक कार्बन घट रहा है। जिंक, सल्फर और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बढ़ रही है। हताशा में किसान खाद की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी उत्पादन नहीं बढ़ रहा। यानी लागत निरंतर बढ़ रही है और लाभ घट रहा है।

यूरिया का बेतहाशा इस्तेमाल भूजल को कर रहा जहरीला : अधिक यूरिया का असर सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। इसका बड़ा हिस्सा मिट्टी में रिसकर भूजल तक पहुंच जाता है। इससे पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती है जो पेयजल को दूषित करता है। ऐसे में उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ अब मिट्टी बचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और राज्य सरकारों की टीमें गांव-गांव पहुंचेंगी। किसानों को मिट्टी परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक खाद और फसल की जरूरत के अनुसार पोषण प्रबंधन की जानकारी देंगी। खेत बचाने के साथ उर्वरकों पर हो रहे बेतहाशा खर्च के बारे में भी बताया जाएगा।

उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने वाले शीर्ष 12 राज्य

राज्य	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटाश (अनुपात)
नगालैंड	101	5.8	1
राजस्थान	45.7	15	1
झारखंड	37.3	11	1
पंजाब	29.8	6.5	1
हरियाणा	29.2	7.3	1
उत्तर प्रदेश	22.7	6.7	1
उत्तराखंड	22.2	5.1	1
मध्य प्रदेश	15.3	6.8	1
गुजरात	14.7	4.6	1
तेलंगाना	12.6	4.8	1
छत्तीसगढ़	11.2	5.1	1
बिहार	11	3.3	1

हिंद-प्रशांत की सुरक्षा के लिए भारत और आस्ट्रेलिया ने मिलाया हाथ

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उनके आस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्लेस ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गर्मजोशी दी
- उच्च स्तरीय वार्ता में समुद्री स्वतंत्रता, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा व रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने पर जोर

नई दिल्ली, प्रेट्र : वैश्विक उथल-पुथल, पश्चिम एशिया संकट के बाद ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर चिंताओं के बीच भारत और आस्ट्रेलिया के रिश्ते एक नए और ऐतिहासिक दौर में प्रवेश कर चुके हैं। नई दिल्ली में आयोजित 'रक्षा मंत्रियों के दूसरे दौर के संवाद' में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके आस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्लेस ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गर्मजोशी दी। दोनों नेताओं ने माना कि आज दोनों देश रणनीतिक रूप से जितने करीब हैं, उतने इतिहास में कभी नहीं रहे। दोनों देशों ने सोमवार को नौवहन, हवाई पारगमन और निर्बाध समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया।

रक्षा साजो-सामान के लिए बनेगा समझौता : इस उच्च स्तरीय बैठक का सबसे बड़ा और ठोस नतीजा दोनों देशों के बीच रक्षा साजो-सामान और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) विकसित करने का निर्णय रहा। यह कदम सैन्य हार्डवेयर के सह-उत्पादन और सह-विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। दोनों देशों ने 'ज्वाइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलाबोरेशन रोडमैप' को अंतिम रूप देने और समुद्री गश्ती विमानों के जरिये 'अंडर-सी डोमेन अवेयरनेस' (समुद्र के भीतर की निगरानी) बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके अलावा, आपसी तालमेल को मजबूत करने के लिए इसी साल पहली 'ज्वाइंट स्टाफ टाक्स' शुरू करने का भी स्वागत किया गया।

'क्वाड' को मजबूती और मुक्त समुद्री व्यापार का संकल्प : दोनों मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों (विशेषकर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन 1982) के तहत समुद्री स्वतंत्रता, उड़ानों की आजादी और निर्बाध व्यापार का पुरजोर समर्थन किया। दोनों देशों ने भारत, आस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के 'क्वाड' समूह की बढ़ती ताकत की सराहना की। गुरुग्राम स्थित 'इन्फार्मेशन फ्यूजन सेंटर' के माध्यम से समुद्री क्षेत्र की कमान को मजबूत करने और समूचे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक साझा परिचालन ढांचा तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

नई दिल्ली में सोमवार को गार्ड आफ आनर के दौरान अपने आस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्लेस का स्वागत करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एएनआइ >>

भारत-आस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति करने के लिए तैयार है। हमने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इसे और अधिक बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। - राजनाथ सिंह

आज हमारे संबंध इतिहास के सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं, जो गहरे भरोसे की बुनियाद पर टिके हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि हमारे साझेदारों के साथ मिलकर काम करने पर निर्भर करती है। - रिचर्ड मार्लेस

114 राफेल की खरीद के लिए फ्रांस अनुरोध पत्र जारी, 94 भारत में बनेंगे

- दोनों देशों की सरकारों के बीच होगा लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये का सौदा
- भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी में बनेंगे विमान, पहली बार बनेंगे फ्रांस से बाहर

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत ने वायुसेना के लिए 114 राफेल युद्धक विमान खरीदने के लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये के सौदे के लिए फ्रांस को अनुरोध-पत्र (एलओआर) जारी किया है। सौदे के तहत फ्रांसीसी निर्माता कंपनी दासौ एविएशन 94 राफेल जेट भारत में किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी में बनाएगी। इस तरह पहली बार राफेल को फ्रांस के बाहर बनाया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की खरीद शाखा ने पिछले हफ्ते फ्रांस सरकार के अफसरों को अनुरोध-पत्र जारी किया था। फ्रांस की ओर से अगले दो-तीन माह में भारतीय अनुरोध-पत्र या निविदा का जवाब आने की उम्मीद है। दोनों देश अगले एक वर्ष के भीतर सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं। पीएम नरेन्द्र मोदी के जून के मध्य में फ्रांस जाने की उम्मीद है और फ्रांसीसी नेतृत्व के साथ बैठक में राफेल सौदे पर भी बात होने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह इस समय फ्रांस में हैं। वह दासौ एविएशन की फ्रेंच इकाई का दौरा भी कर सकते हैं।

भारत, युद्धक विमानों की बेहद कमी का सामना कर रहा है और 4.5वीं पीढ़ी के राफेल विमानों को बड़ी संख्या में शामिल करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वायुसेना और नौसेना ने पहले ही 62 राफेल विमानों के आर्डर दे दिए हैं। 114 राफेल के आर्डर से यह संख्या 176 हो जाएगी। नौसेना समुद्री खतरों से निपटने के लिए 31 और विमानों को शामिल करने का इरादा पहले ही जाहिर कर चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के 2024 में पद संभालने के तुरंत बाद उनकी अगुआई में भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए एक बड़ा अध्ययन किया था और रक्षा मंत्रालय इस दिशा में केंद्रित तरीके से काम कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीश नियुक्त, शपथ आज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इससे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है जो कुल मंजूर पद 38 से एक कम है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत मंगलवार को नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। नवनियुक्त पांच न्यायाधीशों में चार हाई कोर्ट से प्रोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जबकि पांचवां नाम वरिष्ठ वकील वेंकिटा सुब्रमणि मोहना का है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीधे नियुक्त होने वाली वह दूसरी महिला न्यायाधीश हैं। इससे पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त हुई थीं, जो मार्च, 2021 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। वीएस मोहना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 12वीं महिला जज हैं और वह जून, 2031 में सेवानिवृत्त होंगी।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से सोमवार को अलग-अलग जारी अधिसूचनाओं में सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इनमें वरिष्ठ वकील वी. मोहना के अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बांबे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली शामिल हैं।

वेंकिटा सुब्रमणि मोहना की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या दो हो जाएगी। अभी सिर्फ एक महिला न्यायाधीश बी.वी. नागरत्ना (31 अगस्त, 2021 से) हैं जो 2027 में एक माह से कुछ अधिक समय के लिए प्रधान न्यायाधीश भी बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट में दो और जज हैं जिन्हें सीधे वकील से जज बनाया गया है, ये हैं- पीएस नरसिम्हा और जस्टिस केवी विश्वनाथन।

केंद्र की मंजूरी

- वीएस मोहना वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली दूसरी महिला
- इससे पहले इंदु मल्होत्रा नियुक्त हुई थीं, जो अब हो चुकी हैं सेवानिवृत्त

चार दिनों में ही मिली मंजूरी

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 27 मई को इन पांचों लोगों को न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी और चार दिन के भीतर ही नियुक्तियां हो गई हैं। ज्ञात हो, केंद्र ने कुछ दिन पहले ही अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से 38 की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल मंजूर पद प्रधान न्यायाधीश को मिलाकर 38 हो गए हैं। संख्या बढ़ने के बाद ये पांच नियुक्तियां हुई हैं। सरकार ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के बोझ को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है। हालांकि अभी भी एक पद रिक्त है।

जल संसाधन के प्रबंधन के लिए किया जाएगा सेटेलाइट का उपयोग

- केंद्र सरकार ने इसरो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए
- जलाशय निगरानी समेत 24 अनुसंधान क्षेत्रों में मिलकर करेंगे काम

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में जल संसाधन के प्रबंधन में सेटेलाइट टेक्नोलाजी का उपयोग किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय और इसरो ने जल संसाधन प्रबंधन में उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

जल शक्ति मंत्रालय ने नए जल अनुसंधान मिशन की भी शुरुआत की। इसके तहत प्रति परियोजना 20 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। देशभर में दो करोड़ जल-संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डा. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत जल संसाधन विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जलाशय निगरानी, नदी-प्रवाह विश्लेषण, उपग्रह-आधारित जल गुणवत्ता आकलन और जलाशयों में प्लास्टिक कचरे के बढ़ने पर अध्ययन सहित 24 अनुसंधान क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल सुरक्षा अहम है। जल संबंधी चुनौतियों का समाधान प्रौद्योगिकी, नवाचार, पारंपरिक ज्ञान व जनभागीदारी के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा इस साझेदारी से भूजल आकलन, जल संसाधन निगरानी और बाढ़ पूर्वानुमान जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी।

जल शक्ति मंत्री ने जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) अभियान के तीसरे चरण का भी शुभारंभ किया और मई 2027 तक दो करोड़ जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य घोषित किया। कहा, अभियान के पहले चरण ने 10 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के लक्ष्य के मुकाबले 27.5 लाख संरचनाओं का निर्माण किया गया।

जांच पड़ताल

महाराष्ट्र की 80 लाख महिलाएं लाडकी बहिन योजना के अयोग्य, विपक्ष हमलावर

ई-केवाईसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ से घटकर हुई लगभग 1.7 करोड़, विपक्ष का दावा, योजना से लाभार्थियों को हटाना राज्य की गंभीर वित्तीय संकट का परिचायक

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

ई-केवाईसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद लगभग 80 लाख महिलाएं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लिए अपात्र हो गई हैं। जिससे विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र सरकार पर 'गंभीर वित्तीय संकट' के कारण लाभार्थियों को बाहर करने के आरोप लगाए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को जानकारी दी कि ई-केवाईसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ से घटकर लगभग 1.7 करोड़ हो गई है। महिलाओं के नाम कटने का कारण मानदंडों का पालन न करने से भी जुड़ा है।

अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने लाभार्थियों को ई-केवाईसी पूरा करने के लिए आठ माह का समय दिया था। 50 से 55 लाख महिलाएं पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में असफल रहीं, जबकि दो से तीन लाख महिलाओं ने इस अवधि के दौरान अपनी त्रुटियों को सुधारा। इसके अतिरिक्त लगभग 12 लाख महिलाएं ऐसी पाई गईं जिनकी वार्षिक आय योजना के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक थी।

लाडली बहिना योजना। फाइल

इसके अलावा 45 लाख से अधिक महिलाएं 65 वर्ष के ऊपर आयु सीमा को पार कर चुकी थीं, जिन्हें किसी अन्य सरकारी योजना के तहत लाभ मिल रहा है या मिल सकता है। उन्होंने आगे बताया कि नमो शेतकरी योजना के तहत लगभग पांच लाख महिलाओं को पहले से ही लाभ मिल रहा है। अधिकारी ने कहा कि वास्तविक लाभार्थियों की अंतिम संख्या एक सप्ताह में स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया कि ई-केवाईसी पूरा न करने के आधार पर ही 80 लाख महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया था।

वहीं, विपक्षी दल राकांपा (शरदचंद्र पवार) के नेता जयंत पाटिल ने दावा किया कि योजना से लाभार्थियों को हटाना राज्य के 'गंभीर वित्तीय संकट' को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली यह योजना लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन के बाद 2024 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई थी। अब लगभग 80 लाख महिला लाभार्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। यह उन लोगों को पूरी तरह से त्यागने के समान है, जिन्हें सहायता का वादा किया गया था। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि यह कदम राज्य सरकार पर बढ़ते वित्तीय दबाव का संकेत है।

इसी पार्टी के विधायक रोहित पवार ने भी आरोप लगाया कि केवाईसी महज एक बहाना है। असली मकसद लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और अंततः योजना को बंद करना है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महायुति सरकार पर इस योजना के लाभार्थियों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को केवल चुनाव जीतने के लिए शुरू किया गया था। राकांपा (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि सरकार को लगभग डेढ़ साल बाद ही पता चला कि कथित तौर पर 80 लाख महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र थीं। यह राजनीतिक, प्रशासनिक और कार्यान्वयन स्तर पर सरकार की गंभीर विफलता को दर्शाता है।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

7 सीटों पर कर्नाटक में राज्य विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने हैं, जबकि राज्य विधान परिषद के लिए एकमात्र उपचुनाव बिहार में होगा। यह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में चुने जाने के बाद खाली हुई सीट के लिए होगा।

बंगाल में 'पुरुष' ले रहे थे लक्ष्मी भंडार योजना की राशि, एसआइटी करेगी जांच

22 फर्जी खातों का चला पता, अन्नपूर्णा योजना की स्क्रूटनी में घोटाला आया सामने

वैध लाभार्थियों को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का भरोसा– 'सबको मिलेगा हक'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

बंगाल में महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई 'अन्नपूर्णा योजना' के आते ही पूर्ववर्ती सरकार के समय 'लक्ष्मी भंडार' योजना में हुए बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नवान्न में एक प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान बताया कि महिलाओं के लिए तय सरकारी राशि अवैध रूप से पुरुषों और घुसपैठियों के खातों में जा रही थी। अब तक ऐसे 22 फर्जी खातों का पता चला है, जिनमें महिलाओं के लिए निर्धारित योजना की राशि पुरुषों के खातों में पहुंच रही थी। मुख्यमंत्री के अनुसार, एक खाता राकिबुल शेख का, 15 खाते मुस्ताफिजुर रहमान और उनकी पत्नी तुहिना से जुड़े तथा छह खाते तारिकुल रहमान से संबंधित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह संख्या और बढ़ सकती है तथा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह पूछने पर कि क्या इसकी मनी लांड्रिंग की भी जांच होगी तो उन्होंने कहा कि अभी एसआइटी की जांच होने दीजिए। मुख्यमंत्री ने इस महाघोटाले की जड़ तक जाने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने का कड़ा निर्देश दिया है।

तीन जून को भेजी चाएगी अन्नपूर्णा योजना की राशि : अन्नपूर्णा योजना के लंबे और विस्तृत फार्म को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि तीन जून को कैबिनेट की पूर्ण बैठक के साथ ही एक बड़ी संख्या में पात्र उपभोक्ताओं के बैंक खातों में राशि सीधे भेज दी जाएगी। वैध लाभार्थियों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

कोलकाता में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। एएनआइ

नीति आयोग की बैठक से पहले शुभेंदु ने सभी विभागों के सचिवों से मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण। कोलकाता : दिल्ली में आगामी 11 जून को होने वाली नीति आयोग की बैठक से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार के सभी विभागों के सचिवों से उनके विभागों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। निर्देश दिया गया है कि पांच जून तक सभी रिपोर्ट राज्य सचिवालय को सौंप दी जाएं। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में बंगाल की समग्र प्रशासनिक और वित्तीय स्थिति को विस्तार से रखना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से वह पहले सभी विभागों की मौजूदा स्थिति का आकलन कर रहे हैं। राज्य सचिवालय के अधिकारियों का मानना है कि पिछले 15 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार की कथित असहयोगी नीति के कारण राज्य केंद्र से मिलने वाले कई वित्तीय लाभों से वंचित रहा। नई सरकार अब उन बकाया अधिकारों और केंद्रीय सहायता को हासिल करने पर विशेष जोर दे रही है। गौरतलब है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें बालुरघाट से उम्मीदवार बनाया था और वह विजयी भी हुए थे। इस बार उन्हें चुनाव में नहीं उतारा गया था। बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद ही उन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

पंजाब कांग्रेस में बदलाव के संकेत

राज्य ब्यूरो, जागरण, चंडीगढ़ः कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के शीर्ष नेताओं में बीते कई दिनों से चल रही अंदरूनी खींचतान को विराम देने की कवायद शुरू कर दी है। पंजाब के शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर दिल्ली बुलाया गया है। सप्ताह के भीतर दिल्ली से यह दूसरी बार बुलावा आया है। हाईकमान द्वारा तय कर लिया गया है कि पंजाब में चुनाव से पूर्व न सिर्फ संगठन, बल्कि विधायक दल के नेतृत्व में भी बदलाव किया जाए। मंगलवार को होने वाली बैठक के तुरंत बाद इसकी घोषणा हो सकती है।

सूत्र बताते हैं कि बैठक का समय दोपहर को रखा गया है, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय राजस्थान के पुष्कर में हैं। उनकी वापसी का समय तय नहीं है, इसलिए बैठक के समय में बदलाव भी हो सकता है। यह भी पता चला है कि बीते दिनों हुई बैठकों के दौरान चर्चा और काडर की फीडबैक के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के स्थान पर विजय इंदर सिंगला की नियुक्ति तय हो चुकी है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बदलने की भी चर्चा : चर्चा है कि प्रताप सिंह बाजवा के स्थान पर अरुणा चौधरी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लाया जाएगा। इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा, चरनजीत सिंह चन्नी व सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी चुनाव के मद्देनजर जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।

कर्नाटक में मंत्रिपरिषद के गठन पर हाईकमान से वार्ता के लिए दिल्ली पहुंचे शिवकुमार और सिद्दरमैया

- कल शाम 4:05 बजे कुछ मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे शिवकुमार
- सिद्दरमैया की मंत्रिपरिषद में शामिल रहे कई चेहरों को शायद नहीं मिलेगी जगह

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और वरिष्ठ नेता सिद्दरमैया तीन जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य की नई मंत्रिपरिषद के गठन पर कांग्रेस हाईकमान से सलाह-मशविरा करने के लिए सोमवार को दिल्ली पहुंचे। शनिवार को कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का औपचारिक तौर पर नेता चुने जाने के बाद शिवकुमार अब सिद्दरमैया की जगह लेंगे। शिवकुमार बुधवार शाम 4:05 बजे कुछ मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

शिवकुमार ने यहां कर्नाटक भवन में पत्रकारों से वार्ता में कहा, 'हमें (मंत्रिमंडल के बारे में) फैसला करना है।' उधर, सिद्दरमैया दिल्ली के एक निजी होटल में रुके हैं। कर्नाटक की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत 34 लोग ही हो सकते हैं। मंत्री पद के लिए आकांक्षी लोगों की बढ़ती संख्या के साथ शिवकुमार के लिए यह उनका पहला और सबसे बड़ा टेस्ट है।

पार्टी सूत्रों ने माना कि जो लोग मंत्रिपरिषद में जगह नहीं बना पाएंगे, उनमें बड़े पैमाने पर नाराजगी का खतरा है। रविवार को जब उनके साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या के बारे में पूछा गया था, तो शिवकुमार का कहना था, 'मुझे नहीं पता। पार्टी हाईकमान जो भी तय करेगा, वही किया जाएगा। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।'

बड़ी संख्या में मंत्री पद के आकांक्षी दिल्ली पहुंच गए हैं, पुराने मंत्री व विधायक अपनी दावेदारी पेश करने के लिए शिवकुमार और सिद्दरमैया दोनों से मिलना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि नई मंत्रिपरिषद में जाने-पहचाने चेहरे और नए लोग शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाति, क्षेत्रीय संतुलन और निष्ठा के समीकरणों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

अटकलें हैं कि नई सरकार में कई उपमुख्यमंत्री हो सकते हैं और मौजूदा सिद्दरमैया मंत्रिमंडल कई मंत्री शायद न रहें। सिद्दरमैया के एमएलसी बेटे यतींद्र ने रविवार को शिवकुमार से मिलने के बाद कैबिनेट में जगह मिलने का भरोसा जताया और कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें मंत्री पद का भरोसा दिया है। दिल्ली इस सवाल पर भी बात होने की उम्मीद है कि शिवकुमार की जगह कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा।

भाजपा में पहली बार राष्ट्रीय संगठक का नया पद सृजित, नागेंद्र नाथ को मिली जिम्मेदारी

- वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के बीच तालमेल में होगी सक्रिय भूमिका
- उत्तराखंड से राजस्थान में संगठन के प्रदेश महामंत्री बनाए गए अजेय कुमार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बिहार और बंगाल की चुनावी गहमागहमी से फुर्सत होने के बाद भाजपा ने अब संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में काम तेज कर दिया है। महत्वपूर्ण यह है कि संगठन के विस्तार में युवाओं को जोड़ने के साथ ही पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चलना चाहती है। इसी उद्देश्य से पहली बार भाजपा में राष्ट्रीय संगठक का पद सृजित किया गया है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के बीच तालमेल और संवाद का यह दायित्व पार्टी ने संगठन के अनुभवी और संघ की पृष्ठभूमि वाले नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को सौंपा है। उन्हें राष्ट्रीय संगठक (वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क) के पद पर नियुक्ति दी गई है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर युवा नेता नितिन नवीन के चयन के बाद से ही यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी अब युवाओं को संगठन में आगे बढ़ाना चाहती है। नए और पुरानों का संतुलन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कैसे साधा जाएगा, वह जल्द ही कार्यकारिणी की घोषणा के साथ साफ हो जाएगा। इस बीच, पार्टी ने उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी संज्ञान लिया है, जिन्होंने वर्षों तक संगठन के लिए संघर्ष किया है और जमीनी प्रभाव भी रखते हैं। अक्सर ऐसी बातें भी सुनाई पड़ती हैं कि कई बार वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बात व्यस्तता के कारण शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाती।

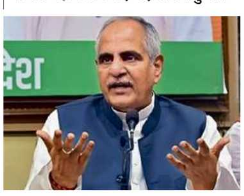
नागेंद्र नाथ त्रिपाठी। सौ. भाजपा

नागेंद्र नाथ त्रिपाठी की नियुक्ति को इसी शिकायत के निवारण के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा उन्हें राष्ट्रीय संगठक (वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क) बनाए जाने का पत्र सोमवार को राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की ओर से जारी किया गया। इसमें नागेंद्र नाथ त्रिपाठी का केंद्र दिल्ली रहेगा। उल्लेखनीय है कि नागेंद्र नाथ मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। संघ से जुड़ाव के साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। उप्र में प्रदेश महामंत्री संगठन का दायित्व निभा चुके हैं और इस नियुक्ति के पहले तक वह बिहार और झारखंड के प्रदेश महामंत्री संगठन का जिम्मा संभाल रहे थे। वह देशभर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच सेतु का काम करेंगे। इसी तरह पार्टी ने राजस्थान में भी ढाई वर्ष से रिक्त चल रहे प्रदेश महामंत्री संगठन के पद पर अजेय कुमार की नियुक्ति की है। वह अभी उत्तराखंड में इसी दायित्व को संभाल रहे थे।

अभिषेक पर हमला मामले में छह आरोपितों को मिली जमानत

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 11 आरोपितों की पहचान की है। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है कि आरोपितों में से अधिकांश का भाजपा से संबंध है और वे पार्टी के पदाधिकारी या सक्रिय सदस्य हैं। इधर, मामले में गिरफ्तार छह आरोपितों को सोमवार को जमानत मिल गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इन आरोपितों का टीएमसी के ही एक गुट से संबंध रहा है।

अभिषेक और सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमले और चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं के खिलाफ पार्टी ने सोमवार को राज्य के सभी ब्लाकों व वार्डों में विरोध जुलूस निकाला। हालांकि इनमें पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की काफी कम उपस्थित रही। मंगलवार को ममता बनर्जी के प्रस्तावित धरने के लिए रानी रासमणि एवेन्यू में मंच निर्माण की अनुमति कोलकाता पुलिस ने नहीं दी। पुलिस ने धर्मतला स्थित वाई चैनल को वैकल्पिक स्थान के रूप में सुझाया।

संगठन विस्तार के लिए भाजपा में पदाधिकारियों के साथ महामंथन

- पार्टी पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ नितिन नवीन की अहम बैठक
- भाजपा के विस्तार व कार्यप्रणाली में दिखेगा बड़ा परिवर्तन : संबित पात्रा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दो दर्जन से अधिक राज्यों में सरकार बनाने और 14 करोड़ से अधिक सदस्य संख्या वाली भाजपा अपने संगठन विस्तार की कवायद में जुट गई है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारिओं और प्रदेश अध्यक्षों के साथ मैराथन बैठक की।

भाजपा कार्यालय में पांच घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों और पेशेवरों की बीच पार्टी की पहुंच मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा के पहले इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पात्रा ने कहा कि आने वाले समय में भाजपा के संगठन के विस्तार के साथ ही पार्टी की कार्यपद्धति में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कार्यकर्ताओं के सुझावों को संग्रहित कर उन पर अमल को एक संस्थागत रूप देना जरूरी है। चर्चा के मुद्दों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इनमें चार-पांच मुद्दे अहम हैं। इनमें अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए, महिलाओं का सशक्तीकरण कैसे हो, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और अधिक शक्ति के साथ कैसे आगे बढ़ें एवं पेशेवर लोग कैसे आगे बढ़ें जैसे मुद्दे शामिल हैं।

संबित पात्रा। फाइल

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा-राजग को 22 राज्यों में अपनी सरकार के जरिये लोगों की सेवा करने का भी मौका मिला है। पार्टी का और विस्तार बैठक का मुख्य एजेंडा था। भाजपा कार्यालय में यह महामंथन इसलिए अहम है क्योंकि पार्टी ने अगले वर्ष होने वाले सात राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी पांच राज्यों में भाजपा सत्ता में है। पात्रा ने कहा कि भाजपा को भरोसा है कि वह जिन राज्यों में अभी राज कर रही है, वहां सत्ता में बनी रहेगी और हिमाचल प्रदेश व पंजाब में अपनी सरकार बनाएगी।

हिमाचल में नगर निगमों के बाद जिला परिषदों में भी खिला कमल

- प्रदेश में 144 सीटों पर भाजपा, 57 पर कांग्रेस व 47 पर अन्य ने जीत की हासिल
- सिर्फ एक जिले में कांग्रेस को बहुमत, शिमला व कांगड़ा में किसी को बहुमत नहीं

सिरमौर जिले के नाहन में बनकला व त्रिलोकपुर जिला परिषद वार्ड से जीते प्रत्याशी जश्न मनाते हुए। जागरण

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला

एक दिन पहले हिमाचल नगर निगम चुनाव में मिली हार के बाद जिला परिषद चुनाव में भी कांग्रेस को झटका लगा है। प्रदेश के 12 में से आठ जिलों में जिला परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस को एक जिले में स्पष्ट बहुमत मिला है जबकि तीन जिलों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। रविवार को तीन नगर निगमों धर्मशाला, मंडी और सोलन में भाजपा जीती थी जबकि कांग्रेस के हाथ सिर्फ पालमपुर नगर निगम ही आया था।

जिला परिषदों की कुल 251 सीट में से 250 पर चुनाव हुआ। 248 सीटों के परिणाम में 144 पर भाजपा, 57 पर कांग्रेस व 47 पर अन्य ने जीत हासिल की है। सिरमौर की दो सीट का परिणाम अभी आना है।

चुनावी हार से परेशान अन्नाद्रमुक कार्यकर्ता ने की आत्महत्या

तंजावुर, प्रेट्र : अन्नाद्रमुक की लगातार चुनावी हार से परेशान एक 32 वर्षीय पार्टी कार्यकर्ता ने थिरुप्पानंदल में आत्महत्या कर ली। रविवार को इस कदम को उठाने से पहले केएएस महेंद्रन ने इंटरनेट मीडिया पर खुद का फिल्माया वीडियो जारी कर पार्टी की हाल की राजनीतिक हारों पर गहरा दुख व्यक्त किया। मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।

केएएस महेंद्रन अन्नाद्रमुक तंजावुर ईस्ट ट्रेडर्स विंग के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। उनके परिवार में पत्नी और एक वर्षीय बच्चा है। मरने से पहले जारी वीडियो संदेश में उन्होंने अन्नाद्रमुक के विभिन्न गुटों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में एकजुट हों ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। सूचना मिलने पर थिरुप्पानंदल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए थिरुप्पानंदल के सरकारी अस्पताल भेजा।

उत्तर से दक्षिण तक संतुलन की अचूक बिसात

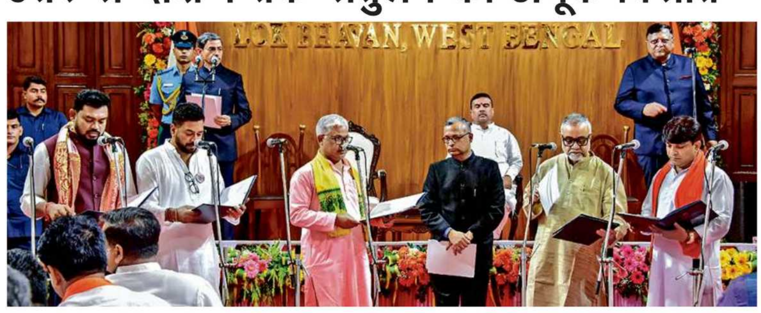

कोलकाता में सोमवार को लोक भवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाते बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि (पीछे बाएं), साथ में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। प्रेट्र

प्रथम पृष्ठ से आगे

बंगाल में इस मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य की भौगोलिक विविधता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान किया गया है। भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ 'उत्तर बंगाल' को इस बार सरकार में खासी तवज्जो मिली है। चाय बागान और राजबंशी बेल्ट से आने वाले 10 चेहरों को शामिल कर विकास का नया कारिडोर बनाने की तैयारी है। वहीं, 'जंगलमहल' के आदिवासी और कुड़मी बहुल जिलों से जुझारू नेताओं को मंत्रिपरिषद में लाकर सुदूर वनांचलों को मुख्यधारा से जोड़ा गया है। दक्षिण बंगाल और कोलकाता से कद्दावर रणनीतिकारों को कैबिनेट रैंक देकर विपक्ष के हर हमले को कुंद करने का पूरा इंतजाम किया गया है।

शुभेंदु सरकार की इस नई टीम का ताना-बाना 2026 के ऐतिहासिक जनादेश को ध्यान में रखकर बुना गया है। ममता बनर्जी के राजनीतिक एकाधिकार को तोड़ने वाले अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और मतुआ समुदाय को सत्ता में सीधी भागीदारी देते हुए रिकार्ड 13 मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही महिलाओं को केवल वोटर बैंक न मानकर प्रशासन में नीति-निर्धारक की भूमिका दी गई है। कलिता माझी के साथ-साथ फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पाल, मौमिता बिस्वास सहित सात महिलाओं को कैबिनेट का हिस्सा बनाकर भाजपा ने राज्य की आधी आबादी के बीच अपनी पैठ को संस्थागत रूप दे दिया है।

राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन शुरू

नई दिल्ली, आइएएनएस : चुनाव आयोग द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी करने के साथ ही सोमवार से राज्यसभा की 27 सीटों (द्विवार्षिक और उपचुनावों सहित) और कुछ राज्यों की राज्य विधान परिषदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मतदान 18 जून को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा, जिसके बाद शाम पांच बजे मतगणना होगी।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जून दोपहर तीन बजे तक है। नामांकन पत्रों की जांच रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नौ जून को की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून निर्धारित की गई है। 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम में आयोजित किए जाएंगे। वहीं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक-एक सीट के लिए उपचुनाव होंगे।

बिहार में राज्य विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव नौ सीटों पर होंगे।

बंगाल का मामला

मताधिकार से वंचित लोगों की जानकारी के लिए कोर्ट में याचिका

बंगाल प्रदेश कांग्रेस की एसआइआर समिति के अध्यक्ष ने दायर की है यह जनहित याचिका, प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों की भी जानकारी मांगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) के कारण मताधिकार से वंचित लोगों की विस्तृत जानकारी साझा करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

बंगाल प्रदेश कांग्रेस की एसआइआर समिति के अध्यक्ष प्रसेनजीत बोस द्वारा वकील नेहा राठी के माध्यम से दाखिल इस याचिका में चुनाव आयोग, बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य सरकार को एसआइआर से संबंधित विस्तृत डाटा सार्वजनिक करने के निर्देश देने की मांग की है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्य में एसआइआर कराए जाने का चुनावों के परिणाम पर प्रभाव पड़ा। यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई है जब हाल ही में शीर्ष अदालत ने एसआइआर को सही ठहराया था।

सुप्रीम कोर्ट से लगाई आस। फाइल

याचिका में चुनाव आयोग, बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए यह निर्देश देने की मांग की गई कि वे एसआइआर के दौरान दावों और आपत्तियों के चरण और बाद के चरणों में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जमा, स्वीकार और अस्वीकार किए गए फार्म 6 (नाम जोड़ने के लिए) और फार्म 7 (नाम हटाने के लिए) आवेदनों की संख्या के बारे में जानकारी दी जाए।

प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या के बारे में जानकारी भी मांगी गई है। गौरतलब है कि भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया है।

याचिका के अनुसार बंगाल में दावों और आपत्तियों के चरण के दौरान नामों को शामिल करने के लिए 9.64 लाख आवेदन और नाम हटाने के लिए 99,118 आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन 28 फरवरी, 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में केवल 1.82 लाख नाम ही शामिल किए गए थे।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बनाए गए अपीलीय तंत्र का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और हटाने को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन किया गया था, लेकिन सात अप्रैल को न्यायिक समिति द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस मानक संचालन प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही अपील प्रक्रिया के लिए बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी में सरल गाइडलाइंस जारी की जाएं।

याचिका में दावा किया गया कि अपील दाखिल करने, सुनवाई करने, नोटिस जारी करने और निपटान के लिए समय-सीमा के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दिशानिर्देशों के अभाव ने प्रक्रियात्मक अनिश्चितता पैदा कर दी है।

डाटा और मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया गया है कि न्यायाधिकरणों के समक्ष दायर की गई लगभग 25 लाख अपीलों में से केवल कुछ अपीलों का निपटारा हो सका है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुख पर ही नजर लगी रहेगी।

नई पार्टी बनाने के अटकलों पर अन्नामलाई बोले–दो दिन प्रतीक्षा करें

- तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के सियासी भविष्य पर अटकलें तेज

चेन्नई, एएनआइः तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई सोमवार को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने चेन्नई से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। उनके इस दौरे ने राज्य की राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इंटरनेट मीडिया पर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वे जल्द ही एक नया राजनीतिक मंच या पार्टी शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं।

दिल्ली रवाना होने से पहले अन्नामलाई से लगातार फैल रही अफवाहों पर सवाल किया गया। भाजपा छोड़ने और नई पार्टी बनाने संबंधी चर्चाओं पर उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा, 'कृपया प्रतीक्षा करें। हम दो दिन में बैठकर बात करेंगे।'

इस बीच, चार जून को अन्नामलाई की जन्मतिथि से पहले चेन्नई की प्रमुख सड़कों और इलाकों में उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों पर 'हमारे नेता, आइए और हमारा नेतृत्व कीजिए' जैसे नारे लिखे गए हैं, जिससे उनके समर्थकों की सक्रियता साफ दिखाई दे रही है।

के. अन्नामलाई। फाइल

36 वर्ष पहली बार जम्मू-कश्मीर में मई में एक भी आतंकी हिंसा नहीं हुई है। कोई नागरिक आतंकी हिंसा की भेंट नहीं चढ़ा है और न कोई सुरक्षाकर्मी आतंकियों के खिलाफ किसी अभियान में भाग लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी की 21 जून को होने वाली परीक्षा में सीबीटी की मांग ठुकराई

याचिकाकर्ता से कहा ▶ परीक्षा कराने वाली अथारिटी की व्यावहारिक दिक्कतें समझिए

एनटीए पहले से ही बहुत सारी समस्याओं का कर रही है सामना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट का व्यावहारिक दृष्टिकोण पर जोर।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा पेन-पेपर के बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में कराने की मांग सोमवार को ठुकरा दी और कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पहले से ही बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही है। कोर्ट ने हालांकि याचिका खारिज नहीं की है और मुख्य याचिका के साथ सुनवाई 27 जुलाई तक टाल दी है।

नीट-यूजी का आयोजन तीन मई को हुआ था, लेकिन पेपर लीक के कारण 12 मई को परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद अब 21 जून को दोबारा परीक्षा होनी है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। इसमें कई मांगें की गई हैं, जिसमें से एक मांग यह भी थी।

सोमवार को यह याचिका जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगी थी। सुधाकर सिंह के वकील सत्यम सिंह राजपूत ने मामले को अर्जेंट बताते हुए कहा कि वह याचिका में पहली मांग पर जोर देना चाहते हैं, वह महत्वपूर्ण है। उनकी मांग है कि नीट-यूजी की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा पेन-पेपर के बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराई जाए। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इन्कार करते हुए कहा कि परीक्षा कराने वाली अथारिटी की व्यावहारिक दिक्कतें समझिए। परीक्षा निरस्त हो चुकी है और अभी दोबारा परीक्षा होनी है। अथारिटी पहले ही कई तरह के बदलाव कर रही हैं। वकील ने बार-बार कोर्ट को सहमत करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट नहीं माना और मामले को छुट्टियों के बाद जुलाई में सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया। इस मामले में डाक्टर संघों ने पहले से ही याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं जिसकी सुनवाई में पिछले हफ्ते कोर्ट ने जवाबदेही तय करने पर जोर दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा था कि वह भविष्य की परीक्षाओं में क्या उपाय करने वाली है जिससे की पेपर लीक घटनाओं की पुनरावृति न हो।

नीट पेपर लीक मामले में तीन आरोपित 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

जासं, नई दिल्ली: राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनमें एनटीए से संबद्ध भौतिकी की लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार, महाराष्ट्र के लातूर निवासी बाल रोग विशेषज्ञ डा. मनोज शिरुरे और भौतिकी शिक्षक तेजस हर्षद कुमार शाह हैं। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने सीबीआइ की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे पूर्व मनीषा की सीबीआइ हिरासत शनिवार को दो दिन के लिए बढ़ाई गई थी, जबकि डा. मनोज शिरुरे और तेजस हर्षद कुमार शाह को 27 मई को पांच दिन की सीबीआइ रिमांड पर भेजा गया था। सीबीआइ के अनुसार, मनीषा हवलदार ने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर साजिश के तहत बिना किसी अधिकृत अनुमति के नीट-यूजी परीक्षा का प्रश्नपत्र अपने पास रखा और धन के बदले उसे साझा किया। सीबीआइ अब तक इस मामले में 13 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।

ओएसएम विवाद में फंसी कंपनी की जा सकती है ब्लैकलिस्टेट

रीतिका मिश्रा • जागरण

नई दिल्ली: सीबीएसई की 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लागू की गई आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली से जुड़े विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सख्त कार्रवाई पर विचार कर रहा है। सीबीएसई से जुड़े सूत्रों के अनुसार, डिजिटल परीक्षा सेवा प्रदाता कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड पर भारी आर्थिक दंड लगाने से लेकर भविष्य के सरकारी अनुबंधों से बाहर करने तक के विकल्पों पर चर्चा चल रही है। मामला उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया में सामने आई तकनीकी गड़बड़ियों से जुड़ा है। इसमें हजारों उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापियों में धुंधली छवियां, पन्नों के क्रम में गड़बड़ी और अन्य संरचनात्मक त्रुटियां सामने आई हैं।

सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले कंपनी पर अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन को लेकर भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि जांच में गंभीर लापरवाही या निविदा प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता साबित होती है तो कंपनी को केंद्र सरकार की भविष्य की परियोजनाओं से ब्लैकलिस्ट करने पर भी विचार किया जा सकता है। एक अन्य विकल्प कंपनी के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं करना भी है। बोर्ड के भीतर यह राय बन रही है कि भविष्य की परीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी को दोबारा जिम्मेदारी न सौंपी जाए और ओएसएम प्रणाली का विस्तार अन्य विषयों और कक्षाओं में करने से पहले इसकी व्यापक समीक्षा की जाए। द

ूसरी ओर कुछ अधिकारियों का कहना है कि कंपनी का चयन केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के माध्यम से सामान्य वित्तीय नियमों के तहत पारदर्शी प्रक्रिया से किया गया था और वह सबसे कम बोली लगाने वाली पात्र एजेंसी के रूप में उभरी थी।

पुनर्मूल्यांकन पोर्टल एक जून को भी नहीं खुला

सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों को पुनर्मूल्यांकन और अंकों के सत्यापन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ रहा है। बोर्ड ने परिणाम बाद की प्रक्रिया के लिए एक जून की तारीख तय की थी, लेकिन सोमवार देर रात तक भी पोर्टल शुरू नहीं हो सका। सीबीएसई ने सोमवार दोपहर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया कि सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल जल्द लाइव किया जाएगा और इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। वहीं, पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का इंतजार कर रहे छात्रों ने कहा कि यह केवल अंकों का मामला नहीं है।

काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक दीपके छह को भारत लौटेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र: काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को कहा कि वह छह जून को भारत लौटेंगे और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू करेंगे।

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जारी वीडियो में दीपके ने काकरोच जनता पार्टी के समर्थकों से दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हम सब संविधान के रास्ते पर चलते हुए एकजुट हों और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाएं. अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे, तो उन्हें हमारी बात जरूर सुननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि शनिवार को सुबह दिल्ली पहुंचुंगा।

एयरपोर्ट पर मेरा साथ दें और हम सब मिलकर संसद मार्ग थाने जाएंगे, ताकि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांग सकें।' दीपके द्वारा शुरू किया गया युवाओं से जुड़ा इंटरनेट मीडिया आंदोलन काकरोच जनता पार्टी पिछले महीने शुरू होने के बाद से तेजी से लोकप्रिय हुआ है।

उन्होंने दावा किया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग वाली आनलाइन याचिका पर आठ लाख हस्ताक्षर हो चुके है।

कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: ईडी की चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने पंचकूला नगर निगम के 145 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट और मास्टरमाइंड पुष्पिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोपित को विशेष पीएमएलए अदालत, पंचकूला में पेश किया और इसके रिमांड की मांग की। अदालत ने आरोपित को नौ दिन के रिमांड पर भेज दिया है। ईडी की जांच हरियाणा के पंचकूला स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की ओर से दर्ज एफआइआर के आधार पर शुरू हुई थी।

एफआइआर में नगर निगम पंचकूला के 145 करोड़ रुपये की हेराफेरी के लिए बैंक अधिकारियों की गहरी साजिश का पर्दाफाश किया गया था। जांच में सामने आया कि नगर निगम के तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी विकास कौशिक, बैंक के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप कुमार राघव और पुष्पिंदर सिंह ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो अनधिकृत बैंक खाते खुलवाए।

ओएसएम में खामियों पर कांग्रेस बोली-शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ जयराम रमेश बोले - कोएम्प्ट कंपनी को ओएसएम का ठेका देने के लिए नियमों में दी गई ढील

सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की नई आन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली की खामियों तथा उत्तर पुस्तिकाओं का डाटा लीक होने को लेकर हमलावर कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा इतिहास की सबसे बड़ी संस्थागत विफलताओं की मिसाल बन गए हैं। साथ ही कोएम्प्ट कंपनी को ओएसएम का ठेका देने के लिए नियमों में ढील दिए जाने का दावा करते हुए पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद या अपने सहयोगियों के लिए ईमानदारी या नैतिकता का कोई पैमाना तय नहीं करते लेकिन नीट पेपर लीक से लेकर अब सीबीएसई ओएसएम की गंभीर विफलता के मद्देनजर शिक्षा मंत्री प्रधान को राजधर्म का पालन करते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि सीबीएसई ने आखिरकार मान लिया है कि सिस्टम से समझौता किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय में कोएम्प्ट से लाभान्वित होने वालों को पहले से अंदाजा था कि कंपनी इस काम के योग्य साबित नहीं होगी। जयराम ने कहा कि अगस्त 2025 में सीबीएसई ने उन वेंडर्स को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार अपने पास रखा था, जो काम को प्रभावी ढंग से पूरा करने में विफल रहते।

लेकिन सितंबर में एक संशोधन जारी कर वेंडर्स को ब्लैकलिस्ट करने का अपना ही अधिकार हटा लिया और यह कोएम्प्ट को बचाने की सरकार समर्थित कोशिश दिखाई देती है जोकि उसे कांट्रैक्ट मिलने से पहले ही शुरू हो गई थी।

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का डाटा लीक होने पर कहा कि बीते 12 साल के कुशासन और दुष्प्रचार ने देश की शिक्षा व्यवस्था की नींव को खोखला कर दिया है।

बिहार के शुभम कुमार जेईई एडवांस्ड में अव्वल

जागरण टीम, नई दिल्ली

▶ आइआइटी रुड़की ने रिजल्ट जारी किया, गुरुग्राम के कबीर रहे दूसरे स्थान पर

▶ गुरुग्राम के कबीर छिल्लर रहे दूसरे स्थान पर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) रुड़की ने जेईई एडवांस्ड-2026 का परीक्षा परिणाम रविवार देर रात घोषित कर दिया। आइआइटी दिल्ली जोन के शुभम जेईई एडवांस्ड के टापर बने। वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। परीक्षा में कुल 1,87,389 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। जिनमें से 1,79,694 उम्मीदवारों ने 17 मई 2026 को आयोजित परीक्षा के पेपर-1 और पेपर-2 दोनों में भाग लिया। इस परीक्षा में कुल 56,880 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 10,107 लड़कियां हैं।

आइआइटी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस्ड-2026 परीक्षा आयोजित की गई थी। आइआइटी दिल्ली जोन के शुभम कुमार टापर रहे। उन्होंने 360 में से 330 अंक प्राप्त किए। आइआइटी दिल्ली जोन की आरोही देशपांडे लड़कियों में शीर्ष रहीं।

जिन्होंने सीआरएल 77वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने 360 में से 280 अंक प्राप्त किए। जेईई एडवांस्ड-2026 के दूसरे नंबर पर आइआइटी दिल्ली जोन के कबीर छिल्लर रहे हैं। उन्होंने 360 में से 329 अंक प्राप्त किए हैं।

आइआइटी दिल्ली जोन के ही जतिन चाहर 360 में से 319 अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। जतिन मूल रूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए आइआइटी रुड़की के निदेशक और जेएबी के चेयरमैन प्रो. कमल किशोर पंत ने जेईई एडवांस्ड 2026 उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं दीं। कहा कि यह उपलब्धि उनकी लगन, दृढ़ता और शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाण है।

योग्य अभ्यर्थी जोसा 2026 काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

शुभम को जेईई मेन में भी मिला था 100 परसेंटाइल

शुभम कुमार। सौजन्य : स्वजन

शुभम जेईई मेन-2026 के दोनों सत्रों में 100 परसेंटाइल हासिल कर चुके हैं। शुभम ने बताया कि वह पिछले दो वर्षों से जेईई की तैयारी के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए निश्चित समय-सारिणी बनाई थी और उसी अनुसार अध्ययन करते थे। लगातार अभ्यास, कमजोर विषयों पर अतिरिक्त ध्यान और नियमित आत्म मूल्यांकन को तैयारी का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को देते हुए कहा कि परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त करना अविस्मरणीय अनुभव है। शुभम के पिता शिव कुमार गयाजी शहर में ही हार्डवेयर व्यवसाय से जुड़े हैं और माता कंचन देवी गृहिणी हैं। शुभम की बड़ी बहन श्रेया कुमारी भी पिछले वर्ष जेईई की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह अभी आइआइटी पटना में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही हैं।

जतिन ने मोबाइल और इंटरनेट मीडिया से बनाई दूरी

परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल करने वाले जतिन चाहर ने पढ़ाई के दौरान मोबाइल और इंटरनेट मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी, जिससे उनका ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित रहा। उन्होंने बताया कि वह कोचिंग के अलावा प्रतिदिन छह से सात घंटे अतिरिक्त अध्ययन करते थे। इस तरह उनकी कुल पढ़ाई करीब 12 घंटे प्रतिदिन होती थी। जतिन का मानना है कि किसी भी विषय में यदि कोई समस्या आती थी तो वह तुरंत अपने शिक्षकों से उसका समाधान कर लेते थे। विषय से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान होने के बाद ही अगले टापिक पर आगे बढ़ते थे। जतिन के पिता दिनेश कुमार सीमा सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल हैं।

उत्तर प्रदेश के डीजीपी बोले, अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो एनकाउंटर होगा ही

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

▶ पूर्णकालिक डीजीपी बनने के बाद राजीव कृष्ण ने बताईं प्राथमिकताएं

▶ कहा, हर प्रकार के अपराधियों के आर्थिक स्रोत की होगी जांच

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण सोमवार को लखनऊ में प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। प्रेट्र

उत्तर प्रदेश में चार वर्ष बाद पूर्णकालिक डीजीपी बनने के बाद राजीव कृष्ण ने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के तहत पुलिस की कार्रवाई प्रभावी तरीके से जारी रहेगी। अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो उसके साथ एनकाउंटर होना तय है। समाज के हर वर्ग को सुरक्षा का अहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा और पुख्ता की जाएगी। सभी थानों में शक्ति केंद्रों की स्थापना के बाद पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिल रहा है। महिलाओं के प्रति अपराधों में 33 प्रतिशत की कमी आई है।

सोमवार को पुलिस मुख्यालय में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि राज्य में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अब एआइ की मदद लेगी। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 62 हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में 400.66 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज की गई है। संगठित अपराधियों, माफिया व उनसे जुड़े सफेदपोश अपराधियों के विरुद्ध रणनीतिक, वित्तीय और तकनीक-आधारित कार्रवाई को और सुदृढ़ किया जाएगा। अपराध से अर्जित संपत्तियों, बेनामी निवेश, शेल कंपनियों, हवाला नेटवर्क, फर्जी लेन-देन और अन्य वित्तीय माध्यमों की गहन जांच कर उनके आर्थिक स्रोतों की पहचान की जाएगी। इसके लिए आर्थिक अपराध शाखा, साइबर क्राइम इकाइयों तथा अन्य विशेषीकृत एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर वित्तीय ट्रेल की वैज्ञानिक विवेचना की जाएगी। पुलिस का लक्ष्य केवल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनके आर्थिक साम्राज्य, संरक्षक तंत्र और सहयोगी नेटवर्क को ध्वस्त भी करना है।

डीजीपी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपराधिक मामलों की विवेचना 60 से 90 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। ई-साक्ष्य के माध्यम से डिजिटल व वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन,व न्यायालय में प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

लुधियाना की फैक्ट्री में जहरीली गैस से पिता-पुत्र समेत तीन की मौत

जागरण संवाददाता, लुधियाना: हैंडटूल बनाने वाली दीप्स टूल्स फैक्ट्री में रविवार रात करीब तीन बजे वेस्टेज टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से पिता-पुत्र समेत तीन श्रमिकों की मौत हो गई। दो कर्मियों की हालत गंभीर है। फैक्ट्री में न तो सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं थे और न ही नियमों का पालन हो रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा मानकों की अनदेखी व लापरवाही का मामला दर्ज किया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फैक्ट्री में रविवार रात को काम चल रहा था। यहां वेस्टेज टैंक की सफाई का ठेका मान सिंह के पास था। मान सिंह बेटे के साथ कई वर्षों से यह काम कर रहा था। मान सिंह बिना सेफ्टी किट पहने पाइप लेकर टैंक के भीतर उतरा और जहरीली गैस की चपेट में आ गया। बचाने के लिए बेटा अमित आगे बढ़ा तो गैस के प्रभाव से वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। दोनों को बचाने के लिए पहुंचा श्रीराम भी गैस की चपेट में आ गया।

राजौरी के जंगल में फिर गूंजी गोलियों की आवाज, सुरक्षाबल की घेराबंदी तेज

जागरण संवाददाता, राजौरी

▶ दो से तीन आतंकियों के जंगल में छिपने की आशंका

▶ आपरेशन शेरूवाली में सुरक्षाबलों के दो से तीन हजार जवान हैं तैनात

डोरी माल के जंगल की तरफ जाने वाले मार्ग पर तैनात जवान। जागरण

जम्मू-कश्मीर में राजौरी जिले के डोरी माल जंगल में सोमवार को बीच-बीच में गोलीबारी और धमाकों की आवाज गूंजती रहीं। सुरक्षाबल ने जंगल और आसपास क्षेत्र की घेराबंदी और निगरानी कड़ी कर दी है। बीते 10 दिन से जारी आपरेशन शेरूवाली में दो से तीन हजार सुरक्षाबल उतारे गए हैं। जंगल के चप्पे-चप्पे को खंगाला जा रहा है। सेना और पुलिस के आला अधिकारी पूरे आपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन-हेलीकाप्टर से तलाश जारी है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि घने जंगल में कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र अभियान के सामने चुनौती बने हुए हैं। स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को देने की अपील की गई है। सुरक्षा एजेंसियां जंगल के हर संभावित मार्ग और प्राकृतिक ठिकाने की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि आतंकियों को भागने का कोई मौका न मिल सके। दुर्गम इलाका होने के कारण जवानों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हेलीकाप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडो की मदद ली जा रही है। सेना हेलीकाप्टर की मदद से ऊपरी और दुर्गम क्षेत्रों की निगरानी कर रही है। ड्रोन कैमरों के जरिये जंगल के भीतर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आतंकियों के दो ठिकाने मिलने के बाद अभियान को दिशा मिल रही है। ड्रोन से मिली तस्वीरों व वीडियो फुटेज के आधार पर संभावित ठिकानों की पहचान कर रणनीति तैयार की जा रही है। आतंकियों तक पहुंचने के लिए पैरा कमांडो अभियान में शामिल किए हैं। जंगल के भीतर से आतंकियों के उपयोग का कुछ सामान भी बरामद किया गया है। बरामद सामग्री की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां उससे जुड़े तथ्यों का विश्लेषण कर रही हैं। आपरेशन अब निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा है। जंगल के आसपास क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।

सराहनीय

मोदी ने 'मन की बात' में गोंडा वन प्रभाग के अनूठे प्रयास को सराहा, संसाधनों के अभाव में खटिया के दम पर शुरू हुआ था रेस्क्यू मिशन

चारपाई से एंबुलेंस... 13 साल में बचाई 45 डाल्फिन की जान

वरुण यादव • जागरण

गोंडा : यह कहानी सिर्फ एक जलीय जीव को बचाने की नहीं, बल्कि संसाधनों के अभाव को मात देने वाली मजबूत इच्छाशक्ति की है। साल 2013 में जब मनकापुर की सरयू नहर में एक डाल्फिन फंसी, तो वन विभाग ने टर्टल सर्वाइवल एलायंस (टीएसए) से मदद मांगी। टीएसए के निदेशक भास्कर दीक्षित बताते हैं कि तब उनके पैर में प्लास्टर बंधा था और टीम के पास न कोई अनुभव था, न साधन। हार मानने के बजाय घाघरा के मछुआरों को बुलाया गया और एक पिकअप गाड़ी व गांव की 'चारपाई' (खटिया) के सहारे कड़ी मेहनत के बाद डाल्फिन को सुरक्षित निकालकर अयोध्या की सरयू नदी में छोड़ा गया। यहीं से शुरू हुआ बदलाव का वह सफर।

शुरुआती कुछ वर्षों तक डाल्फिन को बचाने के लिए इसी चारपाई और बाद में स्ट्रेचर का इस्तेमाल होता रहा। साल 2025 में 'नमामि गंगे' योजना के तहत इस मुहिम को पंख मिले। जनवरी 2026 में लांच हुई यह एंबुलेंस किसी चलते-फिरते आइसीयू जैसी है। बीते 13 वर्षों में चारपाई से एंबुलेंस तक के सफर के बीच गोंडा समेत नौ जिलों में 45 डाल्फिन का सफल रेस्क्यू किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई डाल्फिन एंबुलेंस का जिक्र करते हुए गोंडा के इस रेस्क्यू के बारे में मन की बात में बताया था। सरयू नहर में फंसी करीब 5.3 फीट लंबी और 26.4 किलो वजनी नर डाल्फिन को सकुशल बाहर निकाला गया था।

रेहराबाजार रेंज के ग्रामसभा इटईमैदा के घिरवनडीह में रेस्क्यू के बाद एंबुलेंस में डाल्फिन का तापमान चेक करते टीएसए के सदस्य। सौ. भाष्कर दीक्षित

मछली नहीं, समझदार स्तनधारी है डाल्फिन

डाल्फिन कोई मछली नहीं, बल्कि पानी में रहने वाला एक अत्यंत बुद्धिमान सामाजिक स्तनधारी (मैमल) जीव है। यह फेफड़ों से सांस लेती है, इसलिए इसे बार-बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। यह कछुओं के संरक्षण के लिए समर्पित वैश्विक संस्था 'टीएसए' और वन विभाग की देखरेख में सुरक्षित रह रही है।

सेतु निगम की तकनीकी टीम ने माना, पुल के पिलर में लगी सामग्री घटिया

जागरण संवाददाता, हमीरपुर

▶ संयुक्त प्रबंध निदेशक ने कहा- मौसम के अलर्ट के बाद नहीं कराना चाहिए था काम, पहली बार देखा ऐसा हादसा

▶ निर्माण सामग्री व टूटे पिलर के मलबे के नमूने लिए, आइआइटी कानपुर या बीएचयू की टीम करेगी जांच

बेतवा नदी पर 92 करोड़ रुपये से बन रहे 700 मीटर लंबे पुल के पांचवें पिलर के तीन टुकड़ों में टूटने और स्लैब गिरने से छह लोगों की मौत के मामले में भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी हैं। सोमवार दोपहर सेतु निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक (जेएमडी) मिथलेश कुमार के नेतृत्व में आई तीन सदस्यीय टीम ने तीन घंटे जांच के बाद माना कि पिलर में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हुआ है। कहा कि मौसम के अलर्ट बाद रात में काम नहीं कराया जाना चाहिए था। टीम ने सरिया, सीमेंट, बालू, गिट्टी व टूटकर गिरे पिलर के मलबे के नमूने लिए हैं।

जेएमडी मिथलेश कुमार ने कहा कि ऐसा हादसा जीवन में पहली बार देखा। नमूनों की जांच आइआइटी कानपुर या बीएचयू वाराणसी में कराई जाएगी। पुल के सभी 13 पिलर व स्लैब में लगी सामग्री की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट सप्ताह भर में मिलने की उम्मीद है। इसके बाद मौजूदा ढांचे पर पुल निर्माण बढ़ाने या नए सिर से दोबारा बनवाने पर निर्णय लिया जाएगा। टीम ने हर हिस्से की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी की। टीम में शामिल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर डिजाइन व महाप्रबंधक प्रेम सिंह ने सभी पिलर की स्थिति देखी। पिलर के टूटे तीनों टुकड़ों की जांच की।

Loot Blink
SABSE BADI DEALS, SABSE BADA FAAYDA!
JOIN INDIA'S MOST TRUSTED
DEALS CHANNEL
SAVE MORE SPEND LESS!
100% REAL DEALS
LIMITED TIME OFFERS
BEST PRICES GUARANTEED
SAB PE BADI BACHAT!
UP TO 90% DISCOUNT DEALS
BIGGEST DISCOUNTS • BEST BRANDS • LIMITED STOCK
LIMITED STOCK
JOIN KARO AUR PAO SABSE BADI LOOT DEALS!
boat Airdopes 141 TWS Earbuds
₹2,990
₹249
92% OFF
YOU SAVE ₹2,741
Noise Pulse 2 Smart Watch
₹4,999
₹349
93% OFF
YOU SAVE ₹4,650
iPhone 13 128GB
₹59,900
₹5,399
91% OFF
YOU SAVE ₹54,501
SAMSUNG
32" HD Smart TV
89% OFF
YOU SAVE ₹25,800
realme
Narzo N55 (6GB+128GB)
₹13,999
₹799
94% OFF
YOU SAVE ₹13,200
ASUS
Vivobook 15 (i3 12th Gen, 8GB/512GB SSD)
90% OFF
YOU SAVE ₹40,491
GREEN SOUL
Office Chair Ergonomic
₹14,999
₹1,499
92% OFF
YOU SAVE ₹17,500
SAMSUNG
980 500GB NVMe SSD
₹6,999
91% OFF
YOU SAVE ₹6,400
WILDCRAFT
Backpack
₹1,999
₹149
93% OFF
YOU SAVE ₹1,850
PHILIPS
Trimmer Series 3000
₹1,995
₹199
90% OFF
YOU SAVE ₹1,796
AGARO
Air Fryer 4.5L
₹6,999
₹699
90% OFF
YOU SAVE ₹6,300
PUMA
Men's Running Shoes
₹3,999
91% OFF
YOU SAVE ₹3,650
ZEBRONICS
Study Headphones with Mic
₹1,499
₹169
89% OFF
YOU SAVE ₹1,330
PORTABLE
Laptop Table Foldable
₹1,299
₹129
90% OFF
YOU SAVE ₹1,170
boAt
Stone 650 Bluetooth Speaker
₹3,999
₹199
95% OFF
YOU SAVE ₹3,800
UPTO 90% OFF ON TOP BRANDS
PRICE DROP ALERTS BE THE FIRST TO KNOW
100% GENUINE PRODUCTS
FAST DELIVERY ACROSS INDIA
DEALS ITNI BADI, KI CHOOK GAYE TO PACHTAOGE!
ABHI JOIN KARO AUR LOOTNA SHURU KARO!
JOIN OUR WHATSAPP CHANNEL
Instant Deal Alerts
Exclusive Offers
Limited Stock Updates
CLICK HERE
JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL
Latest Deals & Offers
Price Drops Alerts
Limited Time Offers
CLICK HERE
SAVE TIME SHOP SMART
SAVE MONEY LIVE BETTER
SMART CHOICES. BRIGHTER FUTURE!
SHOP SMART. SAVE BIG. SHINE BRIGHT.
JOIN 1 LAKH+ SMART SHOPPERS & SAVE THOUSANDS EVERY MONTH!

17 के स्थान पर रेलवे के लोगो में 18 सितारे दिखने लगे। लोगो में इस बदलाव का मुख्य कारण देश में 18वें रेलवे जोन के रूप में 'साउथ कोस्ट रेलवे' (एससीओआर) का गठन होना है। रेलवे की परंपरा रही है कि लोगो में मौजूद सितारों की संख्या उसके कुल जोन को दर्शाती है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार, 02 जून, 2026

न्यूज गैलरी

आरोपित अधिकारी के घर से करोड़ों की नकदी व गहने बरामद

अहमदाबाद : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ऊर्जा विभाग के एक प्रथम श्रेणी अधिकारी को सोलर पैनल के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बदले पांच लाख रुपये से अधिक की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ घटिया पैनल व प्रोजेक्ट को स्थल के निरीक्षण के बिना ही प्रमाण पत्र देने के बदले लाखों रुपये की घूस मांगने की शिकायत की गई थी। एसीबी की निदेशक भारती पंड्या ने बताया कि उद्योग भवन के मुख्य इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत प्रथम श्रेणी अधिकारी अश्विन बी चौधरी के खिलाफ सोलर पैनल को एनओसी देने के बदले लाखों की रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। (राब्यू)

गोवा पुलिस ने हेरोइन तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़

पणजी : गोवा पुलिस ने सोमवार को एक अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। मामले में मुख्य आरोपित इखलाक अहमद को बहराइच से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले पुलिस ने तस्करी गिरोह में शामिल तीन नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि 20 मई को मांडोवी पुल के नीचे बेतिम जेटी पर थोक मछली बाजार के पास छापेमारी के बाद जांच शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप नेपाली नागरिक 36 वर्षीय अर्जुन बिस्वोकर्मा और 25 वर्षीय चेतकंत ओली को 8.88 लाख मूल्य की 39.88 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद नेपाल निवासी नारीशोर भंडारी को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि आरोपितों ने मोबाइल के जरिए बहराइच स्थित एक आपूर्तिकर्ता को हेरोइन का आर्डर दिया। (प्रेट्र)

किसकी अनुमति से तोड़ा गया बरगी बांध हादसे वाला क्रूज

जबलपुर : दिल दहला देने वाले बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे को लेकर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी के एकल न्यायिक जांच आयोग के समक्ष सोमवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। इसके जरिये सवाल किया गया है कि क्रूज को तोड़ा क्यों गया, क्या किसी जिम्मेदार विशेषज्ञ ने इसकी अनुमति दी थी। इसी तरह मौसम विभाग एकमात्र ऐसा जिम्मेदार विभाग हैं, जो ज्योतिष शास्त्र की भांति पहले ही जान जाता है कि भविष्य में मौसम का रुख क्या होने वाला है। मौसम विभाग द्वारा रेलवे, एविएशन आदि को भी इस तरह की जानकारी दी जाती है। जनसामान्य तक भी इस तरह की जानकारी सूचना माध्यमों के जरिये पहुंचाई जाती है। मौसम विभाग ने यह जानकारी एमपी टूरिज्म को दी थी की नहीं, यह जांच का विषय है। (नईदुनिया)

दो-तीन दिनों में केरलम में दस्तक दे सकता है दक्षिण-पश्चिम मानसून

पूर्वानुमान ▶ मौसम विभाग ने कहा- स्थितियां मानसून के आगमन के अनुकूल

आमतौर पर एक जून को केरल पहुंचता है दक्षिण पश्चिम मानसून

नई दिल्ली, प्रेट्र : मौसम विभाग ने सोमवार को भविष्यवाणी की कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले दो से तीन दिनों में केरलम में दस्तक दे सकता है। स्थितियां मानसून के आगमन के अनुकूल हैं। इसके साथ ही आइएमडी ने इस सप्ताह के लिए केरलम के अलप्पुझा, कोट्टायम समेत सात जिलों में आरेंज अलर्ट जारी किया है और इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

आमतौर पर केरलम में एक जून के आसपास मानसून पहुंचता रहा है। आइएमडी ने पहले 26 मई को केरलम में मानसून के आगमन की भविष्यवाणी की थी, लेकिन मानसून में देरी हुई। विभाग ने 29 मई को कहा था कि यह अगले सप्ताह पहुंच सकता है। साथ ही कहा था कि इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा होगी। इसकी वजह अलनीनो की स्थिति का उभरना हो सकता है, जो भारत में मानसून के दौरान कम वर्षा का कारण बनता है।

मानसून की आहट : केरल के तिरुअनंतपुरम में मुल्लूर स्थित आजीमाला शिव स्थल के ऊपर रविवार को बादल छाए रहने के दौरान इकट्ठा हुए लोग। प्रेट्र

आइएमडी ने कहा- "दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं जो दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप द्वीप समूह, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों में आ सकता है।"

यह अनुमान लगाया गया है कि इस अवधि के दौरान दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों में भी मानसून का आगमन हो सकता है।

आइएएनएस के अनुसार, मौसम विभाग ने केरलम के अलप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम को बुधवार और गुरुवार को आरेंज अलर्ट पर रखा है, जबकि पत्तनमथिट्टा और कोझीकोड गुरुवार को अलर्ट पर रहेंगे।

मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन जिलों के कुछ स्थानों पर कम समय में 11 से 20 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। ऐसी सूरत में न केवल बाढ़ के हालात पैदा होते हैं बल्कि यह पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का जोखिम भी बढ़ा देता है। इससे लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा राज्य के कई अन्य जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किए गए हैं, जोकि राज्य के बड़े हिस्सों में भारी बारिश की संभावना को दर्शाते हैं।

पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया के घर पर पुलिस का छापा, नहीं आए हाथ

▶ थाने से आरोपित को छुड़ाने के प्रयास के मामले में मजीठिया सहित 60 पर एफआइआर, पुलिस को डराने धमकाने का आरोप

अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करने के लिए अमृतसर में उनके निवास पर बड़ी संख्या में पहुंचा पुलिस बल। राघव शिकारपुरिया

जागरण संवाददाता, अमृतसर

पंजाब पुलिस ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के घर पर छापा मारा। यह छापेमारी मजीठा थाने से आरोपित को छुड़ाने के प्रयास में दर्ज मामले को लेकर की गई। हालांकि, मजीठिया घर पर नहीं मिले। पुलिस के अनुसार मजीठिया लोगों की उस गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा थे, जिसने मजीठा पुलिस थाने में हिरासत में लिए गए जोबनप्रीत सिंह को छुड़ाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले में मजीठिया व उनके 60 से ज्यादा समर्थकों पर एफआइआर दर्ज की है। उधर, सरकार ने सोमवार देर शाम अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी सोहेल मीर कासिम का तबादला कर दिया।

सोमवार को मजीठिया को गिरफ्तार करने के लिए एसएसपी सोहेल मीर कासिम ने 10 पुलिस टीमें तैयार करके रवाना कीं। पुलिस मजीठिया की दो कोठियों में पहुंची, लेकिन वह नहीं मिले।। वहीं, शिअद के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने इसे बदले की राजनीति करार दिया। दरअसल, निकाय चुनाव के मतगणना वाले दिन गत शुक्रवार को मजीठिया के कुछ समर्थकों ने मजीठा में एक बूथ के बाहर जमकर हंगामा किया था। इस मामले में शनिवार को गांव सोइयां कलां के जोबनप्रीत को गिरफ्तार किया गया। रविवार को थाने में जोबनप्रीत से पूछताछ की जा रही थी। इसके विरोध में मजीठिया 60-70 समर्थकों के साथ थाने के बाहर धरना देने पहुंच गए और जबरदस्ती थाने में घुस गए। आरोप है कि उन्होंने वहां पुलिसकर्मियों को डराया-धमकाया, थाने में हंगामा किया। जोबनप्रीत से पुलिसकर्मी पूछताछ कर रहे थे, जहां से उसे उन्होंने बाहर निकाल लिया। इसके बाद मजीठिया समर्थकों के साथ वहां से चले गए। हालांकि, जोबनप्रीत को पुलिस ने वहीं पकड़ लिया।

'अस्थायी कर्मियों से नियमित कर्मियों की तरह काम लेकर अधिकार छीनना गलत'

▶ सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों के भत्तों व सेवानिवृत्ति लाभों में भारी असमानता का लिया संज्ञान

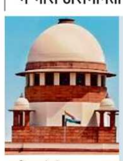

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

कहा - राज्य तक दशकों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अधर में नहीं छोड़ सकता

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोई भी सरकार या विभाग अस्थायी कर्मचारियों से स्थायी कर्मियों की तरह काम लेकर उन्हें उनके हक और पेंशन से वंचित नहीं रख सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समान काम के बदले अधिकार छीनना नाइंसाफी है। राज्य एक 'आदर्श नियोक्ता' है और वह प्रशासनिक ढिलाई के चलते दशकों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अधर में नहीं छोड़ सकता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें डाक विभाग में दशकों तक नाइट गार्ड के रूप में सेवाएं देने वाले अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से इन्कार कर दिया गया था।

पेंशन खैरात नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार : सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 के एक ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन कोई खैरात या इनाम नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी की वर्षों की कड़ी मेहनत की कमाई है। संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत यह संपत्ति के समान एक 'संवैधानिक अधिकार' है। विभाग की सुस्ती या प्रशासनिक विफलता के कारण किसी भी कर्मचारी के इस मौलिक और कानूनी अधिकार को छीना या निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता।

तीन महीने में भुगतान करने का सख्त निर्देश : सुप्रीम कोर्ट ने डाक विभाग की 1991 की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य ही अस्थायी श्रमिकों को धीरे-धीरे नियमित ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के समकक्ष लाना था।

हिमाचल में एंट्री टैक्स के विरोध में पंजाब के एंट्री प्वाइंट पर जाम

जागरण टीम, रूपनगर

हिमाचल प्रदेश द्वारा अन्य राज्यों के वाहनों पर लगाए गए एंट्री टैक्स के खिलाफ सोमवार को पंजाब के 56 एंट्री प्वाइंट पर चक्का जाम किया गया। किसान संगठनों, ट्रांसपोर्टरों, टैक्सी यूनियनों और व्यापारियों के संयुक्त मोर्चे ने सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक प्रदर्शन किया, जिस कारण दोनों राज्यों की सीमा पर वाहनों की कतारें लग गईं।

पंजाब मोर्चा के संयोजक गौरव राणा ने बताया कि रूपनगर जिले के छह एंट्री प्वाइंट पर लगभग 20 से 25 हजार लोग फंसे रहे। हालांकि, एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को जाम से मुक्त रखा गया। इन दिनों पर्यटन सीजन चरम पर है। ऐसे में रोजाना हजारों पर्यटक हिमाचल में आ-जा रहे हैं।

रूपनगर जिले के कीरतपुर साहिब-मनाली हाईवे और ऊना-चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित एंट्री प्वाइंट पर साढ़े तीन घंटे बाद रास्ता खोला गया।

धरना समाप्त होने के बाद ट्रैफिक सामान्य होने में लगभग पौन घंटा लगा। इस दौरान वाहनों को बिना टोल अदा किए निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान उत्तर भारत के महत्वपूर्ण कीरतपुर साहिब-मनाली और ऊना-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा।

इसी तरह मैहतपुर प्रवेश द्वार पर ऊना से पंजाब जाने वाले वाहनों को रोका गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार एंट्री टैक्स के नाम पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रही है। प्रशासन ने स्वारघाट क्षेत्र में यातायात डायवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अन्य मार्गों पर भी धरना देकर आवाजाही बाधित कर दी।

इसी प्रकार, रूपनगर-नालागढ़ ढेरोवाल एंट्री प्वाइंट पर भारतीय किसान यूनियन बहराम, शेर-ए-पंजाब किसान यूनियन और बिक्को-घनौली क्षेत्र के किसानों ने भी चक्का जाम रखा। गौरव राणा और कीर्ति किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीर सिंह बड़वा ने चेतावनी दी कि यदि जब तक एंट्री टैक्स समाप्त नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

▶ सुबह 11 बजे से ही हिमाचल आने-जाने वाले वाहन रोके, चार घंटे फंसे रहे हजारों लोग

▶ प्रदर्शनकारियों ने दी चेतावनी, टैक्स वापस न लेने तक जारी रहेगा आंदोलन

निहंग संगठन बोले, राहत नहीं तो खालसा राज टैक्स लागू करेंगे

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंजाब सरकार रेसिप्रोकल (समानांतर) टैक्स लगाने के दावों के बावजूद लोगों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। निहंग संगठनों ने कहा कि यदि पंजाब सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो बुधवार से खालसा राज टैक्स लागू करने का निर्णय लिया जा सकता है।

हिमाचल सरकार की तरफ से लगाए एंट्री टैक्स के विरोध में रूपनगर जिले के कीरतपुर साहिब-मनाली नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर रोष प्रदर्शन करते हुए विभिन्न संगठनों के सदस्य। जागरण

बहुत कम समय में उड़ान भरता है दिव्यास्त्र एमके-1 ड्रोन

प्रथम पृष्ठ से आगे

एक और महत्वपूर्ण बदलाव इसकी मोबाइल लांच क्षमता है। इसे किसी ट्रक या अन्य वाहन पर लगाकर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। युद्ध या सीमा पर हालात तेजी से बदलने पर सेना जरूरत के मुताबिक किसी भी स्थान से इसे तुरंत तैनात कर सकेगी। परीक्षण के दौरान कई बार लांचिंग कर यह भी दिखाया गया कि ड्रोन को तैयार करने और उड़ान भराने में बहुत कम समय लगता है।

होवरित के तरकश में कई और 'ड्रोनास्त्र' : दिव्यास्त्र एमके-1 के सफल परीक्षण के साथ चर्चा में आई स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरित केवल एक ड्रोन परियोजना तक सीमित नहीं है। कंपनी कई तरह के सामरिक और निगरानी ड्रोन विकसित कर रही है, जिनका उपयोग सेना और सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, होवरित फिलहाल दिव्यास्त्र एमके-2 पर भी काम कर रही है। यह लंबी दूरी का यूएवी होगा, जिसकी संभावित परिचालन क्षमता करीब 2000 किलोमीटर तक बताई गई है। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में निगरानी और मिशन संचालन की क्षमता बढ़ सकती है। होवरित के पोर्टफोलियो में बाज, आंख और रफ्तार नाम के ड्रोन भी शामिल हैं। बाज ड्रोन 15 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और लगभग 45 मिनट तक हवा में रह सकता है। यह अधिकतम 15 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। वहीं, रफ्तार ड्रोन की खासियत इसका वर्टिकल टेक-आफ है। इसे सीधे जमीन से हवा में लांच किया जा सकता है। यह करीब 90 मिनट तक उड़ान भरते हुए 45 किलोमीटर के दायरे में निगरानी मिशन संचालित कर सकता है। कंपनी का आंख ड्रोन ऊंचाई वाले इलाकों में निगरानी के लिए विकसित किया गया है। इसे 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है और यह लगभग 45 मिनट तक 12 किलोमीटर के क्षेत्र में निगरानी रखने में सक्षम है।

ऋण धोखाधड़ी में आरकाम के पूर्व एमडी किए गए गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र: सीबीआइ ने सोमवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकाम) के पूर्व ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला को ऋण धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरकाम द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को पहुंचाए गए 2,929.05 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी में अमिताभ झुनझुनवाला की संलिप्तता पायी गई है।

ईडी द्वारा की जा रही एक जांच के सिलसिले में झुनझुनवाला पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा पेशी वारंट जारी किए जाने के बाद सीबीआइ द्वारा झुनझुनवाला को मुंबई लाया गया। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद सीबीआइ ने औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद, आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। सीबीआइ के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पुलिस हिरासत याचिका पर मंगलवार सुनवाई होगी।

सच की तलाश में सीबीआइ ने फंदे पर लटकाया 80 किलोग्राम वाला त्विषा शर्मा का पुतला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल

▶ सीबीआइ ने सोमवार को कराया क्राइम सीन रीक्रिएट

▶ गिरिबाला व समर्थ के बयान में विरोधाभास, जांच एजेंसी ने कराया क्रास-वेरिफिकेशन

माडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बहुचर्चित मामले की जांच कर रही सीबीआइ ने सोमवार को क्राइम सीन रीक्रिएट कराया। सच की तलाश में सीबीआइ ने त्विषा की ससुराल में डमी टेस्ट किया। इस दौरान 80 किलोग्राम वाले एक पुतले को फंदे पर लटकाया गया। पुतला लटकाने के बाद सीबीआइ के अधिकारियों ने सबसे पहले समर्थ को बुलाया और उस दिन के घटनाक्रम की क्रमवार जानकारी ली। समर्थ ने बताया कि वह ऊपर आया तो त्विषा को फंदे पर लटका देखा। इसके बाद उसे उतारा। सीबीआइ ने समर्थ से डमी को उसी तरह से उतरवाया, जैसे उसने त्विषा को उतारने का दावा किया था। काफी देर तक समर्थ से घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेने के बाद उसे नीचे दूसरे कमरे में भेजा गया, उसके बाद गिरिबाला को बुलाया और उनसे भी पूरा घटनाक्रम जाना गया। इस दौरान गिरिबाला और समर्थ के कथन में विरोधाभास होने के कारण सीबीआइ के अधिकारियों ने दोनों को आमने-सामने बैठाकर क्रास-वेरिफिकेशन भी किया। अधिकारियों ने समर्थ और गिरिबाला से घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना न देने और सीसीटीवी तकनीशियन को बुलाने के कारणों पर सवाल किए। करीब तीन घंटे तक परीक्षण और पूछताछ के बाद सीबीआइ टीम दोनों आरोपितों को वापस ले गई।

भोपाल में त्विषा शर्मा मौत प्रकरण में सोमवार को आरोपित गिरिबाला सिंह के आवास पर अपराध का दृश्य रीक्रिएट करते सीबीआइ के अधिकारी। मौके पर त्विषा के पति समर्थ सिंह (धारीदार टी-शर्ट में) भी दिख रहा। प्रेट्र

सीबीआइ में लंबे समय तैनात रहे एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया का का उद्देश्य यह जांचना रहता है कि क्या वह कुंदा इतना भारी वजन सहने में सक्षम था और क्या उस लिगेचर से वास्तव में फंदा बनाया जा सकता है। बता दें कि त्विषा का शव 12 मई को उसकी ससुराल में पाया गया था।

ठगी में 1.47 करोड़ गंवा 28 दिन डिजिटल अरेस्ट रहा बुजुर्ग

नई दिल्ली, एएनआइ : गुजरात से साइबर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां 72 वर्षीय एक व्यक्ति को हाल ही में 1.47 करोड़ रुपये की भारी राशि की ठगी का शिकार होना पड़ा। पीड़ित को लगभग 28 दिनों तक "डिजिटल अरेस्ट" का सामना करना पड़ा। इसने जांच एजेंसियों के बीच व्यापक चिंता पैदा कर दी है।

गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा विंग ने इस बुजुर्ग के मामले का उल्लेख किया, जिसे धोखेबाजों ने पुलिस, सीबीआइ और ईडी जैसी विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों के रूप में पेश किया। साइबर विंग के अधिकारियों ने बताया कि वीडियो काल और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करते हुए धोखेबाजों ने "पीड़ित को गंभीर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक विस्तृत कहानी बनाई।" धोखेबाजों ने दावा किया कि व्यक्ति के डिजिटल क्रेडेंशियल्स से समझौता किया गया है और उन्हें आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा गया है।

विडंबना

खेल निदेशालय में 10 वर्षों से बतौर सफाईकर्मी काम कर रहीं राष्ट्रीय स्तर की दिव्यांग खिलाड़ी, 2024 में आयोजित थ्रो बाल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किया था झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व

सम्मान की जगह झाड़ू थामे खड़ी हैं स्वर्ण पदक विजेता

दिवाकर सिंह • जागरण

रांची : झारखंड के खेल तंत्र की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो खिलाड़ियों के सम्मान और उनके भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े करती है। जिस खेल निदेशालय का काम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और सम्मान देना है, उसी परिसर में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाली 29 वर्षीय दिव्यांग खिलाड़ी सुनीता कुमारी पिछले 10 वर्षों से झाड़ू लगाकर अपनी जीविका चला रही है।

सुनीता ने वर्ष 2024 में थ्रो बाल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की पैरा वालीबाल प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लेकिन, इन उपलब्धियों के बावजूद उन्हें न तो कोई विशेष सम्मान मिला और न ही खेल उपलब्धियों के अनुरूप अवसर। बकौल सुनीता, माता-पिता के निधन के बाद से वह भाई-भाभी के साथ रहती हैं और जीवनयापन के लिए 2016 से खेल निदेशालय में सफाई का काम करती हैं। बचपन से ही खेल में दिलचस्पी रही है।

खेल निदेशालय परिसर में झाड़ू लगाती सुनीता कुमारी। जागरण

काम के साथ-साथ उन्होंने विधिवत खेल का प्रशिक्षण भी लिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। अब उनका सपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां राह में खड़ी हैं। 2024 में तमिलनाडु में टीम के साथ पारा नेशनल वालीबाल चैंपियनशिप और 2025 में मेरठ में संपन्न नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीत चुकीं सुनीता के अनुसार, उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी खेल में कोई खिलाड़ी पदक जीतता है तो उसे पदक के अनुसार कैश अवार्ड दिया जाता है। वहीं, सम्मान के साथ खेल कोटा के तहत नियुक्ति भी होती है। हालांकि, झारखंड में राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिव्यांग खिलाड़ी पदक जीतता है तो उसे न तो कैश अवार्ड मिलता है और न ही उसे सीधी नियुक्ति मिलती है। पड़ोसी राज्य बिहार में एक नियम लागू है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ।

3,600 रुपये के लिए फास्ट फूड वाले ने की महिला कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

जागरण संवाददाता, मेरठ

▶ आरोपित ने बीयर पिलाई और ईंट से सिर पर वार कर नाले में दिया धक्का

▶ डेढ़ माह बाद पुलिस ने हत्यारोपित को पकड़ बरामद किया अनुष्का का शव

3,600 रुपये की उधारी नहीं चुकाने पर फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले ने राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल के सिर में ईंट से वार कर नाले में धक्का दे दिया। इसके बाद चंडीगढ़ भाग गया। डेढ़ माह बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर रविवार को नाले से अनुष्का का सड़ा-गला शव बरामद कर लिया।

सोमवार सुबह स्वजन ने शव को अनुष्का का न बताकर पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा कर दिया। अधिकारियों के समझाने पर वह माने और डीएनए रिपोर्ट जल्द मंगाने की मांग की। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव लेकर गांव चले गए। इससे पहले हत्या के आरोप में आरोपित 17 साल जेल में बंद रहा था। छह माह पहले ही सजा पूरी करने के बाद जेल से छूटा था।

अनुष्का। फाइल

नेमपाल की 17 वर्षीय बेटी अनुष्का राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी थी। अनुष्का ने इसी वर्ष कृष्णा पब्लिक स्कूल से 12वीं पास की थी। गांव से स्कूल और अभ्यासस्थल तक आने-जाने में दिक्कत के चलते वह नौ माह से छोटे भाई अनमोल के साथ दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित एक मकान में किराए पर रह रही थी। आठ मार्च को अनुष्का ने बताया था कि वह गाजियाबाद में कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। इसके बाद उसने बताया कि जीतने पर 60 हजार रुपये पुरस्कार में मिले थे। अनुष्का ने स्वजन को बताया कि सहेली की मां बीमार है। रुपये उसे दे दिए। 16 अप्रैल को अनुष्का का मोबाइल बंद हो गया। 28 अप्रैल को गुमशुदगी दर्ज कराई गई। एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर से अनुष्का की अंतिम लोकेशन देहरादून निवासी श्याम धानक के साथ मिली। वह चंडीगढ़ में रह रहा था।

1968 में देश में पहली बार त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया था। इसके बाद 1986 की शिक्षा नीति में भी इसे स्थान मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के तहत इसमें कुछ अहम बदलाव किए गए हैं।

त्रिभाषा फार्मूला सर्वसमावेशी, किसी भाषा को थोपने की कोशिश नहीं : शास्त्री

देवेंद्र दीक्षित • जागरण

जागरण विमर्श

नोएडा : भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर चमू कृष्ण शास्त्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू किए जा रहे त्रिभाषा फार्मूला को लेकर व्याप्त आशंकाओं को निराधार बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था किसी राज्य या समुदाय पर कोई भाषा थोपने का प्रयास नहीं है। उनका कहना है कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषाई विविधता को सशक्त बनाने और विद्यार्थियों को बहुभाषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पद्मश्री प्रोफेसर चमू कृष्ण शास्त्री सोमवार को दैनिक जागरण के नोएडा कार्यालय में जागरण विमर्श के दौरान त्रिभाषा फार्मूले को लेकर प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बहुभाषी देश में विभिन्न भाषाओं को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। एनईपी-2020 इसी सोच को आगे बढ़ाती है। त्रिभाषा फार्मूला कोई नई व्यवस्था नहीं है। यह पहले भी लागू रहा है। देश के अनेक विद्यालयों में छात्र हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाओं का अध्ययन करते रहे हैं। त्रिभाषा फार्मूला पहली बार वर्ष 1968 में लागू किया गया था, जिसके बाद 1986 की शिक्षा नीति में भी इसे स्थान मिला। हालांकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

शास्त्री के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्यों और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को अधिक महत्व देती है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ)-2023 में भाषाओं के लिए आर-1, आर-2 और आर-3 की अवधारणा अपनाई गई है।

- भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चमू कृष्ण शास्त्री ने त्रिभाषा फार्मूला को लेकर दूर किया भ्रम
- बोले, दक्षिण भारत में जबरन हिंदी थोपने के आरोप केवल राजनीतिक, वहां हिंदी के प्रति रुचि

प्रो. चमू कृष्ण शास्त्री।

देश में बोली जाती हैं 1369 भाषाएं

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 1369 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें 121 भाषाओं के बोलने वालों की संख्या एक लाख से अधिक है। ऐसे में देश की भाषाई विविधता को संरक्षित और प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उनके अनुसार, त्रिभाषा फार्मूला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो भारतीय भाषाओं को शिक्षा, तकनीक, रोजगार और सार्वजनिक जीवन से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

आर-1 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, आर-2 आर-1 से अलग कोई दूसरी भाषा और आर-3 पहली दो भाषाओं से अलग तीसरी भाषा होगी। भारतीय मूल की दो भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ाने का प्रविधान किया गया है। छठी से दसवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा।

दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में त्रिभाषा फार्मूला को लेकर हो रहे विरोध को लेकर पूछे गए सवाल पर चमू कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वहां इसका विरोध मुख्य रूप से राजनीतिक स्तर पर देखने को मिलता है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिंदी सीख रहे हैं और लोगों में हिंदी के प्रति रुचि मौजूद है। एक सवाल पर कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं ली जा सकती हैं। संकुल स्तर पर उपलब्ध शिक्षकों का भी उपयोग किया जा सकता है।

विदेशी भाषाओं के अध्ययन पर संभावित प्रभाव के संबंध में शास्त्री ने कहा कि सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी भारतीय भाषाएं ही सीखते हैं। फ्रेंच, जर्मन या अन्य विदेशी भाषाओं का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे छात्र पहले की तरह अतिरिक्त भाषा के रूप में इन भाषाओं का अध्ययन जारी रख सकेंगे।

एआइ के दौर में त्रिभाषा फार्मूला की प्रासंगिकता पर उनका कहना था कि एआइ केवल एक तकनीकी उपकरण है। भारतीय भाषाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ना समय की आवश्यकता है। भारतीय भाषाओं में कोडिंग, साफ्टवेयर और तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भाषाई समृद्धि और तकनीकी प्रगति साथ-साथ आगे बढ़ सकें।

तेलंगाना में अब श्रमिकों को कैश पेमेंट पर रोक, गिग वर्कर्स को न्यूनतम वेतन का सुरक्षा कवच

हैदराबाद, प्रेट्र : तेलंगाना सरकार ने राज्य में श्रमिकों को नकद भुगतान (कैश पेमेंट) पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए आदेश के तहत अब नियोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर (एनईएफटी/आरटीजीएस/आइएमपीएस) या बैंक चेक के जरिये ही वेतन देना होगा। इस नीति का उद्देश्य वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाना और श्रम निरीक्षकों के लिए एक पुख्ता रिकार्ड तैयार करना है। साथ ही गिग वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया गया है। सरकार ने केंद्र के 'वेतन संहिता, 2019' के प्रविधानों को लागू कर 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948' को निरस्त कर दिया है। इस नए नियम के तहत सभी गैर-कृषि, वाणिज्यिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को चार कौशल श्रेणियों (अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल) में बांटा गया है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने कुर्क की 1,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति

कुर्क की गई संपत्तियों में उत्तरी गोवा का प्रतिष्ठित वेस्टिन होटल भी शामिल

3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • रायपुर

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के संयुक्त बाजार मूल्य वाली संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों का रजिस्ट्री मूल्य करीब 200 करोड़ रुपये बताया गया है। कुर्क संपत्तियों में उत्तरी गोवा का प्रतिष्ठित वेस्टिन होटल भी शामिल है। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने तीन अलग-अलग अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए हैं। 3,200 करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपितों की संख्या अब 85 हो गई है। बता दें कि पूरक आरोपपत्र में विजय भाटिया, टी. भुवनेश्वर राव, प्रोबीर शर्मा और निखिल चंद्रकार को नए आरोपित के रूप में शामिल किया गया है।

ईडी के अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 के बीच होटल कारोबारी अनवर ढेबर और सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के नेतृत्व में संचालित शराब सिंडिकेट ने राज्य की उत्पाद शुल्क व्यवस्था में व्यवस्थित हेरफेर कर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की। शराब की खरीद दरों में कृत्रिम वृद्धि, अवैध शराब निर्माण और एफएल-10ए लाइसेंसधारियों से कमीशन वसूली के जरिए 2,883 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता की गई। ईडी के पहले कुर्की आदेश में अनवर ढेबर और विकास अग्रवाल से जुड़ी अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। ईडी ने विकास अग्रवाल को सिंडिकेट का वित्तीय प्रबंधक बताया है, जो शराब भट्टियों और लाइसेंसधारियों से कमीशन वसूलकर अनवर ढेबर तक धन पहुंचाता था।

भूपेश बघेल के बेटे पर गंभीर आरोप

ईडी का दावा है कि नकदी को कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के निर्देश पर भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया था। तीसरे आदेश में तीन एफएल-10ए लाइसेंसधारी कंपनियों के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड जब्त किए गए हैं। जांच में पता चला कि इन कंपनियों को अपने मुनाफे का 50 से 60 प्रतिशत हिस्सा सिंडिकेट को देने के लिए मजबूर किया गया था, जिसकी राशि लगभग 51 करोड़ रुपये है।

घोटाले की रकम से खरीदा था होटल

रायपुर स्थित ढेबर सिटी होम्स सहित विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से खरीदी गई कथित बेनामी जमीनों को भी कुर्क किया गया है, जिसका मूल्य लगभग 30 करोड़ रुपये है। दूसरे आदेश में अंजुना (उत्तरी गोवा) स्थित प्रीमियम वेस्टिन होटल को कुर्क किया गया है। जांच में पाया गया कि करीब 110 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा गया यह होटल कथित तौर पर शराब घोटाले से अर्जित नकदी के जरिए अधिग्रहित किया गया था। इस होटल के निदेशक राहुल अग्रवाल और विजय अग्रवाल है।

महादेव सट्टा एप केस

666 करोड़ के फ्रीज शेयरों को नहीं मिली बेचने की अनुमति

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • रायपुरः महादेव आनलाइन सट्टा एप से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपितों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायालय ने ईडी द्वारा फ्रीज किए गए 666 करोड़ रुपये के शेयरों में ट्रेडिंग की अनुमति देने से संबंधित याचिका खारिज कर दी है। साथ ही 13 कंपनियों में किए गए संदिग्ध निवेश पर लगी रोक जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान आरोपितों ने दलील दी कि बाजार में गिरावट के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है, अतः शेयर बेचने की अनुमति दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को नहीं स्वीकारा। ईडी के अनुसार, महादेव सट्टा नेटवर्क से अर्जित अवैध धन को वैध दिखाने के लिए दुबई के रास्ते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) का इस्तेमाल किया गया। जांच में सामने आया है कि 666 करोड़ रुपये भारतीय शेयर बाजार में लगाए गए, जिनका संबंध मनी लांड्रिंग से है। यह रकम हवाला नेटवर्क के जरिए पहले विदेश भेजी गई, फिर मुखौटा कंपनियों के जरिये विदेशी निवेश के रूप में भारत लाई गई। ईडी ने बताया कि दुबई में बैठे कोलकाता के हवाला कारोबारी हरिशंकर टिबरेवाल और गोविंद केड़िया इस नेटवर्क के प्रमुख किरदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संस्थान की न्यायाधिकरण में अदालती शुल्क में छूट संबंधी याचिका पर उठाए सवाल

- पूछा, कौन सा कानून आपको अदालती शुल्क से छूट की देता है अनुमति
- गुजरात हाई कोर्ट ने भी कहा था, वक्फ संस्थाएं अदालती शुल्क से मुक्त नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य वक्फ न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाही में वक्फ संस्थानों को अदालती शुल्क के भुगतान से छूट देने के कानूनी आधार पर सवाल उठाया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने ये टिप्पणियां गुजरात हाई कोर्ट के दिसंबर, 2025 के उस आदेश के विरुद्ध दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें अदालती शुल्क नहीं देने के कारण वक्फ मुकदमों को खारिज करने का फैसला बरकरार रखा गया था। हाई कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि वक्फ संस्थाएं, राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष अदालती शुल्क देने से मुक्त नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील एजाज मकबूल ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा। लेकिन जस्टिस नरसिम्हा ने उनसे अदालती शुल्क से छूट के दावे का आधार पूछा, 'छूट कैसे मिल सकती है? वह कौन सा कानून है जो आपको अदालती शुल्क से छूट मांगने की अनुमति देता है?' मकबूल ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से जवाब दाखिल करेंगे और सुनवाई सात अगस्त तक स्थगित करने का आग्रह किया। गुजरात हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर, 2025 को वक्फ संस्थानों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिनमें गुजरात राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनमें अपर्याप्त अदालती शुल्क के कारण वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों पर कार्यवाही को अस्वीकार कर दिया गया था। अदालत ने कहा था कि वक्फ अधिनियम की धारा-83 के तहत कार्यवाही के लिए अदालती शुल्क के भुगतान से वक्फ संस्थानों को छूट हासिल नहीं है।

104 वर्षीय वृद्ध से फर्जीवाडा करने वाले लोन मैनेजर को तीन वर्ष की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर

- छत्तीसगढ़ के मुंगेली का मामला, 104 वर्षीय वृद्ध की जमीन पर लिया था केसीसी लोन

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 104 वर्षीय वृद्ध की 20 एकड़ भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक से नौ लाख 50 हजार रुपये के फर्जी केसीसी लोन लिए जाने के मामले में एक्सिस बैंक के तत्कालीन लोन मैनेजर सुमन कार्तिक रथ सहित चार लोगों को धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया है। न्यायालय ने दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

आरोपितों ने 13 मार्च 2018 को सरकंडा स्थित एक्सिस बैंक में वृद्ध की भूमि पर केसीसी लोन पास करा लिया और रकम आपस में बांट ली। पीड़ित के पोते ने जब आनलाइन रिकार्ड देखा तो उक्त भूमि बैंक के पास बंधक दिखी। पोते की शिकायत पर सरकंडा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुप तिग्गा ने परीक्षण में पाया कि आधार कार्ड में लगी फोटो पीड़ित के फोटो से अलग है। असली आधार कार्ड के अनुसार, पीड़ित का जन्म वर्ष 1934 था, जबकि फर्जी आधार कार्ड में जन्म का वर्ष 1969 और वोटर आइडी में 1971 दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा, इसे नग्न आंखों से देखने पर भी साफ पता चलता है कि दस्तावेज की कूटरचना की गई है।

असम में एकतरफा प्यार में मुस्लिम किशोर ने की आसू नेता की हत्या

- माधुर्य की बहन ने ठुकरा दिया था प्रेम का प्रस्ताव
- बहन को बचाने में गई जान, हमलावर आशिक मुठभेड़ में ढेर

नलबाड़ी, प्रेट्रः असम के नलबाड़ी जिले में मुस्लिम किशोर के हमले से बहन को बचा रहे आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के स्थानीय नेता माधुर्य बर्मन की हत्या कर दी गई। इस हमले में उनकी चचेरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गईं। हमलावर माधुर्य की चचेरी बहन से एकतरफा प्यार करता था। प्रेम का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बाद में हमलावर आशिक अली उर्फ रोज अली को पुलिस ने उस समय गोली मार दी जब वह गिरफ्तारी के बाद भागने की कोशिश कर रहा था।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि आशिक अली ने रविवार शाम जगारा के पास गंगापुर गांव में माधुर्य व उनकी बहन पर उस उस समय हमला किया जब वे नलबाड़ी कस्बे से कुछ किताबें खरीदकर घर लौट रहे थे। हमलावर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई सोमवार को मुकलमुआ के नदी द्वीप पर हुई।

धारदार हथियार से हमला किए जाने से माधुर्य के सिर व गर्दन पर गहरे घाव हो गए। उन्हे नलबाड़ी मेडिकल कालेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल उनकी चचेरी बहन का गुवाहाटी मेडिकल कालेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है। वह 11 वीं कक्षा की छात्रा है। एसपी बिबेकानंद दास ने बताया कि पुलिस को मुकलमुआ क्षेत्र के नदी द्वीप पर आशिक अली के होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने उसे वहीं से दबोचा। हथियार की बरामदगी के दौरान उसने पुलिसकर्मी से राइफल छीन ली और टीम पर तीन गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई थी।

कुरुक्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपित 62 वर्षीय डाक्टर बोला-गलती हो गई

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र

- आरोपित की गिरफ्तारी के साथ सेवाएं समाप्त, महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान
- एलएनजेपी अस्पताल में उपचाराधीन पिता के साथ रुकी थी किशोरी
- आरोपित पहले भी दुष्कर्म के आरोप में भेजा गया था जेल, बाद में हुआ बरी

लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल (एलएनजेपी) में 62 वर्ष के परामर्शदाता चिकित्सक डा शैलेंद्र शैली पर 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। गिरफ्तारी के बाद आरोपित डाक्टर ने सोमवार को न्यायालय में पेश करने से पहले कहा कि मैं रिटायर्ड सीएमओ हूं, मुझसे गलती हो गई। मामले में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक कार्यालय की ओर से आरोपित चिकित्सक की सेवाएं समाप्त करने का पत्र जारी किया गया है। राज्य महिला आयोग ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है।

आरोपित डा शैलेंद्र शैली कैथल के नागरिक अस्पताल से सीएमओ के पद से सेवानिवृत्त है और एलएनजेपी में परामर्शदाता चिकित्सक के पद पर कार्यरत था। उस पर पहले भी एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे। तब उसे जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि, बाद में बरी हो गया था। इस मामले में नाबालिग के पिता गत शुक्रवार से अस्पताल में भर्ती थे और वह वार्ड में ही रुकी थी। शनिवार दोपहर नाबालिग की भी तबीयत खराब हो गई और उसे आपातकालीन विभाग में दाखिल किया गया। अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डा. उपेंद्र ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे किशोरी को ज्यादा ब्लीडिंग होने पर महिला वार्ड से इमरजेंसी में भेजा गया। किशोरी ने बताया कि उसके साथ डाक्टर ने गलत काम किया है। मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने पिता के बयान पर केयूके थाने में केस दर्ज कर आरोपित को रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया।

स्वास्थ्य विभाग ने सेवाएं समाप्त कीं

रविवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमित मिश्रा ने आरोपित डा शैलेंद्र शैली की सेवाएं तुरंत प्रभाव से की रद करने का पत्र जारी कर दिया। इसमें उनके खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद पिता की शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की बात भी लिखी है।

नैनोप्लास्टिक : उदासी और अवसाद की ओर धकेल रहे सूक्ष्म कण

जागरण विशेष

सीमैप के अध्ययन में सामने आई जानकारी, हल्दी, तुलसी व ताजे फल दे सकते हैं सुरक्षा

गौरी त्रिवेदी • जागरण

लखनऊः प्लास्टिक प्रदूषण अब केवल नदियों या बाह्य पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गया है। यह हमारे शरीर में प्रवेश कर मानसिक स्वास्थ्य पर प्रहार कर रहा है। प्लास्टिक के अत्यंत सूक्ष्म कण (नैनोप्लास्टिक) अब मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान (सीमैप) के विज्ञानियों के एक हालिया अध्ययन में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। शोध के अनुसार, शरीर में पहुंचे नैनोप्लास्टिक के कण कोशिकाओं के ऊर्जा केंद्र को नष्ट कर देते हैं, जिससे डोपामिन जैसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर घटने लगता है। यही स्थिति आगे चलकर उदासी, अवसाद और पार्किंसन जैसी लाइलाज न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों की जमीन तैयार करती है।

घट रहा है हैप्पी हार्मोन का स्तरः अध्ययन में देखा गया कि नैनोप्लास्टिक के कण कोशिकाओं के ऊर्जा उत्पादन केंद्र यानी माइटोकान्ड्रिया की कार्यक्षमता को ठप कर देते हैं। इससे शरीर में आक्सीडेटिव स्ट्रेस (तनाव) बढ़ता है और हानिकारक फ्री रेडिकल्स की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है। परिणामस्वरूप मस्तिष्क में डोपामिन का स्तर तेजी से गिरता है।

चूंकि, डोपामिन को आम बोलचाल में खुशी का हार्मोन कहा जाता है, जो व्यक्ति के मूड, मानसिक संतुलन और संतुष्टि को नियंत्रित करता है, इसलिए इसकी कमी सीधे अवसाद की ओर धकेलती है। शोधकर्ताओं ने आगाह किया है कि यदि मानव शरीर लंबे समय तक नैनोप्लास्टिक के संपर्क में रहता है, तो यह तंत्रिका तंत्र को स्थायी रूप से पंगु बना सकता है। यह स्थिति अंततः पार्किंसन रोग का रूप ले लेती है, जिसमें व्यक्ति के शरीर का संतुलन, कंपन और शारीरिक गति पर नियंत्रण समाप्त होने लगता है। यह शोध प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका फ्री रेडिकल बायोलाजी एंड मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन का नेतृत्व सीमैप के वरिष्ठ विज्ञानी डाक्टर रत्नशेखर सीएच ने किया। शोध दल में प्रिया राठौर, आशुतोष के. तिवारी, राजेंद्र पी. पटेल, अनूप कुमार वर्मा और शीलेंद्र प्रताप सिंह जैसे युवा विज्ञानी शामिल रहे।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

शोधार्थी डा. रत्नशेखर, अनूप कुमार, आशुतोष तिवारी, पूनम और प्रिया (बाएं से दाएं) • संस्थान

ऐसे हुआ सूक्ष्म कणों के कुप्रभाव का विश्लेषण

विज्ञानियों ने इस शोध के लिए आधुनिक ब्रेन लिपिडोमिक्स तकनीक का उपयोग किया, जिसके जरिये मस्तिष्क की कोशिकाओं में मौजूद वसा (लिपिड) और उसमें होने वाले सूक्ष्म बदलावों का बारीकी से विश्लेषण किया गया। अध्ययन के लिए वैश्विक स्तर पर मान्य ड्रोसोफिला (फ्रूट फ्लाई) माडल का प्रयोग किया गया, जो जैविक और न्यूरोलाजिकल शोधों के लिए सटीक माना जाता है।

हाल के वर्षों में वैश्विक शोधों ने यह सिद्ध किया है कि माइक्रो और नैनोप्लास्टिक कण भोजन, पेयजल और रक्त के रास्ते हमारे अंगों में पहुंच रहे हैं। अब इनके मस्तिष्क तक पहुंचने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं, जो भविष्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक अलार्मिंग स्थिति है।

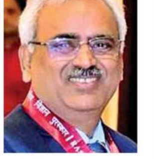

प्रो. प्रबोध कुमार त्रिवेदी, निदेशक, सीमैप

प्रकृति की शरण में है समाधान

इस गंभीर संकट के बीच सीमैप के विज्ञानियों ने एक राहत भरी उम्मीद भी जगाई है। अध्ययन में पाया गया कि हल्दी, तुलसी, ग्रीन-टी और ताजे फलों में प्रचुरता से पाए जाने वाले पालीफेनोल्स नामक तत्व नैनोप्लास्टिक के दुष्प्रभावों को बेअसर करने में सक्षम हैं। ये शक्तिशाली एंटीआक्सीडेंट शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को शांत कर मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, जिससे नैनोप्लास्टिक से होने वाले न्यूरोटॉक्सिसिटी का खतरा काफी हद तक टल जाता है। प्लास्टिक के अनियंत्रित उपयोग के बीच यह शोध एक गंभीर चेतावनी है। यह साफ करता है कि प्लास्टिक का जहर अब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को निगल रहा है। ऐसे में प्लास्टिक का बहिष्कार, पर्यावरण की शुचिता और आहार में एंटीआक्सीडेंट से भरपूर प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना अब हमारी पसंद नहीं, बल्कि जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। सीमैप, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। वर्ष 1959 में स्थापित यह संस्थान औषधीय और सुगंधित पौधों की उन्नत किस्मों के विकास, उनकी वैज्ञानिक खेती और पौधों से जीवन रक्षक औषधीय तत्वों के निष्कर्षण संबंधी उच्च स्तरीय शोध के लिए वैश्विक पटल पर विख्यात है।

आपरेशन म्यूल हंट से साइबर अपराधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक

राज्य ब्यूरो, जागरण • गांधीनगर

- गुजरात में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने चलाया विशेष अभियान

2289 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी पकड़ी, 638 गिरफ्तार

साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए गुजरात पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया। करीब एक हजार म्यूल अकाउंट की जांच कर 2289 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया।

पुलिस ने 565 प्राथमिकी दर्ज कर 638 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस ने गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में आपरेशन म्यूल हंट 1.0 आपरेशन चलाया। संघवी इस अभियान की आनलाइन निगरानी भी करते रहे।

गुजरात पुलिस के साइबर सेंटर आफ एक्सीलेंस ने इस आपरेशन में म्यूल अकाउंट्स पर कार्रवाई कर अलग-अलग मामलों में कुल 2289 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर 565 एफआइआर दर्ज किया। उसने 638 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

म्यूल अकाउंट का उपयोग साइबर अपराधी धोखाधड़ी से पैसों को प्राप्त करने, ट्रांसफर करने और मनी लांड्रिंग के लिए करते हैं। ऐसे खाते के मालिक को "मनी म्यूल" कहा जाता है। अभियान के चलते चेक के जरिये निकासी में 75 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं मासिक चेक निकासी 126 करोड़ से घटकर 25 करोड़ हो गई जो 80 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है।

इस अभियान को कारगर बनाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआइ) के दिशा-निर्देशों के तहत इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कारपोरेशन की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिये रिस्क स्कोरिंग प्रणाली लागू की जा रही है।

इस प्रणाली के तहत हर ट्रांजेक्शन को लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ताकि संदिग्ध अकाउंट की पहचान की जा सके।

दैनिक जागरण
सकारात्मकता से ही उत्पादकता बढ़ती है

खेत बचाओ अभियान

यह अच्छा है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति में कठिनाई और उनके मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने खेत बचाओ अभियान शुरू किया। इस अभियान को शुरू करने के पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों, आइसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों और किसान संगठनों से गहन संवाद किया, उससे यह पता चलता है कि वे इस अभियान को वास्तव में सफल होते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे किसी अभियान की सफलता जन भागीदारी और जागरूकता के माध्यम से ही संभव है। निःसंदेह इस अभियान में केंद्र सरकार को राज्यों का सक्रिय सहयोग चाहिए होगा। इसी तरह यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि आम किसान यह समझें कि रासायनिक उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग केवल खेती की लागत ही नहीं बढ़ाता, बल्कि खेतों की मिट्टी की उर्वर क्षमता को भी कम करता है। इसके अतिरिक्त भूजल भी दूषित होता है। एक ऐसे समय जब जलवायु बदल रही है, तब उर्वरकों का अंसतुलित उपयोग खेती के सामने गंभीर चुनौती बन रहा है। समस्या यह है कि औसत किसान यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल अंततः उनके लिए घाटे का सौदा ही सिद्ध होता है, क्योंकि प्रारंभ में तो फसल अच्छी होती है, लेकिन समय के साथ खेतों की मिट्टी दूषित हो जाने के कारण उपज प्रभावित होती है। वैसे तो प्रधानमंत्री ऐसी अपील करते रहे हैं कि किसान रासायनिक उर्वरकों का सही उपयोग करने के लिए खेतों की मिट्टी का परीक्षण कराएं और जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दें, लेकिन इसके बाद भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए और रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग जारी है। इसका एक कारण उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी भी है। एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये उर्वरक सब्सिडी पर खर्च किए। इस वर्ष यह खर्च कहीं अधिक बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि अधिकतर उर्वरकों का आयात किया जाता है और अमेरिका-ईरान तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा की मानें तो जहां दो बोरी उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता होती है, वहां किसान चार बोरी का उपयोग करते हैं। वास्तव में जब भी कोई वस्तु सब्सिडी के चलते कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है तो उसका अनावश्यक उपयोग बढ़ जाता है। तथ्य यह भी है कि किसानों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने वाले उर्वरक की कालाबाजारी भी होती है, क्योंकि उसका इस्तेमाल औद्योगिक रसायन के रूप में भी होता है।

नगर निगम के परिणाम

चार नगर निगमों के चुनाव परिणाम ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे राजनीतिक सेमीफाइनल माना जा रहा था। धर्मशाला, मंडी और सोलन में भाजपा की जीत तथा पालमपुर में कांग्रेस की सफलता ने दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण संदेश छोड़े हैं। भाजपा ने तीन नगर निगमों में स्पष्ट बहुमत हासिल कर यह संकेत दिया है कि शहरी क्षेत्रों में उसकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। विशेषकर मंडी और सोलन में मिली सफलता उत्साहवर्धक है। कांग्रेस के लिए यह परिणाम चिंता का विषय हैं, क्योंकि सत्ता में होने के बावजूद वह तीन नगर निगमों में जनसमर्थन को वोटों में परिवर्तित नहीं कर सकी। इन नतीजों को केवल सत्ताविरोधी लहर का परिणाम मानना उचित नहीं होगा। कांग्रेस में टिकट वितरण में असंतोष और उम्मीदवारों के चयन में देरी भी हार का कारण माना जा सकता है। पार्टी को हार के कारणों की पड़ताल करनी होगी। दूसरी ओर भाजपा को भी आत्मसंतुष्टि से बचना होगा। नगर निगम चुनाव स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की लोकप्रियता से भी प्रभावित होते हैं। विधानसभा चुनावों में मतदाता विकास, रोजगार, महंगाई और शासन के व्यापक मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। इन परिणामों का बड़ा संदेश यही है कि चुनाव केवल जनभावना से नहीं, बल्कि मजबूत संगठन, समय पर निर्णय और कार्यकर्ताओं की एकजुटता से भी जीते जाते हैं। कांग्रेस के लिए आंतरिक चुनौतियों को दूर करने का समय मिला है, वहीं भाजपा के लिए यह सफलता एक अवसर है, जिसे जनविश्वास में बदलना उसकी अगली बड़ी चुनौती होगी।

नगर निगम चुनाव परिणाम में कांग्रेस को हार के कारण ढूंढ़ने होंगे

रचनात्मक बहस के बजाय सतही नारेबाजी

रामानंद शर्मा

लोकतंत्र में तीखी आलोचना सत्ता को निरंकुश होने से रोकती है, पर जब आलोचना का स्थान व्यक्तिगत घृणा ले ले, तो संवाद का रास्ता बंद हो जाता है

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों जब प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 'देशद्रोही' कहा, तो यह साधारण राजनीतिक आरोप नहीं था। देशद्रोह का यह आरोप इतना संगीन है कि सीधे प्रतिपक्ष की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि देश के शीर्ष कार्यकारी पदों और एक बड़े सामाजिक संगठन पर लगाए गए इस गंभीर आरोप का प्रामाणिक आधार क्या है? यदि देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, तो उसके समर्थन में तथ्य भी सामने आने चाहिए। अन्यथा यह राजनीतिक असहमति नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श के स्तर को गिराने वाली बयानबाजी मानी जाएगी। संवैधानिक मर्यादा के इसी क्षरण के संदर्भ में 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दिया गया बाबासाहेब आंबेडकर का अंतिम भाषण याद आता है। उन्होंने सचेत किया था कि जब अपनी बात रखने और सरकार बदलने के शांतिपूर्ण मार्ग उपलब्ध हों, तब अमर्यादित भाषा और असंवैधानिक तौर-तरीकों का आश्रय लेना 'अराजकता का व्याकरण' बन जाता है। दुर्भाग्य से, विपक्ष का एक वर्ग ऐसी भाषा और शैली को अपनी राजनीतिक कार्यशैली का हिस्सा बनाता दिखाई देता है। लोकतंत्र में तीखी आलोचना सत्ता को निरंकुश होने से रोकती है, परंतु जब आलोचना का स्थान व्यक्तिगत घृणा ले ले, तो संवाद का रास्ता बंद हो जाता है। देश के सर्वोच्च कार्यकारी पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों के लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग न केवल उस विशाल जनादेश का अवमूल्यन है जिसने उन्हें चुना है, बल्कि यह हमारी समूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की वैधता को ही कठघरे में खड़ा करता है।

विपक्ष द्वारा लगातार यह विमर्श गढ़ा जा रहा है कि वर्तमान सत्ता 'संविधान को खत्म' कर रही है। संविधान पर आघात की पड़ताल करने से तथ्य स्वयं अपनी कहानी कह देंगे। याद कीजिए जून 1975 का वह दौर जब बिना किसी विधिवत कैबिनेट बैठक के देश पर आपातकाल थोपा गया था। विपक्षी नेताओं को जेलों में डालना, प्रेस पर सेंसरशिप लगाना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करना संवैधानिक ढांचे का विध्वंस था। बिना विपक्ष की मौजूदगी के संसद के भीतर 42वां संविधान संशोधन पारित कर संविधान की मूल प्रस्तावना को बदला गया था। वर्तमान में संसद के भीतर हर विधेयक पर बहस होती है, मत विभाजन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है और सर्वोच्च अदालत कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। जहां तक संविधान के सम्मान और जन-जागरूकता का प्रश्न है, वर्तमान सरकार ने संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उसके मूल्यों को समाज तक पहुंचाने और लोकतांत्रिक चेतना को सशक्त करने के लिए निरंतर संस्थागत प्रयास किए गए हैं। संविधान शिल्पी बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के जीवन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण स्थानों को 'पंचतीर्थ' के रूप में भी इसी सरकार ने विकसित किया। राजा सुहेलदेव से लेकर वीरा पासी तक, वंचित समाज के नायकों को जो सांस्कृतिक सम्मान आज मिल रहा है, उससे समाज के अनेक वंचित वर्गों में आत्मगौरव और सांस्कृतिक पहचान की भावना को बल मिला है।

अवधेश राजपूत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महात्मा गांधी के अंतर्संबंधों को लेकर भी विपक्ष का विमर्श ऐतिहासिक तथ्यों से परे दिखाई देता है। गांधीजी मानते थे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम विकास, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वच्छता और अस्पृश्यता उन्मूलन को जीवनशैली बनाना होगा। आजादी के बाद सत्ता संभालने वाले तंत्र ने गांधी के इस रचनात्मक माडल को पीछे छोड़ दिया, जबकि संघ ने राजनीति से अलग रहकर गांधी के इन सेवापरक कार्यों को अपने संगठन का मूल आधार बनाया। आज वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार और सुदूर गांवों में चल रहे 'एकल विद्यालय' महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के विचार के ही व्यावहारिक रूप हैं। महात्मा गांधी ने 1934 में वर्धा के पास संघ के एक शिविर का प्रत्यक्ष दौरा किया था और वहां जातिगत भेदभाव की पूर्ण अनुपस्थिति की सराहना की थी। अतः संघ को गांधी के विचारों का विरोधी बताना व्यावहारिक यथार्थ की कसौटी पर निराधार सिद्ध होता है।

डा. आंबेडकर का मानना था कि वास्तविक सशक्तीकरण वित्तीय समावेशन से आता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिचौलियों की पुरानी संस्कृति को खत्म करके निर्धन नागरिकों के बैंक खातों में मदद पहुंचाना, यूपीआइ तकनीक द्वारा छोटे व्यापारियों को मुख्यधारा से जोड़ना और मुद्रा ऋणों के जरिये करोड़ों वंचित युवाओं को उद्यमी बनाना इसी दौर में संभव हुआ है। इन आर्थिक वास्तविकताओं को समझे बिना केवल सतही नारा गढ़ने से कोई रचनात्मक आर्थिक बहस संभव नहीं है। विपक्ष राजनीतिक हताशा में जिस आक्रामक शैली को अपना रहा है, उसका नुकसान देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को हो रहा है। जब न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सरकार और संसद की पूरी प्रक्रिया पर लगातार आधारहीन सवाल उठाए जाते हैं, तो इससे भारतीय राज्य की साख ही कमजोर होती है।

लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने या हारने का नाम नहीं है, यह उन संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास पर टिका होता है, जो इस व्यवस्था का संचालन करती हैं। यदि देश का नागरिक यह मानने लगेगा कि उसकी हर संस्था बिकी हुई या पक्षपाती है, तो वह व्यवस्था के प्रति उदासीन हो जाएगा। इसके दुष्परिणाम विपक्ष को भी भोगने पड़ेंगे और देश एक स्थायी राजनीतिक अस्थिरता में फंस जाएगा। विपक्ष को यह समझना होगा कि उसका कार्य सत्ता की नीतियों का ठोस विकल्पों के साथ विरोध करना है, न कि पूरे तंत्र की वैधता को ही खारिज कर देना। पूरी व्यवस्था को ही अवैध ठहराने का यह विमर्श लोकतंत्र के हित में नहीं है। व्यवस्था की साख बनी रहेगी, तभी देश का जनतंत्र सुरक्षित रह सकेगा।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

अविश्वास से घिरती जा रहीं परीक्षाएं

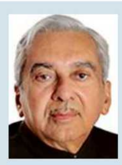

जगमोहन सिंह राजपूत

ऐसी शिक्षा-पद्धति की तलाश करनी होगी, जो केवल ज्ञान और कौशल ही नहीं, बल्कि नैतिकता का भी निर्माण करें

देश में प्रश्नपत्रों का परीक्षा से पहले 'आउट' हो जाना लगभग सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। इसका विस्तार बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षाओं तक फैल चुका है। सरकारी तंत्र ने अगले वर्ष के लिए सुधारों का आश्वासन दिया है। यह आवश्यक भी था, लेकिन जो अविश्वास पूरे देश में फैल चुका है, क्या उसका समाधान भी हो पाया है? अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। कुछ लोग तो वर्षों से इस प्रकार के अवैध कार्यों को व्यवसाय की तरह संचालित करते रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें कहीं न कहीं से संरक्षण भी मिलता रहा होगा। हर बार सरकारी तंत्र प्रश्नपत्र तैयार करने, उसे परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने और परीक्षा प्रारंभ होने तक उसकी गोपनीयता बनाए रखने की व्यवस्था में सुधार करता है, लेकिन समस्या का एक बड़ा पक्ष ऐसा भी है, जिसे सभी जानते हैं, पर उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ वर्ष पहले बिहार की एक बोर्ड परीक्षा के परिणामों को लेकर देशव्यापी चर्चा हुई थी। उस दौरान एक छात्रा का यह कथन व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करने वाला था कि 'मैं तो सेकेंड डिवीजन में पास होना चाहती थी, चाचा ने टाप करा दिया।' यह एक ऐसा संकेत था, जो समस्या के वास्तविक समाधान की दिशा दिखा सकता था।

हमें इस पर भी विचार करना होगा कि आखिर लीक हुए प्रश्नपत्र कौन खरीदता है? इसके लिए धन तो परिवार ही देता है और साल्वर, वह भी नीट जैसी परीक्षा में, कौन बन सकता है? कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा छात्र या डाक्टर बन चुका सुशिक्षित व्यक्ति ही यह कार्य कर सकता है। क्या इस देश ने कभी नागरिकों को यह बताया कि किसी साल्वर को या बड़ी धनराशि देकर अपने लाड़लों के लिए प्रश्नपत्र खरीदने वाले परिवार के किसी सदस्य को क्या सजा मिली? इस प्रकार के मामलों और ऐसी अन्य कारगुजारियों में अपराधियों को दंडित करने के मामले में भारत इतना कमजोर क्यों है? या यूं कहें कि व्यवस्था इतनी शिथिल क्यों है? संविधान में मूलभूत कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यदि सरकार, शिक्षित वर्ग और समाज इनका पालन करते होते तो क्या प्रश्नपत्र लीक होते? आगे क्या केवल कानून बदलकर प्रश्नपत्र लीक को रोका जा सकेगा? व्यवस्था को लगातार सतर्क तो रहना ही होगा, लेकिन जब तक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मानवीय तत्व को जागृत करने में असमर्थ रहेगी, तब तक ऐसी आशंकाएं साकार होती रहेंगी और परीक्षाओं की साख पुनः स्थापित नहीं हो पाएगी। नीट के प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच तेजी से चल रही है। यह स्पष्ट हो गया है कि जो लोग प्रश्नपत्र बनाने योग्य समझे गए थे, जो विशेषज्ञ माने जाते थे, वे अपेक्षित नैतिक स्तर पर खरे नहीं उतरे।

नीट पेपर लीक में गिरफ्तार कोचिंग संचालक। फाइल

स्वतंत्रता के बाद के पहले कई दशकों तक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक क्यों नहीं होते थे। वर्ष 1965-70 तक समाज में हर तरफ ऐसे लोग उपस्थित थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग किया था, तपस्या की थी और अपना सर्वश्रेष्ठ देश तथा उसके नागरिकों के लिए समर्पित कर दिया था। आज स्थिति कहां पहुंच गई है? सत्ता में पहुंचकर या व्यवस्था का अंग बनकर सामान्य जन को भूल जाना लगभग पूरी तरह स्वीकार्य हो चुका है। महात्मा गांधी का एक सूत्र-वाक्य लगभग हर विचार-विमर्श में दोहराया जाता है कि 'प्रकृति के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति के लिए नहीं।' क्या नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने जैसी अनेक कष्टदायक घटनाओं के कारण इसी विचार में कहीं छिपे नहीं हैं? अंततः वह धन-लोलुपता ही है, जो एक अनुभवी अध्यापक को अपनी नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठा को भुलाकर एक जघन्य सामाजिक अपराध की ओर धकेल देती है। यह उस शिक्षा-व्यवस्था और पाठ्यक्रम की भी असफलता है, जो विद्यार्थियों को परीक्षाएं तो उत्तीर्ण करा देता है, लेकिन शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य-नैतिकता और मानवीय मूल्यों के साथ व्यक्तित्व-निर्माण में पूरी तरह असफल सिद्ध होता है। नैतिकता का ह्रास भारत के भविष्य पर सीधी चोट कर रहा है।

विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, एआइ और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के युवा किसी से पीछे नहीं हैं। फिर भी प्रश्न यह है कि हम परीक्षाओं को ईमानदारी और विश्वास के साथ संपन्न कराने में स्वयं को असमर्थ क्यों पाते हैं? एक महत्वपूर्ण पक्ष, जिस पर अपेक्षित चर्चा नहीं होती, वह है मनुष्य की बढ़ती स्वार्थपरकता, संग्रह की प्रवृत्ति और धन के निर्बाध दुरुपयोग का अहंकार। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक इस विषय पर गंभीर वैचारिक मंथन की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा-पद्धति और विकल्पों की तलाश करनी होगी, जो केवल ज्ञान और कौशल ही नहीं, बल्कि नैतिकता से संपन्न व्यक्तित्व का भी निर्माण करें। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी अपने जीवन के लक्ष्यों, सामाजिक दायित्वों और जनहित की समझ पर निरंतर आत्ममंथन करते रहना होगा।

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

समर्पण

समर्पण की क्रिया को प्रायः एक धार्मिक प्रक्रिया से जोड़कर देखा जाता है, परंतु इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि समर्पण एक उच्च कोटि का प्रयास है, जिसमें साधारण मनुष्य भी प्रारंभ से ही किसी न किसी रूप में संलग्न रहता है। माता-पिता अपने परिवार, समाज और देश के प्रति समर्पित भाव से निरंतर कार्य करते हैं। समर्पण और उसके लिए की गई साधना कोई साधारण क्रिया नहीं है। विद्वानों ने साधना का असाधारण महत्व बताया है, जिसमें संकीर्णता का उदारता में और निष्क्रियता का उत्कृष्टता में विसर्जन करना होता है। महत्वाकांक्षाओं, अहंकार और 'मैं' की भावना को नियति अथवा ईश्वर को समर्पित कर स्वयं को रिक्त कर देना ही समर्पण की सर्वोच्च साधना है। समर्पित भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बनता है, बल्कि स्वयं भी धन्य होता है। ईश्वर अपने औदार्य और दानशीलता से समस्त जीव-जगत और निर्जीव प्रकृति को निःस्वार्थ भाव से अनुगृहीत करता है। इसलिए हमें भी भले ही सर्वोच्च स्तर पर नहीं, किंतु पर्याप्त मात्रा में समर्पण का भाव अवश्य रखना चाहिए।

सृष्टिकर्ता द्वारा प्रदत्त इस धरोहर की रक्षा और देखरेख करना भी हमारे समर्पण का ही एक रूप है। प्रकृति की उपेक्षा संसार को विनाश की ओर ले जा सकती है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि अपनी स्वार्थ-प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हुए ईश्वर द्वारा प्रदान की गई संपदाओं-जल, वायु, हरियाली और प्रकृति के अन्य उपहारों के प्रति समर्पण और संरक्षण का भाव रखें। यह समर्पण एक श्रेष्ठ साधना है, जो मनुष्य को अपराध-बोध और ग्लानि से मुक्त करने का सुंदर एवं सुनियोजित माध्यम बन सकती है। इसके परिणामस्वरूप न केवल व्यक्ति का आत्मिक विकास होगा, बल्कि मानवता का सम्मान और गौरव भी बढ़ेगा।

छाया श्रीवास्तव

शिक्षा का नया अवसर

सुनीता मिश्रा

देश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने की समस्या अभी समाप्त नहीं हो सकी है

केंद्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और अन्य कारणों से स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ चुके 14 से 18 वर्ष की उम्र के करीब दो करोड़ बच्चों को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक देशव्यापी योजना तैयार की है। इसके तहत उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआइओएस) के माध्यम से ब्लाक स्तर पर दाखिला देकर पढ़ाया एवं प्रशिक्षित किया जाएगा। पिछले एक दशक में भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर ड्रापआउट की समस्या अभी समाप्त नहीं हो सकी है। वर्ष 2025 में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में देशभर में 65.7 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, जिनमें लगभग 30 लाख लड़कियां थीं। यह स्थिति बताती है कि शिक्षा तक पहुंच बढ़ने के बावजूद बच्चों को स्कूलों में बनाए रखना अब भी एक बड़ी चुनौती है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल इंडिया के दौर में भी देश के 1.19 लाख स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं, जबकि 61,540 स्कूलों में किसी भी प्रकार का उपयोगी शौचालय उपलब्ध नहीं है। लगभग 14,505 स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है और देश में एक लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। ऐसे हालात में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। मुफ्त शिक्षा और पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था होने के बावजूद स्टेशनरी, परिवहन एवं अन्य खर्च कम आय वाले परिवारों के लिए बोझ बन जाते हैं। ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में प्राथमिक विद्यालय निकट होते हैं, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अक्सर दूर होते हैं। सुरक्षित परिवहन और छात्रावास जैसी सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। कई क्षेत्रों में आज भी कम उम्र में विवाह, घरेलू जिम्मेदारियां और लैंगिक भेदभाव के कारण लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पातीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का लक्ष्य स्कूल छोड़ चुके लगभग दो करोड़ बच्चों को पुनः शिक्षा प्रणाली से जोड़ना और वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। यह योजना उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि दो करोड़ बच्चे फिर से शिक्षा से जुड़ते हैं तो यह देश की मानव संसाधन क्षमता को मजबूत करने के साथ बाल श्रम, सामाजिक असमानता और गरीबी कम करने में मदद करेगा। इस योजना की सफलता बच्चों को लंबे समय तक शिक्षा से जोड़े रखना होगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

गरीबों के हित में फ्रीबीज

'विकास को बाधित करती रेवड़ी संस्कृति' शीर्षक से लिखे आलेख में जीएन वाजपेयी ने मुफ्तखोरी और लोकलुभावन योजनाओं को सरकारी खजाने के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक बताया है, लेकिन सवाल यह है कि देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता करना क्या वास्तव में गलत है? हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी या छोटे-मोटे कार्य करके जीवनयापन करते हैं, लेकिन उनकी आय महंगाई की बढ़ती रफ्तार के अनुरूप नहीं बढ़ पाती। ऐसे लोगों को यदि सरकार कुछ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करती है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को कोई विशेष नुकसान नहीं होता। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं का लाभ आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी लेने लगते हैं और सरकार उनकी पात्रता की उचित तथा निष्पक्ष जांच नहीं करती। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से रेवड़ी संस्कृति अर्थव्यवस्था पर बोझ बन सकती है। यदि रेवड़ी संस्कृति को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए तो इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता इसे पूरी तरह बंद करने की नहीं, बल्कि इसमें सुधार करने की है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। साथ ही ऐसी योजनाओं को आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और रोजगार सृजन से भी जोड़ा जाए, ताकि लोग स्थायी रूप से सशक्त बन सकें। यही संतुलित दृष्टिकोण देश के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, दोनों के लिए हितकारी होगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

बचपन में मोबाइल की लत

आज का डिजिटल युग जहां लोगों के लिए अनेक सुविधाएं लेकर आया है, वहीं यह बच्चों के बचपन को भी धीरे-धीरे प्रभावित कर रहा है। कुछ वर्ष पहले तक बच्चे अपना अधिकांश समय मैदानों में खेलते हुए, दोस्तों के साथ समय बिताते हुए और नई-नई चीजें सीखते हुए गुजारते थे। वे खिलौनों से खेलते थे, खुद छोटी-छोटी चीजें बनाना सीखते थे और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते थे। इससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास बेहतर होता था, लेकिन आज स्थिति काफी बदल चुकी है। व्यस्त जीवनशैली के कारण कई माता-पिता बच्चों को समय नहीं दे पाते और उन्हें शांत रखने के लिए कम उम्र में ही मोबाइल फोन थमा देते हैं। शुरुआत कार्टून और वीडियो देखने से होती है, लेकिन धीरे-धीरे बच्चे मोबाइल के इतने आदी हो जाते हैं कि उनके लिए फोन के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। कई बच्चे खाना खाते समय, पढ़ाई के दौरान और यहां तक कि सोने से पहले भी मोबाइल देखने की जिद करते हैं। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा है। कम उम्र में आंखों की कमजोरी, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और शारीरिक निष्क्रियता जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। पहले जहां बच्चे बाहर दौड़ते-भागते थे, वहीं अब घंटों मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। इससे न केवल उनका शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि उनकी रचनात्मकता और सोचने-समझने की क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। इंटरनेट मीडिया की दुनिया ने बच्चों को वास्तविक जीवन से दूर कर दिया है। चिंताजनक यह है कि बच्चे अब किताबों, खेलों और सामाजिक गतिविधियों की तुलना में मोबाइल को अधिक महत्व देने लगे हैं। इससे उनके व्यवहार और व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि यही स्थिति जारी रही तो आने वाली पीढ़ी तकनीक पर निर्भर तो होगी, लेकिन जीवन के कई महत्वपूर्ण अनुभवों और कौशलों से वंचित रह जाएगी। अभिभावक बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं, उन्हें खेलकूद, पुस्तक पढ़ने और रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करें। साथ ही मोबाइल और इंटरनेट मीडिया के उपयोग की एक निश्चित सीमा तय की जानी चाहिए। तकनीक का उपयोग आवश्यक है, लेकिन बचपन की कीमत पर नहीं।

gautam12adarsh96@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी* दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

40 प्रतिशत के आसपास है ब्रिक्स देशों का योगदान वैश्विक अर्थव्यवस्था में, पर्चेजिंग पावर के दृष्टिकोण से, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार। वैश्विक आर्थिकी में इन देशों का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है।

आजकल

बदलती व्यवस्था में भारत के लिए अवसर

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था को यदि एक वाक्य में समझना हो तो यह कहना पर्याप्त होगा कि दुनिया अब मुक्त व्यापार से अधिक सुरक्षित व्यापार पर भरोसा करने लगी है। पिछले तीन दशकों तक परस्पर निर्भरता और नवीन आर्थिकी का मूल सिद्धांत यह था कि उत्पादन वहीं होगा, जहां लागत सबसे कम होगी और मांग ज्यादा हो, भले ही राजनीतिक जोखिम बड़ा क्यों न हो। परंतु कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका-ईरान टकराव और अमेरिका-चीन तकनीकी संघर्ष ने इस सोच को उलट दिया है। ऐसे में भारत के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं

प्रो. एम एल मीणा
भूगोल विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़

भारत आज एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लिहाजा दुनिया उसे आर्थिक संभावना से अधिक अब भूराजनीतिक शक्ति के रूप में देखने लगी है। यही परिवर्तन निर्णायक है। वर्ष 1991 के बाद भारत को उभरती अर्थव्यवस्था कहा जाता था, जबकि आज भारत वैश्विक आर्थिक संरचना का स्थायी हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस संदर्भ में भारत के उभार को केवल राष्ट्रवादी उत्साह के चश्मे से देखना सिर्फ एक पक्ष होगा। वस्तुतः भारत आज जिस स्थान पर दिखाई दे रहा है, वह केवल उसकी उपलब्धियों का परिणाम भर नहीं है। वह वैश्विक अस्थिरता की उपज भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया भारत की ओर उतनी नहीं बढ़ी, जितनी वह चीन पर अत्यधिक निर्भरता से पीछे हटी है। यही कारण है कि भारतीय अवसर को समझने के लिए पहले हमें चीन की थकान को समझना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों में चीन के प्रति पश्चिमी देशों का दृष्टिकोण तेजी से बदला है। कभी जिसे विश्व की फैक्ट्री कहा जाता था, वही चीन अब रणनीतिक जोखिम के रूप में अधिक देखा जा रहा है। भले ही इसे देखने का परिप्रेक्ष्य परिस्थितियों के अनुरूप अलग-अलग हैं। लेकिन हालिया भू-राजनीतिक बदलावों को देखे तो पाते हैं कि अमेरिकी कंपनियों पर घरेलू दबाव बढ़ रहा है कि वे अपनी उत्पादन इकाइयों को चीन से बाहर निकालें। ऐसे में भारत, वियतनाम, मेक्सिको और इंडोनेशिया जैसे देशों को बड़ा अवसर मिला है।

हालांकि यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि भारत चीन का वास्तविक विकल्प बन चुका है, जैसा कि आज के समय में प्रचलित है। चीन आज भी वैश्विक विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। उसकी लाजिस्टिक क्षमता, बंदरगाह संरचना, तकनीकी दक्षता और निर्यात नेटवर्क भारत से कहीं आगे हैं। जैसे कि भारत में अभी भी लाजिस्टिक लागत जीडीपी के 13-14 प्रतिशत तक पहुंच जाती है, जबकि चीन में यह काफी कम है। यही कारण रहता हैं कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश तो कर रही हैं, लेकिन अपनी मुख्य उत्पादन क्षमता अब भी चीन में बनाए हुए हैं।

फिर भी भारत को लेकर वैश्विक उत्साह के पीछे बड़ी आर्थिक संभावना मौजूद है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बनी हुई है। लेकिन यहां असली सवाल यह नहीं कि भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि यह है कि भारत किस प्रकार का विकास माडल बना रहा है। क्योंकि अक्सर आंकड़ों की चमक वास्तविक संरचनात्मक समस्याओं को ढक देती रही है। इसका अर्थ यह है कि भारत मात्रात्मक अर्थव्यवस्था तो बन रहा है, लेकिन अभी समग्र गुणात्मक विकास से दूर हैं। इतिहास बताता है कि केवल विकास दर किसी राष्ट्र को स्थायी शक्ति नहीं बनाती हैं। यदि आर्थिक वृद्धि, रोजगार और सामाजिक समरसता न हो, तो वही विकास अंततः राजनीतिक व आर्थिक असंतोष का कारण बन सकता है।

यहीं भारत के सामने एक अलग प्रकार की चुनौती सामने आती है कि क्या भारत उत्पादक जनसंख्या तैयार कर रहा है? आज दुनिया भारत को उसकी युवा आबादी के कारण अवसर के रूप में तो देख रही है। लेकिन यह जनसांख्यिकीय लाभ तभी शक्ति बनेगा, जब भारत अपनी शिक्षा और कौशल व्यवस्था को वैश्विक उद्योग की जरूरतों के अनुसार बदल सके।

वस्तुतः भारत की आर्थिक कहानी को समझने के लिए हमें उसकी विदेश नीति को भी आर्थिक दृष्टि से देखना होगा। काफी समय से भारत ने जिस प्रकार बहुध्रुवीय कूटनीति अपनाई है, वह भू-राजनीतिक रणनीति के साथ आर्थिक सुरक्षा का हिस्सा भी है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के संबंध थोड़े आशंकित हैं, क्योंकि यह संबंध उन परंपरागत और विरासत की कीमत पर बने हैं, जिन्होंने भारत के साथ मित्रवत व्यवहार रखा।

इसके अलावा, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि भारत की आर्थिक संरचना अभी भी कई बाहरी निर्भरताओं से घिरी हुई है। ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता से कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सी हलचल सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन भारत की विकास यात्रा के लिए नया संकट बनता जा रहा है। इसलिए आने वाले वर्षों में वैश्विक भू-आर्थिक परिदृश्य में भारत को ग्रीन ग्रोथ और विकास के बीच कठिन संतुलन बनाना होगा।

अंततः दुनिया के नए भू-आर्थिक नक्शे में भारत निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत 21वीं सदी का नया आर्थिक केंद्र बन चुका है। फिलहाल भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां अवसर और भ्रम दोनों साथ-साथ मौजूद हैं। यदि भारत विनिर्माण, रोजगार, तकनीक और सामाजिक समानता के बीच संतुलन बना पाया तो संभव है कि आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र वास्तव में एशिया और विशेष रूप से भारत की ओर खिसक जाए। लेकिन यदि विकास केवल आंकड़ों और नारों तक सीमित रहा, तो भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो सकता है जिन्होंने संभावना तो दिखाई, परंतु संरचनात्मक बदलाव पूरा नहीं कर पाए। दुनिया का भू-आर्थिक नक्शा तेजी से बदल रहा है। भौगोलिक नजरिये से आर्थिक संभावना को देखें तो इतिहास प्रायः अवसर देता है, लेकिन वह किसी राष्ट्र को स्थायी महत्व तभी देता है जब वह अवसर को संस्थागत शक्ति में बदल सके।

विनिर्माण केंद्र के रूप में स्वयं को आगे बढ़ाने की भारत में व्यापक क्षमता है। फाइल

विश्व व्यवस्था के प्रारूप में परिवर्तन

रवि दास बिश्नोई
अध्येता, इंडो-पैसिफिक डोमेन

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद निर्मित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था दशकों तक नियम-आधारित वैश्विक प्रणाली की आधारशिला बनी रही थी। किंतु आज उस व्यवस्था की बुनियाद पहले जैसी मजबूत दिखाई नहीं देती है। ब्रेटन वुड्स संस्थाएं, डब्ल्यूटीओ, नाटो और डालर-आधारित वित्तीय तंत्र को लेकर चल रहे हालिया विमर्श इसके स्पष्ट संकेतक हैं। वर्ल्ड इकोनमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2026 में पहली बार भू-आर्थिक टकराव को दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम बताया गया है। इससे यह समझा जा सकता है कि आने वाले दशक में दुनिया एक बहुध्रुवीय अथवा अधिक विखंडित व्यवस्था की ओर बढ़ेगी। ऐसे में प्रश्न केवल यह नहीं रह जाता कि पुरानी व्यवस्था टूट रही है या नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या उसकी जगह कोई नई व्यवस्था आकार ले रही है या फिर हम एक स्थायी वैश्विक अव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं।

दरअसल, वैश्विक प्रतिस्पर्धा अब चोकप्वाइंट भू-राजनीति का रूप लेती जा रही है, जहां सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, ऊर्जा गलियारे और समुद्री मार्ग नई शक्ति-स्पर्धा के केंद्र बन चुके हैं। चीन ने अमेरिकी टैरिफों के जवाब में प्रतिशुल्क लगाए, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच अमेरिका के चीन को निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। वहीं वियतनाम और कंबोडिया जैसे आसियान देश, जिनका अमेरिका के साथ लगभग 227 अरब डालर का व्यापार अधिशेष है, 49 प्रतिशत तक के संभावित टैरिफ दबाव की चपेट में आ गए। इन घटनाओं ने वैश्विक मूल्य-श्रृंखलाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। यदि वर्तमान भू-आर्थिक युग की सबसे तीखी प्रतिस्पर्धा को पहचानना हो, तो वह शायद मुद्रा और वित्तीय शक्ति के क्षेत्र में दिखाई देती है। ब्रिक्स समूह अब डालर-केंद्रित वित्तीय व्यवस्था को चुनौती देता दिख रहा है। रूस और ईरान वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की खोज में हैं, जबकि ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं।

इस समूचे परिदृश्य में यह समझना भी आवश्यक है कि उभरती हुई विश्व व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो सकता है। अमेरिका और चीन के संबंधों को देखें तो वे प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से बचते हुए अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत करने की रणनीति अपनाते दिखाई देते हैं। लिहाजा एक ऐसी व्यवस्था उभर रही है जिसमें नए नियम गढ़ने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन उन नियमों का अंतिम स्वरूप अभी अस्पष्ट है। भारत इस बदलती व्यवस्था में एक विशिष्ट स्थिति रखता है। वह ब्रिक्स का सदस्य भी है, क्वाड का भागीदार भी है और साथ ही डब्ल्यूटीओ में बहुपक्षवाद का समर्थक भी बना हुआ है। अमेरिकी टैरिफ नीतियों के बीच भारत ने अपेक्षाकृत संयत कूटनीति अपनाने का प्रयास किया है, जिसके कारण मशीनरी और वस्त्र जैसे कुछ क्षेत्रों में उसे अवसर भी प्राप्त हुए हैं। किंतु इसके साथ-साथ भारत को डब्ल्यूटीओ जैसे मंचों पर संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध अपनी आवाज भी निरंतर उठानी होगी।

विश्व व्यवस्था का अगला चरण संभवतः न तो अमेरिकी एकध्रुवीयता पर आधारित होगा और न ही पूर्ण चीनी वर्चस्व पर होगा। इसके बजाय यह एक बदलते संतुलनों वाली व्यवस्था होगी, जहां आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक शक्ति एक-दूसरे से गहराई से होंगी। इस बीच एक बात दिखाई देती है कि आने वाले समय में वही राष्ट्र अधिक प्रभावशाली होंगे जो अपनी आर्थिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और कूटनीतिक शक्ति को अपने भूगोल के अनुरूप प्रभावी ढंग से संयोजित कर सकेंगे।

खरी-खरी

प्रतिबंध का प्रबंध

विनय कुमार पाठक

किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। पहला लाभ तो यह होता है कि प्रतिबंधित वस्तु की मांग बढ़ जाती है। राजिंद्र कृष्ण ने वर्ष 1974 में फिल्म 'फाइव राइफल्स' में एक गीत दिया था, 'जब से सरकार ने नशाबंदी तोड़ दी मानो या ना मानो मैंने पीनी ही छोड़ दी।' इन पंक्तियों के द्वारा गीतकार यह बताने का सफल प्रयास करता है कि प्रतिबंधित वस्तु का सेवन करने का अपना अलग ही मजा है।

प्रतिबंध लगने के बाद प्रतिबंधित वस्तु अपना स्वरूप बदल लेता है या फिर कहें कि नवाचारी व्यापारी उसका स्वरूप बदल देते हैं। जिन राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है, उन राज्यों में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। इस बदले हुए रूप में शराब जो कहर बरपाता है, वह कुछ दिनों के लिए सुर्खियों में रहता है। फिर कानून के रक्षकों और कानून के भक्षकों के बीच लुकाछिपी का खेल भी शुरू हो जाता है। कई रक्षक इस प्रतिबंध का छक कर लाभ उठाते हैं।

यदि हम बात करें गुटका की, तो कुछ लोग इसे बहुत बड़ा धोखा करार देते हैं। उनका कहना है कि माल वही रहता है बस पैकिंग और नाम बदल जाती है। नई बोतल में पुरानी शराब की तर्ज पर नए पैकिंग में पुराना गुटका।

यही कारण है कि मुंह के कैंसर से पीड़ित रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। असल में मुंह तो पैकिंग को पहचानता नहीं है, वह तो पैकिंग के अंदर के माल को ही जानता है। एक उपाय और निकाला है तंबाकू सेवन करने वालों के मेहरबानों ने कि पान मसाला और तंबाकू को अलग-अलग पाउच में कर दिया है। इससे लाभ यह हो रहा है कि उपभोक्ता मर्जी से तंबाकू की मात्रा बढ़ा लेते हैं।

और इनको बढ़ावा देने के लिए खतरों के नकली खिलाड़ी यानी हमारे फिल्मी अभिनेताओं को दर्शक विज्ञापन में जब पान मसाला का पाउच खोलकर मुंह में डालते ही दुनिया को मुट्ठी में करते हुए देखते हैं तो वे उत्साहित होकर पान मसाला के साथ तंबाकू भी मिला लेते हैं। दुनिया उनकी मुट्ठी में आए या न आए, मुट्ठी से कुछ सिक्के जरूर खिसक लेते हैं।

मूल आधार को पुष्ट करने का प्रयास

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

भारतीय राजनीति के मानचित्र पर बंगाल केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक चेतना का नाम है। 'जो बंगाल आज सोचता है, वह भारत कल सोचता है'- गोपाल कृष्ण गोखले का यह कथन दशकों तक बंगाल की बौद्धिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रतीक रहा। किंतु बीते कुछ दशकों में यह पहचान के संकट, राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति की भेंट चढ़ती गई।

शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पहली भाजपा सरकार को सत्ता संभाले महज तीन सप्ताह हुए हैं, तो बंगाल की गलियों से लेकर नवान्न (राज्य सचिवालय) के गलियारों तक एक बुनियादी बदलाव की आहट स्पष्ट सुनाई दे रही है। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बंगाल के 'मूलाधार' को पुनर्जीवित करने का एक सुविचारित प्रयास है।

शुभेंदु सरकार का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अब बंगाल में 'धर्म आधारित विशेष लाभ' के दिन समाप्त हो चुके हैं। कैबिनेट के शुरुआती फैसलों में धर्म के आधार पर दिए जाने वाले भत्तों को बंद करना एक साहसिक कदम है। यह निर्णय उस धारणा पर चोट करता है जिसने वोट बैंक की राजनीति के लिए राज्य के खजाने को एक विशिष्ट वर्ग की जागीर बना दिया था। कल्याणकारी योजनाएं 'पात्रता' पर आधारित होनी चाहिए, न कि 'प्रार्थना' पर।

न्यायपालिका के आदेशों का सम्मान और कानून का इकबाल कायम करना इस नई सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। दशकों से बंगाल में सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और फुटपाथों पर होने वाली गतिविधियों से आम जनजीवन प्रभावित होता था। एक तरफ सड़कों पर नमाज पर रोक तो दूसरी ओर हाई कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन कराते हुए खुलेआम पशु वध, जिस पर प्रतिबंध लागू कराया गया है, उसने यह साफ कर दिया है कि अनुशासन सर्वोपरि है।

बंगाल की भौगोलिक स्थिति इसे भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे संवेदनशील केंद्र बनाती है। पूर्ववर्ती सरकारों ने अक्सर सीमा सुरक्षा को राजनीति के चश्मे से देखा, जिससे घुसपैठ और जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या विकराल हुई। शुभेंदु सरकार ने अपने पहले ही महीने में 'चिकन नेक' (सिलीगुड़ी कारिडोर) की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 'जीरो टालरेंस' नीति अपनाई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को फेंसिंग के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाना और घुसपैठियों की पहचान व होल्डिंग कैंपों की स्थापना जैसे निर्णयों ने सीमा पार के असामाजिक तत्वों में भय पैदा किया है।

बकरीद के दिन मायापुर में गाय की पूजा करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। फाइल

राजनीति में प्रतीक बहुत कुछ कहते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बकरीद के दिन मायापुर इस्कान मंदिर जाना, गाय की पूजा व सेवा करना और हर सार्वजनिक मंच पर उनके मस्तक पर सुशोभित 'लाल तिलक' केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं, बल्कि बंगाल की उस लुप्त होती सनातन संस्कृति का सार्वजनिक उद्घोष है जिसे वर्षों तक 'सेकुलरिज्म' के नाम पर हाशिए पर रखा गया। सरकारी कार्यक्रमों में मां काली या मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट करना यह दर्शाता है कि अब बंगाल अपनी विरासत पर शर्मिंदा नहीं, बल्कि गौरवान्वित है।

यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान केवल प्रतीकों तक सीमित नहीं है। यह बंगाल के उस खोये हुए गौरव को लौटाने का संकल्प है, जहां चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचार समाज की मुख्यधारा थे। सत्ता का केंद्र अब 'तुष्टीकरण' की गलियों से निकलकर 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' के खुले मैदान में आ चुका है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य में बंगाल की भूमिका निर्णायक है। नई सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचे का विकास तभी संभव है जब राज्य में शांति और निष्पक्ष कानून व्यवस्था हो। घुसपैठियों के बाहर जाने और पारदर्शी जनगणना के निर्णयों से राज्य के संसाधनों पर वास्तविक नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित होगा। इससे न केवल सामाजिक समरसता बढ़ेगी, बल्कि बंगाल एक बार फिर पूर्वी भारत का आर्थिक पावरहाउस बनने की दिशा में अग्रसर होगा। बंगाल अब एक ऐसे परिवर्तन के दौर में है जहां 'भय' की जगह 'भव्यता' और 'विभाजन' की जगह 'विकास' ले रहा है। यदि यह गति कायम रही, तो बंगाल न केवल अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त करेगा, बल्कि देश को विकसित बनाने में अग्रणी सारथी बनकर उभरेगा। बंगाल बदल रहा है, और इसकी गूंज पूरे राष्ट्र ही नहीं सीमा पार भी सुनाई दे रही है।

मंथन

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण

पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की प्राचीन परंपरा रही है। वर्तमान औद्योगिक युग में प्रकृति क्षरण के दौर में हमें फिर से इसे समझना चाहिए

आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी
कुलपति, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

वर्तमान में संपूर्ण विश्व पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन, तापवृद्धि, जल-संकट, वायु-प्रदूषण, वन-विनाश और जैव-विविधता का क्षय गंभीर चुनौती बन गए हैं। आधुनिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अब 'सतत विकास' तथा 'पर्यावरणीय संतुलन' की आवश्यकता पर बल देने लगी हैं, जबकि वैदिक परंपरा ने सहस्रों वर्ष पूर्व ही प्रकृति और मानव के सामंजस्यपूर्ण संबंध की बात की थी। वेदों ने प्रकृति को केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न अंग, देवतुल्य शक्ति और मातृस्वरूप स्वीकार किया। यही कारण है कि वेदों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, पर्वत, नदियों एवं समस्त जीव-जगत के संरक्षण की भावना झलकती है।

भारतीय संस्कृति का मूल दर्शन 'सह-अस्तित्व' पर आधारित है। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति के प्रत्येक तत्त्व में दिव्यता का अनुभव किया। यह दृष्टि आधुनिक पर्यावरणीय विचारधारा से कहीं अधिक व्यापक है। आज जब हम अपनी असीम भोगवादी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, तब वेदों का पर्यावरण-दर्शन संपूर्ण मानवता के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक हो सकता है।

भारतीय समाज में नदियों को 'माता' कहने के पीछे केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि गहरी पर्यावरणीय चेतना निहित थी। भारतीय परंपरा में जल-संरक्षण की अद्भुत व्यवस्थाएं विकसित हुई थीं। राजस्थान के जोहड़, गुजरात की बावड़ियां, दक्षिण भारत के मंदिर-तालाब और हिमालयी क्षेत्रों के प्राकृतिक जलस्रोत इस बात के प्रमाण हैं कि भारतीय समाज जल के महत्व को भली-भांति समझता था। वर्षाजल संचयन की परंपरा आज जिस रूप में आधुनिक विज्ञान प्रस्तुत कर रहा है, उसका व्यावहारिक रूप भारत में सदियों पहले विद्यमान था। कुएं, बावड़ियां, तालाब और सरोवर भारतीय ग्राम्य जीवन का महत्वपूर्ण भाग थे। इनकी नियमित सफाई और संरक्षण सामाजिक दायित्व माना जाता था।

वायु को वेदों में 'प्राण' कहा गया है। वायु के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है- 'प्राणो वै वायुः।' वायु ही प्राण है। यह वैदिक अनुभूति आधुनिक विज्ञान की उस अवधारणा से मेल खाती है, जिसमें आक्सीजन को जीवन का मूल आधार माना गया है। किंतु औद्योगिक युग में वायु प्रदूषण गंभीर संकट बन चुका है। कारखानों का धुआं, वाहनों से निकलने वाली विषैली गैसें, प्लास्टिक और पराली का दहन तथा वृक्षों की निरंतर कटाई वायुमंडल को दूषित कर रही हैं। अस्थमा, फेफड़ों के रोग, एलर्जी और श्वसन संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। महानगरों में धुंध और स्माग सामान्य दृश्य बन गए हैं। अतः आवश्यकता है कि पौधारोपण, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण-सुरक्षा को जीवन का अनिवार्य भाग बनाया जाए।

वनस्पतियों की महिमा : भारतीय परंपरा में वृक्षों को देवतुल्य माना गया। ऋग्वेद और अथर्ववेद में वनस्पतियों की स्तुति करते हुए उन्हें जीवनदाता कहा गया है- 'वनस्पते शतवल्शो वि रोह।' अर्थात् 'हे वनस्पति! तुम सौ शाखाओं सहित विकसित हो।' भारतीय आयुर्वेद का आधार भी वनस्पति-विज्ञान है। तुलसी, नीम, पीपल और वट जैसे वृक्षों का धार्मिक महत्व वास्तव में पर्यावरणीय महत्व से जुड़ा हुआ था। पीपल वृक्ष दिन-रात आक्सीजन देने वाला माना जाता है। तुलसी वातावरण को शुद्ध करती है। नीम औषधीय गुणों से भरपूर है। भारतीय समाज ने इन्हें पूजा से जोड़कर इनके संरक्षण की सामाजिक व्यवस्था बनाई थी।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी को होना होगा संवेदनशील। फाइल

भारतीय समाज की अनेक परंपराएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी थीं। इनमें गहन वैज्ञानिकता है। हम पीपल, वट, नीम, तुलसी, अशोक और बेल जैसे वृक्षों की पूजा करते थे। वट-सावित्री व्रत, तुलसी-विवाह और पीपल-पूजन जैसी परंपराओं ने वृक्षों को सांस्कृतिक सुरक्षा प्रदान की। उद्देश्य था- समाज वृक्षों को काटने के बजाय उनका संरक्षण करे। गोवर्धन पूजा और वनदेवी की परंपरा के पीछे वन एवं पर्वत संरक्षण की चेतना थी। त्योहार प्रकृति और ऋतु-चक्र से जुड़े थे। मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, नागपंचमी और छठ जैसे पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के माध्यम थे।

वास्तव में वेदों का पर्यावरण-दर्शन भारत की सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए शाश्वत मार्गदर्शन है। यह धार्मिक कल्पना ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और नैतिक चेतना का समन्वित स्वरूप है। आज अनेक पर्यावरणविद् और चिंतक इस दर्शन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 'इंडिजिनस इकोलाजी' की अवधारणाएं वैदिक जीवन-पद्धति के निकट हैं। आधुनिक विकास के साथ वैदिक जीवन-मूल्यों का समन्वय किया जाए। यदि मानव प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व, संयमित उपभोग और संरक्षण की भावना अपनाए, तो पर्यावरणीय संकटों का समाधान संभव है।

पोस्ट

दिल्ली में ध्वस्त हुई इमारत से यही सवाल सामने आता है कि जब कोई भी गैरकानूनी इमारत बन रही होती है तो सरकारी बाबू/अधिकारी गड़बड़ी करके छुपते कहां हैं?
ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

घरेलू सहायिका के रूप में काम करने से लेकर बंगाल सरकार में राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने तक कलिता मांझी का सफर इसका प्रमाण है कि लोकतंत्र आज भी क्यों मायने रखता है।
राहुल शिवशंकर@RShivshankar

अभिषेक बनर्जी के साथ गलत ही हुआ, लेकिन ये समाज की प्रतिक्रिया थी। भाजपा के लोग इसमें होंगे, मगर वे भी समाज का ही तो हिस्सा हैं। इनको तो अंडे ही पड़े हैं, जबकि और तमाम लोगों की तो जान गई है।
सौरव शर्मा@journosaurav

विराट कोहली क्रिकेट के सबसे बड़े चेज मास्टर हैं। सो उन्हें किंग कोहली कहते हैं। पाटीदार भाग्यशाली कप्तान हैं। कप्तानी के लिए वह विराट की ही पसंद हैं। इंदौर से उभर कर दो आइपीएल खिताबी जीत तक का सफर उन्हें नायक सिद्ध कर रहा।
सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या तृणमूल नेताओं पर हमले उनके प्रति जनता के आक्रोश का नतीजा है?

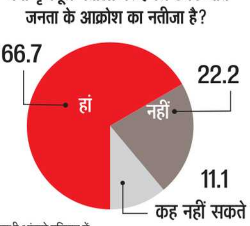

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या अमेरिका-ईरान के बीच कायम युद्धविराम खतरे में पड़ता दिख रहा है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

योगी जी के राज में नाट 'दिस' ओर 'दैट',
बदमाशों के साथ में ओनली 'टिट फार टैट'।
ओनली 'टिट फार टैट' करोगे बच्चू जैसा,
गारंटी के साथ पड़ेगा भरना वैसा!
सुन 'सूर्या' का कत्ल रहें चुप सेक्युलर ढोंगी,
फिर तो 'टिट फार टैट' करेंगे बाबा योगी!!
-ओम प्रकाश तिवारी

99 प्रतिशत आवेदनों का तय समय-सीमा में निपटान

मुंबई: आरबीआइ ने सोमवार को बताया कि उसने मई 2026 में अपने 'नागरिक चार्टर' के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर 99.9 प्रतिशत आवेदनों का निपटान किया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि पिछले महीने उसने कुल 18,763 आवेदनों को निपटारा किया। इसमें लंबित मामले और नए आवेदन शामिल हैं। यह संख्या उन आवेदनों को हटाने के बाद की है जिन्हें अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदकों को वापस भेजा गया था। (प्रेट्र)

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने रिकार्ड 73,890.46 करोड़ रुपये के समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात किया है।
– पी. जवाहर, चेयरमैन, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

संसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलो ग्राम)	डालर	क्रूड (प्रति बैरल)
74,267.34 ▼ 508.40	23,382.60 ▼ 165.15	₹ 1,60,400 ▼ ₹ 2,500	₹ 2,69,700 ▼ ₹ 5,000	₹ 94.95 ▲ ₹ 0.10	$ 94.16

बिजली की मांग बढ़ी, लेकिन कोयला उत्पादन घटा

- मई में बिजली की मांग 11.55 प्रतिशत बढ़ी
- कोल इंडिया का उत्पादन 11.6 प्रतिशत घटा

164.98 अरब यूनिट रही पिछले महीने देश में बिजली की मांग

5.61 करोड़ टन रहा कोल इंडिया का कोयला उत्पादन पिछले माह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश में भीषण गर्मी और लू की स्थिति ने बिजली की खपत को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। मई 2026 में भारत की बिजली खपत 11.55 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 164.98 अरब यूनिट पर पहुंच गई है। पिछले वर्ष मई में यह खपत 147.89 अरब यूनिट थी। पीक आवर में बिजली की मांग भी सरकार के अनुमान को पार करते हुए 2.7082 लाख मेगावाट तक पहुंच गई है जो मई 2025 में यह 2.3099 लाख मेगावाट थी। ऐसे में यह चिंता की बात हो सकती है कि मई 2026 में देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) का उत्पादन 11.6 प्रतिशत घटकर 5.61 करोड़ टन पर आ गया है, जबकि पिछले वर्ष मई में यह 6.35 करोड़ टन था।

देश के कुल कोयला उत्पादन में 80 कोल इंडिया की 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालांकि यह और बात है कि कोयला मंत्रालय इससे चिंतित नहीं है। उसका दावा है कि देश में पर्याप्त कोयला है और उत्पादन जानबूझकर कम किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर, पवन आदि) का विस्तार तेजी से हो रहा है और उनकी अहमियत बढ़ रही है, लेकिन चरम गर्मी के मौसम में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए ताप बिजली संयंत्रों के बिना काम चलाना अभी संभव नहीं है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 18-21 मई 2026 के बीच लगातार बिजली की मांग ने नया रिकार्ड बनाया है। इस दौरान बिजली की मांग 2.57 लाख मेगावाट, 2.60 लाख मेगावाट, 2.65 लाख मेगावाट और 2.71 लाख मेगावाट रही है। जबकि सरकार ने इस वर्ष के लिए अधिकतम बिजली की मांग 2.71 लाख मेगावाट रहने की बात कही थी। साफ है कि बिजली की मांग सरकार के अनुमान को कर गई है। बिजली मंत्रालय ने दावा किया है कि देश में बिजली की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन जमीनी तौर पर देश के कई बड़े राज्यों में बिजली कटौती की सूचनाएं लगातार आ रही हैं।

कोयला आपूर्ति के बारे में कोयला मंत्रालय का डाटा बताता है कि अप्रैल-मई में उत्पादन 10.6 प्रतिशत घटकर 11.22 करोड़ टन रहा, जो पिछले साल 12.56 करोड टन था। सीआइएल की कई सहायक कंपनियों- महानदी कोलफील्ड्स, वेस्टर्न कोलफील्ड्स, भारत कोकिंग कोल और ईस्टर्न कोलफील्ड्स में उत्पादन घट गया है। सिर्फ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में वृद्धि हुई है। चिंता की बात यह है कि मानसून की शुरुआत से पहले ही लगातार दो महीने कोयला का उत्पादन घटा है। आम तौर पर जुलाई से सितंबर के बीच मानसून की वजह से कोयला उत्पादन घटता है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

4.4 प्रतिशत वित्तीय घाटा हासिल करने में सफल रही सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: लेखा महानियंत्रक (सीजीए) ने सोमवार को बताया कि बीते वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार 4.4 प्रतिशत व्यापार घाटे के लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही है। पिछले वर्ष के दौरान वित्तीय घाटा 15,68,936 करोड़ रुपये रहने के अनुमान जताया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2026 में पेश किए गए बजट में इस अनुमान को घटाकर 15,58,492 करोड़ रुपये कर दिया था।

सीजीए के डाटा के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में सरकार का वास्तविक वित्तीय घाटा 15,19,169 करोड़ रुपये रहा है, जो संशोधित अनुमान का 97.5 प्रतिशत है। अप्रैल 2026 में सरकार का वित्तीय घाटा बजट अनुमान का 21 प्रतिशत रहा है। यह किसी वित्त वर्ष के पहले महीने के लिए सामान्य स्तर से काफी अधिक है। यह दर्शाता है कि पिछले महीने राजस्व जुटाने की तुलना में खर्च अधिक हुआ है।

मई में जीएसटी संग्रह 3.2 प्रतिशत बढ़ा

पिछले महीने कुल जीएसटी संग्रह 1.94 लाख करोड़ रुपये रहा, इसी वर्ष अप्रैल में संग्रह 2.43 लाख करोड़ रुपये रहा था

अधिक गिरावट वाले राज्य

राज्य	गिरावट (%में)
दिल्ली	17
पंजाब	5
हिमाचल प्रदेश	27
बिहार	7
असम	13
उत्तराखंड	19
तमिलनाडु	15

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: मई 2026 में जीएसटी संग्रह का उत्साहजनक प्रदर्शन नहीं रहा। पिछले महीने जीएसटी का कुल संग्रह 1,94,184 करोड़ रहा है जो इसी वर्ष अप्रैल में 2.43 लाख करोड़ रुपये रहा था। जीएसटी संग्रह पूरी तरह से वस्तुओं की बिक्री पर निर्भर करता है। ताजा डाटा से पता चलता है कि वस्तुओं की बिक्री मई माह में अप्रैल की तुलना में प्रभावित हुई है। हालांकि, वित्त मंत्रालय का दावा है कि पिछले साल सितंबर महीने में जिन वस्तुओं की जीएसटी दरों में कटौती की गई, उनकी बिक्री में दहाई अंक में इजाफा हुआ है। इस वर्ष मई में जीएसटी संग्रह में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि रही है। मई 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 1.88 लाख करोड़ रुपये रहा था।

इस साल मई में जीएसटी संग्रह में घरेलू बिक्री से मिलने वाला हिस्सा आयात से मिलने वाले राजस्व से कम रहा है। 1.94 लाख करोड़ के कुल जीएसटी में सीजीएसटी 37,397 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 45,143 करोड़ रुपये तो आईजीएसटी 1,11,644 करोड़ रुपये रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मई में रिफंड के बाद जीएसटी का शुद्ध संग्रह 1,66,904 करोड़ का रहा जो पिछले साल समान महीने की तुलना में 3.3 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों (अप्रैल-मई) में कुल जीएसटी संग्रह 4.37 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की समान अवधि के 4.11 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 6.2 प्रतिशत ज्यादा है।

राज्यों के जीएसटी संग्रह मई 2025 की तुलना में पिछले महीने घटा है। इस साल मई में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु के जीएसटी राजस्व में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में गिरावट रही है। उत्तर प्रदेश के जीएसटी संग्रह में 13 प्रतिशत, मध्य प्रदेश और गुजरात में एक-एक प्रतिशत, हरियाणा में आठ प्रतिशत तो कर्नाटक में एक प्रतिशत का इजाफा रहा। महाराष्ट्र व झारखंड में मई में जीएसटी राजस्व में शून्य बढ़ोतरी रही।

एक नजर में

मई में यूपीआइ से 29.9 लाख करोड़ के लेनदेन

नई दिल्ली: गर्मियों की यात्रा और इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के चलते मई 2026 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) के जरिये रिकार्ड 29.90 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए हैं। नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) के अनुसार, पिछले महीने यूपीआइ लेनदेन की संख्या 23.2 अरब रही है। इसी वर्ष अप्रैल में यूपीआइ के जरिये 25.14 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था और यूपीआइ लेनदेन की संख्या 22.35 अरब रही थी। (प्रेट्र)

अप्रैल और मई में दहाई अंक में बढ़ा निर्यात

नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों यानी अप्रैल-मई के दौरान भारतीय निर्यात में दहाई अंक में वृद्धि रही है। वाणिज्य मंत्रालय 15 जून को मई महीने के निर्यात का आधिकारिक डाटा जारी करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि अप्रैल में निर्यात 13.78 प्रतिशत बढ़कर 43.56 अरब डालर रहा है, जो चार साल से भी ज्यादा समय में सबसे अधिक मासिक निर्यात है। इसकी मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बढ़ना रहा है। हालांकि, व्यापार घाटा तीन माह के उच्च स्तर पर रहा है। (प्रेट्र)

एमसीएक्स में सिल्वर-100 फ्यूचर कान्ट्रैक्ट्स लांच

नई दिल्ली: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) ने सोमवार को 'सिल्वर 100' फ्यूचर्स कान्ट्रैक्ट्स लांच किए। इससे खुदरा निवेशक और छोटे ज्वेलर 100 ग्राम जितनी कम मात्रा में भी चांदी में निवेश कर सकेंगे। इससे उस बाजार तक पहुंच का विस्तार हुआ है, जिस पर पहले बड़े संस्थागत निवेशकों का ही दबदबा था। एमसीएक्स की सीईओ प्रवीणा राय ने कहा कि सिल्वर 100 फ्यूचर्स कान्ट्रैक्ट देश के चांदी उद्योग से जुड़े कारोबारियों को कीमतों में उतार-चढ़ाव से खुद को बचाने में मदद करता है। (प्रेट्र)

भारत-ओमान के बीच लागू हुआ व्यापार समझौता

अब 99% भारतीय उत्पाद ओमान को बिना शुल्क भेजे जा सकेंगे, पहले दिन 10 खेप रवाना की गईं

- सेवा क्षेत्र से जुड़े भारतीय पेशेवरों को ओमान में नौकरी के मिलेंगे मौके
- समझौते से ओमान को भारतीय निर्यात 50 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद

नई दिल्ली में सोमवार को भारत-ओमान के बीच सीईपीए लागू होने के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व ओमान के राजदूत इस्सा सालेह अब्दुल्ला अल शिबानी ● एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) सोमवार एक जून से लागू हो गया। इस समझौते पर दोनों देशों ने 18 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षर किए थे। पहले ही दिन देश के विभिन्न बंदरगाहों से शून्य शुल्क पर ओमान के लिए निर्यात की 10 खेप रवाना हुई। अमेरिका के बाद ओमान के साथ द्विपक्षीय समझौता करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ओमान के साथ सीईपीए होने से खाड़ी के विभिन्न देशों के साथ पूर्वी अफ्रीका के देशों को भी भारतीय सामान को आसानी से भेजा जा सकेगा। कृषि से लेकर एमएसएमई और युवाओं को इस समझौते से विशेष लाभ मिलेगा। समझौते के तहत ओमान से भारत को पेट्रोलियम पदार्थ व गैस की आपूर्ति पहले के मुकाबले अधिक मात्रा में होगी। डेरी, कृषि पदार्थ जैसे संवेदनशील उत्पादों को समझौते में शामिल नहीं किया गया है। भारत के 99 प्रतिशत आइटम अब ओमान में बिना शुल्क के भेजे जा सकेंगे। ओमान में निवेश करने वाली भारतीय कंपनी में अब भारत के युवाओं को नौकरी देने में प्राथमिकता दी जाएगी। सर्विस सेक्टर को भी व्यापार समझौते में शामिल किया गया है जिससे भारतीय पेशेवरों को ओमान में नौकरी करने का मौका मिलेगा। समझौते के तहत आयुष केंद्र भी ओमान में खोले जाएंगे। भारत और ओमान के बीच गत वित्त वर्ष 2025-26 में 11.18 अरब डालर का व्यापार किया गया था।

एमएसएमई समेत इन सेक्टरों को मिलेगा लाभ

सीईपीए से एमएसएमई से जुड़े भारत के रोजगारपरक सेक्टर इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स व ज्वेलरी, गारमेंट्स, लेदर आइटम, इलेक्ट्रानिक्स गुड्स, जेनेरिक दवा, समुद्री उत्पाद के निर्यात को मुख्य रूप से लाभ मिलेगा। गोयल ने बताया कि अमेरिका व ब्रिटेन जैसे देश में मंजूरी प्राप्त भारतीय जेनेरिक दवा अगले 90 दिनों में ओमान शून्य शुल्क पर भेजे जा सकेंगे। सोमवार को 12 करोड़ डालर के जेम्स व ज्वेलरी का ओमान में शून्य शुल्क पर निर्यात किया गया। समझौते पर अमल से रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी।

कृषि और प्रोसेस्ड आइटम का भी बढ़ेगा

मधु, काजू, बासमती चावल, मक्खन, बिस्कुट, आम, आलू, प्याज जैसे आइटम अब ओमान को बिना शुल्क जाएंगे। कृषि व प्रोसेस्ड आइटम का ओमान में निर्यात बढ़ने से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु जैसे राज्यों को लाभ मिलेगा। इस समझौते से ओमान को कुल भारतीय निर्यात में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

इंजीनयर से लेकर शिक्षक तक को मिलेगा मौका

समझौते में 127 प्रकार की सेवाओं को शामिल किया गया है। इसके तहत अब कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं के साथ विभिन्न प्रकार के इंजीनियर, हेल्थकेयर कर्मचारी, शिक्षक, वित्त सेवा के जानकार, संचार व पर्यटन से जुड़े पेशेवरों को ओमान में काम करने का मौका मिलेगा। कारोबार के उद्देश्य से जाने वाले भारतीय ओमान में 90 दिनों तक, स्वतंत्र पेशेवर 180 दिनों तक ठहर सकेंगे। कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लगातार चार साल तक ओमान में अपनी सेवा दे सकेंगे।

प्रतिद्वंद्वी देशों पर बढ़त मिलने पर ही अमेरिका से समझौता

- पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौते को लेकर 99 प्रतिशत मुद्दों पर सहमति बनी
- समझौते को लेकर 2-4 जून तक नई दिल्ली में दोनों देशों के वार्ताकारों के बीच होगी बैठक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को बताया कि जल्द ही भारत व अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन यह व्यापार समझौता तभी संभव है, जब शुल्क के मामले में अमेरिका के बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वी देशों पर भारत को बढ़त मिलेगी। मतलब प्रतिद्वंद्वी देशों के मुकाबले भारत पर कम शुल्क लगने पर ही भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए राजी होगा।

अमेरिका अपने सेक्शन 301 के तहत जल्द ही सभी देशों पर फिर से शुल्क लगा सकता है। अभी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, वहां के बाजार में सभी देशों पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगता है जिसकी अवधि आगामी 24 जुलाई को समाप्त हो रही है। गत फरवरी में भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के लिए अपनी सहमति जता चुके हैं। इसके तहत भारत पर अमेरिका 18 प्रतिशत का शुल्क लगाएगा।

गोयल ने बताया कि समझौते के लिए भारत का मुख्य मुद्दा है कि उसे अमेरिका के बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वी देशों से कम शुल्क देना पड़े, चाहे वह शुल्क कुछ भी हो। उन्होंने बताया कि दो से लेकर चार जून तक नई दिल्ली में दोनों देशों के वार्ताकार समझौते के दस्तावेज को अंतिम रूप देने पर चर्चा करेंगे। लगभग सभी बातों पर रजामंदी हो चुकी है। भारत में अमेरिका के राजदूत गोर ने भी बयान दिया है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर 99 प्रतिशत मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और अमेरिका की क्रय शक्ति अधिक होने से अमेरिका में भारतीय निर्यात बढ़ाने का पूरा मौका है।

तीन महीने के उच्च स्तर पर रही मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर

नई दिल्ली, प्रेट्र: इस वर्ष मई में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर तीन महीने के उच्च स्तर पर रही है। इसमें मांग में मजबूती, बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स और नए व्यापार लाभों का प्रमुख योगदान रहा है।

एचएसबीसी इंडिया की ओर से सोमवार को जारी मासिक सर्वे के अनुसार, मई में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआइ) 55 रहा है, जो इसी वर्ष अप्रैल के 54.7 से अधिक है। एचएसबीसी इंडिया का यह सूचकांक नए आर्डर, उत्पादन, रोजगार, आपूर्तिकर्ता वितरण समय और खरीद स्टाक्स की गणना पर आधारित है। एचएसबीसी के भारत में मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी का कहना है कि पिछले महीने घरेलू बाजार ने मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि को प्रेरित किया है।

अप्रैल में 4.9 प्रतिशत की दर से बढ़ा औद्योगिक उत्पादन

नई दिल्ली, प्रेट्र: पश्चिम एशिया संकट के बीच ऊर्जा क्षेत्र में धीमी वृद्धि के कारण अप्रैल 2026 में औद्योगिक उत्पादन 4.9 प्रतिशत की धीमी दर से बढ़ा है। आधार वर्ष को संशोधित करके 2022-23 किए जाने के बाद यह पहला आंकड़ा है। सोमवार को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के अनुसार, अप्रैल 2025 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी। एक बयान के अनुसार, अप्रैल 2026 में चार क्षेत्रों- खनन, मैन्यूफैक्चरिंग, बिजली व गैस आपूर्ति तथा जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन की वृद्धि दर क्रमश: - 5.1 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत रही है।

एमएसएमई के लिए 35 हजार करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और उद्योगों को 35,000 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी दी है।

इस योजना को पांच मई को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसका मकसद 2.55 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट फ्लो उपलब्ध कराना था, जिसमें मौजूदा भू-राजनीतिक संकट से प्रभावित एयरलाइंस के लिए 5,000 करोड़ रुपये भी शामिल थे। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन ने बताया कि 29 मई तक लोन देने वाली संस्थाओं ने लगभग 80,000 आवेदनों को मंजूरी दे दी है, जिनके तहत 35,194 करोड़ रुपये के लोन दिए गए हैं।

पश्चिम एशिया में ताजा संघर्ष से चौथे दिन भी लुढ़के बाजार

508 अंक गिरकर 74,267 पर जाकर बंद हुआ बीएसई सेंसेक्स, एनएसई का निफ्टी 165 अंक लुढ़कर 23,382 अंक पर पहुंचा

मुंबई, प्रेट्र: पश्चिम एशिया में ताजा संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते एफएमसीजी, वित्तीय और आटो शेयरों में बिकवाली के कारण घरेलू शेयर बाजार सोमवार को लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 508.40 अंक की गिरावट के साथ 74,267.34 अंक पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में इसमें 1,164.25 अंक का उतार चढ़ाव रहा और यह 75,367.93 के उच्च स्तर व 74,203.68 के निचले स्तर तक पहुंचा। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 165.15 अंक की गिरावट के साथ 23,382.60 अंक पर बंद हुआ।

वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 3.34 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और यह 94.16 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

सोना-चांदी में गिरावट रही

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से सोमवार को राजधानी दिल्ली में सोने के मूल्य में 2,500 रुपये की गिरावट रही। आल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, अब दिल्ली में सोना 1,60,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसी तरह, चांदी का मूल्य पांच हजार रुपये घटकर 2,69,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

ब्रिटेन की स्काच व्हिस्की को टैरिफ छूट पर विचार संभव

नई दिल्ली, रायटर: यदि ब्रिटेन अपने स्टील सुरक्षा उपायों पर भारत की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहता है तो भारत मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत उसको स्काच व्हिस्की जैसे उत्पादों पर दी गई टैरिफ छूट पर फिर से विचार कर सकता है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर पिछले वर्ष मई में हस्ताक्षर हुए थे और इसके इस साल लागू होने की उम्मीद थी। हालांकि, ब्रिटेन की ओर से अपने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए स्टील आयात पर कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव पेश करने से एफटीए लागू होने में रुकावट आ गई है। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री पीटर काइल मंगलवार को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत के लिए भारत आने वाले हैं। व्यापार समझौते के तहत भारत ने स्काच व्हिस्की पर टैरिफ को शुरू में 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत करने और फिर 10 सालों में इसे और घटाकर 40 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है। इस सौदे में दोनों पक्षों ने कपड़ों से लेकर व्हिस्की और कारों तक, कई तरह के सामानों पर टैरिफ में कटौती पर सहमति जताई है। दोनों देशों को उम्मीद है कि इस समझौता 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार को 34 अरब डालर की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी।

राष्ट्रीय फलक

वाणिज्यिक और पांच किलोग्राम वाले गैस सिलिंडर का मूल्य बढ़ा

42 रुपये बढ़कर 3,113.50 रुपये हुआ दिल्ली में वाणिज्यिक गैस सिलिंडर का मूल्य, एफटीएल का मूल्य 11 रुपये बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : तेल वितरण कंपनियों ने वाणिज्यिक गैस सिलिंडर के मूल्य में 42 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब राजधानी दिल्ली में इस 19 किलोग्राम गैस वाले सिलिंडर का मूल्य बढ़कर 3,113.50 रुपये हो गया है। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य वाणिज्यिक संस्थानों में इस गैस सिलिंडर का इस्तेमाल होता है। इससे पहले एक मई को वाणिज्यिक गैस सिलिंडर के मूल्य में 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जो अब तक की सबसे अधिक वृद्धि थी। इस वृद्धि के बाद वाणिज्यिक गैस सिलिंडर का मूल्य दिल्ली में 3,071.50 रुपये हो गया था।

इसी तरह, पांच किलोग्राम वाले एलपीसी सिलिंडर का मूल्य 11 रुपये बढ़कर 821.50 रुपये हो गया है। इसको फ्री-ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलिंडर भी कहा जाता है। हालांकि, घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलिंडर के मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू रसोई गैस के सिलिंडर की कीमत में मार्च 2026 के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। तब इसकी कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन (एटीएफ) के मूल्य में 27 प्रतिशत की कटौती की गई है। अब इन कंपनियों को एटीएफ 1,100 डालर प्रति किलोलीटर पर मिलेगा। इससे पहले एक मई को विमानन कंपनियों के लिए एटीएफ के मूल्य में 76.55 डालर प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी की गई थी।

पहलगाम हमला: पाकिस्तान के फैसल बैंक ने मोबाइल खरीदने के लिए दी थी वित्तीय सहायता

राज्य ब्यूरो, जागरण ● श्रीनगर

- पहलगाम हमले के आतंकियों से बरामद किए गए थे रेडमी नोट के दो मोबाइल फोन
- चीन से आए इन फोन को हमले से कुछ समय पहले ही किया गया था एक्टिवेट

पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों से बरामद मोबाइल फोन हमले से दो-चार वर्ष पहले ही चीन से पाकिस्तान पहुंच चुके थे, लेकिन इन्हें हमले से कुछ दिन पहले ही एक्टिवेट किया गया था। इनमें एक रेडमी नोट (नारंगी रंग), जो 2021 में आयात किया गया था और एक रेडमी नोट 12 (काला रंग) जो 2023 में चीन से पाकिस्तान में आयात किया गया था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार शाओमी ग्लोबल ने इस संदर्भ में बताया कि रेडमी नोट उस खेप का हिस्सा था, जिसे पाकिस्तान स्थित कंपनी टेक सिरात प्राइवेट लिमिटेड ने आयात किया था। इस कंपनी का कार्यालय कराची के क्लिफ्टन रोड पर स्थित है। पहली जनवरी 2021 को पाकिस्तान पहुंची मोबाइल फोन की खेप के लिए सूचीबद्ध जिस्टिक्स कंपनी "फैसल बैंक" थी, जबकि डिलीवरी का पता स्ट्रीट/02, फैसल हाउस, मेन शांखा, शाहरा-ए-फैसल, कराची, पाकिस्तान दर्ज था। फैसल बैंक पाकिस्तान का प्रमुख इस्लामिक बैंक है और संभवतः बैक ने टेक सिरात को आयात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी जो बड़े आयात के लिए बैंक द्वारा लेटर आफ क्रेडिट जारी करना सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया है।

सूत्रों के अनुसार पहलगाम हमले के साथ फैसल बैंक का कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन पहले कई बार उक्त बैंक का नाम विभिन्न आतंकी संगठनों के खिलाफ जांच में आ चुका है। लश्कर के अलावा अल-कायदा से संबंधित संगठन के खाते इस बैंक में रहे हैं। दूसरा फोन, रेडमी नोट 12, एयर लिंक कम्युनिकेशंस लिमिटेड द्वारा आयात किया गया था, जिसका कार्यालय लाहौर के न्यू गार्डन टाउन में स्थित है। आतंकियों ने सीमा पार बैठे हैंडलरों के साथ संपर्क बनाने में इन मोबाइल का इस्तेमाल किया। आतंकी हैंडलरों से संवाद के लिए बातचीत में समर्थ विशेष एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे।

पाकिस्तान में ईद पर कुर्बानी की खाल के पैसे से आतंकी फंडिंग

नवीन नवाज ● जागरण

- आपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुके आतंकी शिविरों को फिर तैयार करने में जुटे लश्कर और जैश
- पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठनों ने लगभग 80 करोड़ रुपये की खाल जमा की

श्रीनगर : आपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुके आतंकी शिविरों को फिर से तैयार करने में जुटे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने कश्मीर में जिहाद के नाम पर बीते सप्ताह पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर में ईद पर लगभग 80 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्बान किए गए जानवरों की खाल जमा की हैं।

खाल जमा करने के लिए दोनों संगठनों ने एनजीओ के अलावा विभिन्न इलाकों में सक्रिय अपने मौलवियों का भी सहारा लिया। जाहिर है, खाल की कमाई का इस्तेमाल ये दोनों संगठन कश्मीर में आतंकी हिंसा को बढ़ावा देने व खून खराबा करने के लिए करेंगे। खुफिया एजेंसियों के अनुसार, इस वर्ष लश्कर और जैश ने ईद से लगभग एक सप्ताह पहले लोगों को विभिन्न माध्यमों से सूचित करना शुरू किया था कि वह कुर्बानी की खालों को बाजार में बेचने या नष्ट करने के बजाय उनके स्थानीय सेंटरों में उपलब्ध कराएं। इनका उपयोग वह कश्मीर जिहाद के लिए करेंगे। जैश ने अल रहमत ट्रस्ट्र अल अख्तर ट्रस्ट्र और जमात-उल-मोमिनात के बैनर का इस्तेमाल किया है। इन संगठनों ने न सिर्फ स्टाल लगाए थे बल्कि कई जगह खालों को जमा किया है।

1 जून को दक्षिण कोरिया में एक रक्षा कंपनी में विस्फोट और आग लगने की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। यह विस्फोट दक्षिण कोरिया के डेजान शहर में हनवा एयरोस्पेस के राकेट प्रोपेलेंट के उत्पादन लाइन में हुई।

ड्रोन गिराए जाने के बाद अमेरिका का जवाबी हमला, ईरान ने किया पलटवार

अमेरिकी बमबारी के बाद तेहरान ने कुवैत स्थित अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया, शांति वार्ता रोकी

गाजा व लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई तेज होने के बाद ईरान ने अमेरिका संग संदेश का आदान प्रदान बंद किया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान के बीच तनाव फिर खुली सैन्य कार्रवाई में बदलता दिख रहा है। ईरान द्वारा अमेरिकी एमक्यू-1 प्रीडेटर ड्रोन मार गिराए जाने के बाद अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में रडार व ड्रोन नियंत्रण केंद्रों पर हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन-मिसाइल से हमला करने का दावा किया, हालांकि कुवैत ने कहा, उसने सभी हमले विफल कर दिए। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते टकराव से क्षेत्र में शांति बहाली के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। गाजा-लेबनान में इजरायल की बढ़ती सैन्य कार्रवाई के विरोध में ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही वार्ता व संदेशों के आदान-प्रदान को रोकने का एलान कर दिया है। खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आशंकाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब तीन प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

एपी के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकाम) ने सोमवार को कहा कि ईरानी कार्रवाइयों के जवाब में आत्मरक्षा के तहत दक्षिणी ईरान के गोरुक और केशम द्वीप स्थित रडार तथा ड्रोन कमांड एवं कंट्रोल केंद्रों को निशाना बनाया गया। सेंटकाम के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में उड़ रहे अमेरिकी एमक्यू-1 ड्रोन को गिराए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन व दो ड्रोन नष्ट किए गए।

इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में टोही मिशन पर लगे अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनसे क्षेत्र में समुद्री यातायात को खतरा पैदा हो रहा था।

एएनआइ के अनुसार, अमेरिकी हमलों के बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आइआरजीसी) ने दावा किया कि उसने कुवैत में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। हालांकि उसने संबंधित अड्डे का नाम नहीं बताया। कुवैत में अमेरिका के पांच सैन्य ठिकाने हैं। दूसरी ओर कुवैती अधिकारियों ने कहा कि ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया गया।

राष्ट्रपति ट्रंप का इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट एआइ वीडियो। सौ. ट्रुथसोशल

आर्थिक दबाव कम करने के लिए अंतरिम समझौते पर जोर दे रहा ईरान

रायटर के अनुसार, अमेरिका के साथ बढ़े तनाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच ईरान फिलहाल व्यापक समझौते के बजाय सीमित अवधि के अंतरिम समझौते की संभावनाएं तलाश रहा है। फैसले लेने वाले ईरानी अधिकारियों के करीबी सूत्रों के अनुसार, तेहरान का मकसद आर्थिक दबाव कम करना, वित्तीय राहत हासिल करना और घरेलू हालात को स्थिर रखना है। सूत्रों का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल और विवादित मुद्दों पर तत्काल बड़े समझौते से बचना चाहता है। उसकी कोशिश है कि बातचीत जारी रहे, लेकिन ऐसे किसी स्थायी समझौते में जल्दबाजी न हो, जिसके दूरगामी परिणाम उसके लिए नुकसानदेह साबित हों। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि अंतरिम समझौते से देश में नकदी प्रवाह बढ़ाने और कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जरूरी समय मिल सकता है।

आइएएनएस के अनुसार, ईरानी सरकारी टेलीविजन ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का वीडियो भी प्रसारित किया। वीडियो में एक मिसाइल पर लगे पोस्टर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बंद होर्मुज जलडमरूमध्य की पृष्ठभूमि में दिखाया गया था और उस पर लिखा था कि "जब तक अंतिम अमेरिकी सैनिक क्षेत्र नहीं छोड़ देता।"

उधर, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी दोनों देशों के दावों में अंतर सामने आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के सहयोग से 70 जहाज सफलतापूर्वक होर्मुज पार कर चुके हैं और ईरान उन्हें रोक नहीं सका। ब्रिटिश सेना के अनुसार, ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी को तोड़कर निकलने का प्रयास कर रहे गांबिया के झंडे वाले कार्गो जहाज पर अमेरिकी नौसेना ने मिसाइल हमला किया, जिससे उसके इंजन रूम में आग लग गई। वहीं, सोमवार को इराक के कार्गो जहाज पर भी राकेट से हमला हुआ, जिससे जहाज पर बड़ा धमाका हुआ। इस पर हमला किसने किया, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं आइआरजीसी का दावा है कि पिछले 24 घंटों में 15 जहाजों ने अनुमति लेकर यह मार्ग पार किया, जिनमें चार तेल टैंकर शामिल थे।

न्यूयार्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि पिछले तीन सप्ताह में अमेरिकी निगरानी में 70 व्यापारिक जहाजों ने होर्मुज मार्ग का उपयोग किया है। अधिकारियों के अनुसार, जहाजों को ऐसे समुद्री मार्गों से ले जाया गया जो ईरानी तट से अपेक्षाकृत दूर हैं। शिपिंग विशेषज्ञों का कहना है कि कई जहाज पहचान से बचने के लिए अपने ट्रांसपोंडर बंद कर रहे हैं, जिसे "डार्क पैसेज" कहा जाता है।

सेंटकाम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हाकिन्स ने कहा कि अमेरिकी सेना जहाजों को प्रत्यक्ष सुरक्षा नहीं दे रही, बल्कि समन्वय और मार्गदर्शन के जरिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

रायटर के अनुसार, तनाव के बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के गुजरने पर पूरी तरह रोक लगाने पर विचार कर सकता है। ईरानी तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार, तेहरान और उसके सहयोगी समूहों ने होर्मुज के साथ-साथ बाब-अल-मंदेब जैसे अन्य सामरिक समुद्री मार्गों पर भी दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की है।

इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि किसी एक मोर्चे पर युद्धविराम का उल्लंघन सभी मोर्चों पर उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए अमेरिका तथा इजरायल जिम्मेदार होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका लगातार अपनी शर्तें बदल रहा है, जिससे किसी समझौते तक पहुंचना कठिन हो गया है। उधर, इजरायल ने सेना को लेबनान में और भीतर तक जाकर हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्षेत्रीय पक्षों से बातचीत कर तनाव कम करने के प्रयासों पर चर्चा की है। तस्नीम एजेंसी के अनुसार, ईरान ने स्पष्ट किया है कि यदि गाजा और लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई नहीं रुकती और सेना वहां से पीछे नहीं हटती, तो किसी भी नई शांति वार्ता की संभावना नहीं होगी।

पीएम बालेंद्र के बयान पर नेपाली संसद में हंगामा, कार्यवाही स्थगित

- विपक्षी सांसदों ने सीटों पर खड़े होकर विरोध जताया, बालेंद्र से माफी की मांग पर अड़े

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह द्वारा 'भारत की जमीन कब्जाने' संबंधी विवादित बयान ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के कारण सोमवार को नेपाली संसद के दोनों सदनों (प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सभा) की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इस गतिरोध ने भारत-नेपाल सीमा विवाद की संवेदनशीलता को फिर सतह पर ला दिया है। पीएम ने रविवार को कहा था कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है।

विवाद की वजह: नेपाल ने भी किया अतिक्रमण : यह पूरा विवाद रविवार को तब शुरू हुआ जब पीएम ने प्रतिनिधि सभा में सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए कह दिया, "सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत के क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है।" उनके इस बयान से विपक्ष भड़क उठा। हालांकि, उन्होंने कहा, दोनों देश इस मुद्दे को सुलझाने को इतिहासकारों, सर्वेक्षकों व विशेषज्ञों की मदद लेने पर राजी हैं। काठमांडू ने इस संबंध में चीन व ब्रिटेन के सामने भी बात रखी है, पर विपक्ष पीएम से माफी की मांग पर अड़ गया।

बालेंद्र शाह। फाइल

पीएम ने कहा था - नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है

हंगामे की भेंट चढ़ी संसद, जांच कमेटी गठित : सोमवार को जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसद अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध जताने लगे। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहल ने बैठक 20 मिनट के लिए स्थगित की, पर दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा शांत नहीं हुआ। आखिरकार, दोनों सदनों की बैठकें मंगलवार तक के लिए टाल दी गईं। इस बीच, रविवार को प्रतिनिधि सभा में कुछ सांसदों के "अशोभनीय, आपत्तिजनक" व्यवहार की जांच के लिए सचिव प्रकाश अधिकारी के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया गया है। यह कमेटी सात दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

नेतन्याहू ने दिया बेरूत पर हमले का आदेश

- हिजबुल्ला के प्रभाव वाले उपनगर से आमजनों का विस्थापन शुरू
- ईरान बोला, अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने की वार्ता बाधित होगी

बेरूत, रायटर : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान की राजधानी बेरूत के हिजबुल्ला के प्रभाव वाले दक्षिणी भाग पर हमले का आदेश दिया है। नेतन्याहू के इस आदेश के बाद लेबनान में खूनखराबा बढ़ने और अमेरिका-ईरान में युद्ध खत्म करने के लिए हो रही वार्ता में गतिरोध आने की आशंका है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेरी ने कहा है कि लेबनान पर इजरायल का हमला ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म कराने के कूटनीतिक प्रयास को बाधित कर सकता है। साफ किया कि अमेरिका के साथ होने वाले किसी भी समझौते में लेबनान में युद्धविराम भी अहम शर्त होगी।

नेतन्याहू के आदेश और इजरायली सेना की चेतावनी के बाद बेरूत के दक्षिणी भाग के उपनगर दाहियेह में आमजनों ने इलाका छोड़ना शुरू कर दिया है। दक्षिणी लेबनान में लोगों के इलाका छोड़ने के बाद विस्थापन की यह नई लहर है। इजरायल से लगने वाले लेबनान के सीमावर्ती दक्षिणी भाग में इजरायली सेना की कार्रवाई अक्टूबर 2023 से जारी है। उस समय ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने हमास के समर्थन में इजरायल पर राकेट हमले शुरू किए थे, उसी के जवाब में इजरायल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। उसी दौरान हिजबुल्ला संस्थापक

बेंजामिन नेतन्याहू। फाइल

नसरल्ला समेत ज्यादातर नेता मारे गए थे। नेतन्याहू ने ताजा बयान में कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हिजबुल्ला के आतंकी बेरूत के अपने मुख्यालय के निर्देश पर इजरायल के शहरों और नागरिकों पर हमले करें और हम चुपचाप बैठे रहें। कहा, इजरायल लेबनान में भीतर जाकर कार्रवाई करेगा और हिजबुल्ला के पूरे ढांचे को नष्ट करेगा। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर इजरायल और लेबनान के बीच 16 अप्रैल को युद्धविराम समझौता हुआ था लेकिन इजरायली सेना और हिजबुल्ला के बीच लड़ाई नहीं रुक पाई। लेबनान के अधिकारियों के अनुसार दो मार्च से शुरू हुए लड़ाई के ताजा दौर में 3,400 लेबनानी मारे जा चुके हैं जबकि इजरायल ने बताया है कि इस दौरान उसके 25 सैनिक और चार नागरिकों की मौत हुई है।

रूबियो की तनाव कम करने की अपील

तनाव की बढ़ी स्थिति के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की है। रूबियो ने दोनों नेताओं से तनाव को कम करने के प्रयास अमल में लाने की अपील की है। साथ ही आरोप लगाया है कि हिजबुल्ला लेबनान में स्थितियां बिगाड़ रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे खूनखराबे को बढ़ावा मिले। लेबनान की बिगड़ रही स्थितियों के बीच फ्रांस ने पूरे मामले की सुरक्षा परिषद में चर्चा की मांग की है।

फ्रांस ने रूस से जुड़े शैडो फ्लीट टैंकर को रोका

- रूस ने इस कदम को अवैध और अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती के समान बताया
- फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने टैंकर पर कमांडो उतरने वाला वीडियो पोस्ट किया

पेरिस, रायटर : फ्रांस की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में रूसी तेल व्यापार से जुड़े एक शैडो फ्लीट (प्रतिबंधित टैंकर) टैगोर को रोका और उसे फ्रांसीसी मुख्य भूमि की ओर जाने का आदेश दिया। टैगोर चौथा प्रतिबंधित टैंकर है, जिसे फ्रांसीसियों ने रोका है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसे अवैध और अंतरराष्ट्रीय समुद्री डकैती के समान बताया। कहा- इस घटना के जवाब में रूस माल ढुलाई की सुरक्षा तय करने को कदम उठाएगा।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कमांडो को हेलीकाप्टर से टैगोर टैंकर पर रस्सियों के सहारे उतरते दिखाया गया है। यह आपरेशन रविवार को ब्रिटनी से 740 किमी पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुआ था। मैक्रों ने बताया कि रूस के मरमांस्क से रवाना हुए इस टैंकर पर फर्जी झंडा लेकर चलने का संदेह था और ब्रिटेन के सहयोग से इसे रोका गया। जहाज ट्रैकिंग एजेंसी मरीनट्रैफिक के अनुसार, 252 मीटर लंबा टैंकर मेडागास्कर के झंडे तले चल रहा था। फ्रांस के समुद्री सुरक्षा प्राधिकरण,

रूस का शैडो फ्लीट। फाइल

मैरीटाइम प्रीफेक्चर ने कहा कि जहाज के दस्तावेजों की जांच में झंडे की अनियमितता के संबंध में संदेह की पुष्टि हुई। पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए, रूस अपने तेल और गैस के परिवहन के लिए पुराने जहाजों, जिन्हें शैडो फ्लीट के नाम से जाना जाता है, पर निर्भर रहा है। फ्रांस व ब्रिटेन दोनों ने यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों को वित्त पोषित करने वाले तेल राजस्व का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय रणनीति के हिस्से के रूप में ऐसे जहाजों को रोकने का संकल्प लिया है।

कजाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे दो भारतीय छात्रों की मौत

नई दिल्ली, एएनआइ : कजाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे दो भारतीय छात्रों की तैराकी करते समय डूब जाने से मौत हो गई। राजस्थान निवासी बृजराज मीना और निखिल कुरी करागंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष के छात्र थे।

आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआइएमए) डाक्टर्स एसोसिएशन ने विदेश मंत्रालय को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर कजाकिस्तान से छात्रों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय को लिखे पत्र में एफएआइएमए डाक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि डा. मो. मोमिन खान ने सरकार से शोक संतप्त परिवारों को हर संभव मदद प्रदान करने का अनुरोध किया है। डा. खान ने इस बात पर जोर दिया कि शोक संतप्त परिवार एक अकल्पनीय त्रासदी से गुजर रहे हैं और उन्हें अधिकारियों से हर संभव सहायता मिलनी चाहिए।

भारतीय स्वास्थ्य कर्मी को ब्रिटेन में काम नहीं देने पर 28 हजार पाउंड का हर्जाना

- प्रायोजक कंपनी के काम नहीं देने पर ब्रिटिश न्यायाधिकरण ने सुनाया फैसला
- 40 घंटे के कार्य सप्ताह का वेतन और छुट्टी का भुगतान देने की घोषणा की

लंदन, प्रेट्र: ब्रिटेन में वैध तरीके से काम करने आए एक भारतीय स्वास्थ्य कर्मी को उसकी प्रायोजक कंपनी के काम देने में नाकाम रहने पर ब्रिटिश न्यायाधिकरण ने उसे बड़ा हर्जाना व छुट्टी के भुगतान की धनराशि देने का फैसला सुनाया है। इसमें 28,000 पाउंड से अधिक की खोई हुई उसकी मजदूरी शामिल है। कोर्ट का कहना है, वह बतौर कुशल कामगार यहां तैयार, सक्षम और इच्छुक होकर आया था, पर उसके स्पांसर कंपनी ने उसे पहले से तय रोजगार नहीं दिया।

33 वर्षीय शाबिन शाजी स्वास्थ्य और देखभाल कार्यकर्ता वीजा से ब्रिटेन में आए थे और स्वान केयर साल्यूशंस लिमिटेड से जरूरी प्रायोजन प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। उन्होंने हाल ही में बर्मिंघम में एक रोजगार न्यायाधिकरण को बताया कि प्रायोजक ने कभी उन्हें काम नहीं दिया या भुगतान नहीं किया, जो कि मजदूरी से अवैध कटौती के बराबर था। रोजगार न्यायाधीश एडमंड्स ने निष्कर्ष निकाला कि दावेदार (शाजी) 15 अप्रैल, 2023 से 21 अप्रैल, 2024 तक रोजगार में था। यह 40 घंटे के कार्य सप्ताह के आधार पर 22,880 पाउंड वार्षिक की कुल वेतन पर आधारित था। गत माह सुनवाई में कंपनी को अवैतनिक मजदूरी, छुट्टी का भुगतान और उपचार लागत के अलावा कानूनी कार्रवाई के खर्च कवर करने का निर्देश दिया गया। शाजी, जो केरल से वेस्ट मिडलैंड्स के स्टैफर्ड में प्रवासित हुए थे, वीजा प्रतिबंधों के कारण ब्रिटेन में कहीं और रोजगार की तलाश नहीं कर सकते थे। उन्होंने अंततः वैकल्पिक पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त कर लिया, लेकिन तब तक उन्हें काफी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

मलेशिया में बच्चे नहीं चला सकेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम

कुआलालंपुर, एपी : मलेशिया ने सोमवार को 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के इंटरनेट मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगाने वाले नियम को लागू कर दिया है। नियम के तहत इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी और 16 वर्ष से कम आयु के यूजर्स को अकाउंट बनाने से रोकना होगा। ये नियम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटाक और यूट्यूब सहित अन्य पर लागू होंगे। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट (25 लाख अमेरिकी डालर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री और साइबरबुलिंग से बचाना है। आस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के इंटरनेट मीडिया उपयोग पर आयु-आधारित प्रतिबंध या आवश्यकताएं लागू की हैं या इसे लागू करने की घोषणा की हैं।

अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों की सूची में शामिल होने का ट्रंप का सपना फिर जागा

- ट्रंप ने माउंट रशमोर की चट्टानों पर उकेरी गई अपनी एआइ जनरेटेड तस्वीर साझा की
- इस चट्टान पर वाशिंगटन, जेफरसन, रूजवेल्ट और लिंकन की तस्वीरें उकेरी गई हैं

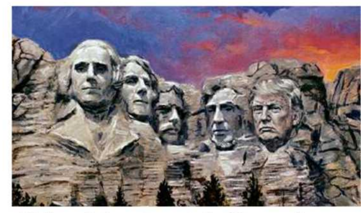
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंटरनेट मीडिया पर जारी एआइ तस्वीर। सौ. ट्रुथसोशल

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों जार्ज वाशिंगटन, थामस जेफरसन, थियोडोर रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन की सूची में शामिल होने का ट्रंप का सपना फिर जाग गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माउंट रशमोर पर अंकित ऐतिहासिक अमेरिकी नेताओं के साथ अपनी तस्वीर वाली एक एआइ जेनरेटेड तस्वीर प्रसारित की है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर तस्वीर को बिना किसी टिप्पणी के पोस्ट किया है। माउंट रशमोर राष्ट्रीय स्मारक दक्षिण डकोटा के कीस्टोन में ब्लैक हिल्स की ग्रेनाइट चट्टान पर उकेरी गई विशाल प्रतिमा है। इस स्मारक में चार पूर्व राष्ट्राध्यक्षों की 60 फुट ऊंची प्रतिमाएं हैं, जो अमेरिका के जन्म, क्षेत्रीय विकास, आर्थिक प्रगति व संरचनात्मक स्थायित्व का प्रतीक हैं।

मूल मूर्तिकार गुटजोन बोर्ग्लम ने अमेरिकी विरासत के शुरुआती 150 वर्षों को समाहित करने के लिए इन विशिष्ट राजनेताओं का चयन किया था। इस संदर्भ में, जार्ज वाशिंगटन गणतंत्र की स्थापना व स्वायत्तता के लिए क्रांतिकारी संघर्ष का प्रतीक हैं, जबकि थामस जेफरसन इसके क्षेत्रीय विस्तार को दर्शाते हैं। वहीं, थियोडोर रूजवेल्ट को राष्ट्रीय उन्नति और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदय का प्रतीक माना गया है, वहीं अब्राहम लिंकन अमेरिकी गृहयुद्ध की दरारों के बीच राष्ट्रीय संरक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राष्ट्रीय स्मारक में अपने आपको शामिल कराने की ट्रंप की महत्वाकांक्षा 2018 में सामने आई थी, जब उन्होंने दक्षिण डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम से कहा था, चट्टान पर खुद की तस्वीर उकेरना उनका सपना है। उन्होंने इस विचार का लगातार समर्थन किया है। ट्रंप का तर्क है उनके शासनकाल में हासिल उपलब्धियां स्मारक में उनके स्थान को उचित ठहराती हैं।

शादी के कुछ घंटे बाद हेलीकाप्टर हादसा, भारतीय मूल के दूल्हे और पायलट की मौत

- जार्जिया में खराब मौसम के बीच हुआ हादसा, नवविवाहिता दुल्हन गंभीर सदमे में
- दूल्हा खुद भी था विमान का पायलट, उड़ान से पहले जताई थी खराब दृश्यता को लेकर चिंता

शादी के बाद डेव फिजी और जेस्नी। इंटरनेट मीडिया

न्यूयार्क, प्रेट्र: अमेरिका के जार्जिया राज्य में एक दर्दनाक हेलीकाप्टर हादसे में भारतीय मूल के नवविवाहित दूल्हे और हेलीकाप्टर पायलट की मौत हो गई, जबकि दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हादसा शादी समारोह के कुछ ही समय बाद खराब मौसम के बीच हुआ।

रिपोर्ट के मुताबिक 26 वर्षीय डेव फिजी और उनकी नवविवाहिता पत्नी जेस्नी शुक्रवार रात शादी के बाद एक विशेष विदाई उड़ान के तहत राबिन्सन आर-66 हेलीकाप्टर से डीकैल्ब-पीचट्री एयरपोर्ट जा रहे थे। हेलीकाप्टर का संचालन पायलट निखिल नरगुंदकर कर रहे थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हेलीकाप्टर जार्जिया के डासनविल इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

हादसे में डेव फिजी और पायलट निखिल नरगुंदकर की मौत हो गई, जबकि 25 वर्षीय जेस्नी को बचा लिया गया। वह छह घंटे तक मलबे में दबी रहीं। उनका इलाज अटलांटा के एक अस्पताल में चल रहा है। बताया गया है कि दंपती भारतीय मूल के थे और उनके परिवार की जड़ें केरलम से जुड़ी हैं। डेव फिजी अमेरिकी एयरलाइन डेल्टा में पायलट के रूप में कार्यरत थे।

रिपोर्ट के अनुसार, शादी समारोह में करीब 400 मेहमान शामिल हुए थे। विवाह के बाद नवदंपती को हेलीकाप्टर के जरिए होटल तक पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण यह खुशी कुछ ही मिनटों में मातम में बदल गई।

डेव के पिता जार्ज फिजी ने बताया कि उनके बेटे ने उड़ान से पहले खराब मौसम और बेहद कम दृश्यता को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि डेव ने पायलट से कहा था कि ऐसी स्थिति में सामान्यतः उड़ान नहीं भरी जाती। परिवार के अनुसार, बाद में जेस्नी ने बताया कि पायलट ने ऊंचाई पर जाकर उड़ान भरने की बात कही थी। अमेरिका का राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) हादसे की जांच कर रहा है।

इजरायल बोला, हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं

- रूवेन अजार ने इसके लिए यहूदी विरोधी बयानों का दिया हवाला
- कहा, शांति की पहल में शामिल होने के लिए सोच में बड़े बदलाव की जरूरत

नई दिल्ली, एएनआइ: भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने सोमवार को कहा,इजरायल को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के यहूदी विरोधी बयानों का हवाला दिया।

ग्रेटर वेस्ट एशिया फोरम, इंडिया (जीडब्लूयएएफआइ) को संबोधित करते हुए अजार ने हिजबुल्लाह के साथ तनाव, पश्चिम एशिया में संघर्ष व क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की अहम भूमिका पर भी बात की। पाकिस्तान की ओर से अब्राहम समझौता खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अजार ने कहा, शांति की पहल में शामिल होने के लिए सोच में बड़े बदलाव की जरूरत है। उन्हें (पाक को) इजरायल की जमीन पर हमारे मूल निवासियों के अधिकारों को पहचानने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि इजरायल इस इलाके का हिस्सा है, न सिर्फ हमारे लेखों बल्कि इस्लामी लेखों के हिसाब से भी। जो कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं है, उसके अब्राहम समझौते में शामिल होने की उम्मीद नहीं है। अजार ने भारत की बढ़ती आर्थिक हालात की तारीफ की और इसे पश्चिम एशिया में भविष्य की खुशहाली के लिए जरूरी बताया। कहा, भारत को बड़ी भूमिका निभानी है क्योंकि क्षेत्र में वह सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिकी है। अगर पश्चिम एशिया में स्थिरता होगी तो लाखों करोड़ डालर का व्यापार होगा। बहुत सारा निवेश होगा। हमें स्थायित्व हासिल करना है, चरमपंथी तत्वों पर अंकुश लगाना है। फिर इस क्षेत्र के सभी देश खुशहाली का मजा ले पाएंगे। कहा, हम लेबनान के साथ शांति वार्ता के जरिये युद्धविराम की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ऐसा स्वतंत्र लेबनान बने जो हिजबुल्लाह की कोशिश को बेअसर कर सके।" अजार ने ईरान पर वैश्विक दबाव बनाने की अपील की। कहा, ईरानी सरकार अपनी हाल की सैन्य पराजय को पलटने की कोशिश कर रही है।

पाकिस्तान कर रहा भारत के जरिये तालिबान को वित्त पोषण का दुष्प्रचार

- भारत सरकार ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के वीडियो को डीपफेक बताया
- पाकिस्तानी गतिविधियों को नकारा, कहा-भारतीय जनरल ने ऐसा बयान नहीं दिया

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत सरकार ने सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर फैल रहे झूठे दावों का खंडन किया और चेतावनी दी कि पाकिस्तान के प्रचार खातों द्वारा भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बारे में एक एआइ-जनित डीपफेक वीडियो साझा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनता को गुमराह करना है।

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआइबी) के फैक्ट-चेक ने एक बयान में कहा, इंटरनेट मीडिया पर "पाकिस्तानी प्रचार खाते एक डिजिटल रूप से संपादित वीडियो का प्रचार कर रहे हैं, जिसमें झूठा दावा किया गया है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तालिबान के साथ भारत की संलिप्तता के बारे में टिप्पणी की।" जनरल द्विवेदी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वायरल क्लिप को डिजिटल रूप से संपादित किया गया है।" यह संपादित क्लिप 150वें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के पासिंग आउट परेड (पीओपी) के बाद एक हालिया प्रेस कांफ्रेंस के मूल फुटेज को बदलती है, जिसमें असल में जनरल द्विवेदी ने कहा था कि 'आपरेशन सिंदूर' जारी है और भारत की तीनों सेनाएं किसी भी भविष्य की आपात स्थिति के लिए उच्च स्तर की तत्परता बनाए रख रही हैं, जिसमें उन्होंने संभावित 'आपरेशन सिंदूर 2.0' का भी उल्लेख किया था।

आरसीबी चैंपियन

धौनी, रोहित और गंभीर के बाद सबसे ज्यादा आइपीएल ट्राफी जीतने वाले कप्तान बने रजत | आरसीबी के लिए जो कोहली, कुंबले और द्रविड़ नहीं कर पाए, वो रजत ने कर दिखाया

आइपीएल ट्राफी चूमते रजत पाटीदार ● एएफपी

आइपीएल का नया जागीरदार रजत पाटीदार

नितिन नागर ● जागरण

नई दिल्ली : महेंद्र सिंह धौनी ने चेन्नई सुपरकिंग्स और रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए पांच-पांच आइपीएल ट्राफी जीतीं। गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए यह कारनामा दो बार किया। विराट कोहली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और फाफ डु प्लेसिस जैसे दिग्गजों के कप्तानी करने के बावजूद रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) 17 साल तक इस चमचमाती ट्राफी के लिए तरसती रही लेकिन 20 वर्षीय रजत पाटीदार ने लगातार दो साल में दो ट्राफी दिलाकर यह दिखा दिया कि यह आइपीएल ट्राफी सिर्फ कुछ टीमों की जागीर नहीं है। अब वह इस ट्राफी के नए जागीरदार हैं।

अनसोल्ड रहे थे पाटीदार: मध्यप्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले रजत की कहानी भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। 2022 की आइपीएल नीलामी में वह अनसोल्ड रहे थे। किसी भी टीम ने उन्हें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था कि आइपीएल में उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उसी साल आरसीबी ने उन्हें चोटिल लवनीत सिसोदिया के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। उस सीजन में एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपरजायंट्स के विरुद्ध खेली गई 54 गेंद में 112 रन की शतकीय पारी ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

लगातार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने टीम में अपनी जगह पक्की की और आरसीबी प्रबंधन का भरोसा जीत लिया। 2025 में जब आरसीबी ने फाफ डु प्लेसिस को हटाकर कप्तानी में बदलाव का फैसला किया तो सबको उम्मीद थी कि टीम विराट कोहली को फिर से कप्तानी का दायित्व सौंपेगी लेकिन फ्रेंचाइजी ने रजत पाटीदार पर दांव लगाया। यह फैसला कई लोगों को चौंकाने वाला लगा, लेकिन पाटीदार ने साबित कर दिया कि नेतृत्व नाम से नहीं, प्रदर्शन और सोच से होता है। आज वही आरसीबी को दो ट्राफियां जिताने वाला कप्तान बन गया है। पाटीदार ने बीते सत्र में 192.69 के स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाए। उनकी कप्तानी में आरसीबी ने न सिर्फ खिताब का सूखा खत्म किया बल्कि लगातार दो ट्राफियां जीतकर इतिहास भी रच दिया। शांत स्वभाव, दबाव में संयम और खिलाड़ियों पर भरोसा रखने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक सफल कप्तान बना दिया। मैदान पर वह कभी भावनाओं में बहते नजर नहीं आते, लेकिन उनके फैसलों में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है।

रजत पाटीदार की कप्तानी की कला केवल आइपीएल तक सीमित नहीं है। घरेलू क्रिकेट में भी वह मध्य प्रदेश के कप्तान हैं। उनकी अगुआई में मध्य प्रदेश की टीम ने 2024 के सैयद मुश्ताक अली ट्राफी फाइनल तक का सफर तय किया और उपविजेता रही। इससे साफ है कि उनकी नेतृत्व क्षमता किसी एक टूर्नामेंट तक सीमित नहीं है। अनसोल्ड रहने का दर्द, खुद को साबित करने का संघर्ष और फिर देश की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी का सफल कप्तान बनने का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

रजत ने साबित कर दिया कि अवसर मिलने पर संघर्ष करने वाले खिलाड़ी इतिहास लिख सकते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक कप्तान की सफलता नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और मेहनत की जीत की कहानी है।

पाटीदार ने भगदड़ में मारे गए प्रशंसकों को समर्पित की जीत : पाटीदार ने टीम की दूसरी खिताबी जीत को पिछले साल आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में मारे गए 11 प्रशंसकों को समर्पित किया। मैच के बाद उन्होंने कहा, मैं हमेशा ये ट्राफी उन्हें समर्पित करना चाहूंगा। मेरे पास भावनाएं बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं।

पिछले साल के हादसे से सबक लेकर इस बार विजय जुलूस नहीं निकालेगी आरसीबी

बेंगलुरु : पिछले साल की भगदड़ और 11 लोगों की मौत को ध्यान में रखते हुए आरसीबी ने आइपीएल में लगातार दूसरी खिताबी जीत के लिए विजय जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया है। आरसीबी के एक सूत्र ने बताया, बेंगलुरु में किसी भी प्रकार का जश्न मनाने की संभावना बहुत कम है। कुछ दिशानिर्देश निर्धारित हैं और हमें उनका पालन करना होगा। बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार सिंह ने कहा कि हम किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं देंगे। यदि कोई जश्न मनाना चाहता है तो वह घर के अंदर मना सकता है।

> कप्तानी का मेरा तरीका अलग है। मैं ज्यादा खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता, लेकिन खेल की स्थिति से भी पूरी तरह वाकिफ रहता हूं। मुझे प्रबंधन और खिलाड़ियों दोनों का भरपूर समर्थन मिला।
> – **रजत पाटीदार,** कप्तान, आरसीबी

आरसीबी के लुइस एनरिक हैं एंडी

एंडी फ्लावर

अहमदाबाद, प्रेट्र : आइपीएल ट्राफी जीतने के बाद विराट कोहली, रजत पाटीदार और भुवनेश्वर कुमार की जमकर प्रशंसा हो रही है, लेकिन एक और व्यक्ति है जिसने टीम की कायापलट में अहम भूमिका निभाई है। यह व्यक्ति हैं एंडी फ्लावर, जो आरसीबी के मुख्य कोच हैं। फ्लावर ने आरसीबी को उसी तरह से बदला है जैसे लुइस एनरिक ने फ्रेंच फुटबाल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) को विजेता बनाया। संयोगवश, एनरिक ने आइपीएल फाइनल से एक दिन पहले अपनी टीम को चैंपियंस लीग में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में योगदान दिया। जब फ्लावर ने अगस्त 2023 में कमान संभाली, तब आरसीबी अपने पहले आइपीएल खिताब की तलाश में थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उस समय आरसीबी आइपीएल की पीएसजी थी। उन्होंने चुपचाप काम किया और अब आरसीबी 2025 और 2026 की चैंपियन है।

विराट व अनुष्का के साथ जश्न मनाता भुवनेश्वर और क्रुणाल का परिवार ● प्रेट्र

आरसीबी के पास भी स्टार खिलाड़ियों की कमी नहीं थी, लेकिन वह चैंपियन नहीं बन पा रही थी। विराट कोहली के अलावा एबी डीविलियर्स, क्रिस गेल, डेल स्टेन, शेन वाटसन और युवराज सिंह जैसे शानदार खिलाड़ी भी रहे, लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। फ्लावर ने अपने अनुभव से आरसीबी को विजेता बना दिया। उन्होंने 2005 में इंग्लैंड को एशेज, 2012 में भारत में टेस्ट सीरीज और 2010 में टी20 विश्व कप दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्लावर ने आरसीबी की गेंदबाजी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। भुवनेश्वर कुमार को 10.75 करोड़ रुपये में खरीदना एक मास्टर-स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने दो आइपीएल सत्र में 45 विकेट लिए। कप्तान पाटीदार ने फ्लावर की क्षमता की प्रशंसा की और कहा कि वह सर्वश्रेष्ठ कोच में से एक हैं।

आरसीबी के प्रशंसकों का कई शहरों में हुड़दंग

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: आइपीएल में रविवार रात गुजरात टाइटंस को हराकर चैंपियन बनी आरसीबी के प्रशंसकों ने मेजबान सिटी अहमदाबाद के बाद दक्षिण भारत के कई शहरों में जश्न मनाने के नाम पर जमकर हुड़दंग काटा। हैदराबाद, बेंगलुरु सहित आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई अन्य शहरों से इस तरह की घटनाएं सामने आईं। हैदाराबाद में तो पटाखे जला रहे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे प्रशंसकों को काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। इन घटनाओं की कई वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद के स्थानीय थाने में इस मामले में 17 लोंगो विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। हैदराबाद में प्रशंसक जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। विशेषकर सचिवालय के पास इस तरह की घटनाएं अधिक हुईं। वहीं कुछ लोग तो गाड़ियों पर चढ़कर नाचे।

हुड़दंग करते प्रशंसकों पर लाठी चार्ज करती पुलिस ● वीडियो ग्रैब

टाइटंस के खिलाड़ियों को ले जा रही बस से निकला धुआं

अहमदाबाद, प्रेट्र: गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए सुरक्षा को लेकर एक चिंताजनक घटना सामने आई है। आइपीएल फाइनल में आरसीबी से हारने के बाद जब टीम बस उन्हें वापस होटल ले जा रही थी, तभी एक शार्ट सर्किट के कारण बस खराब हो और उसके अंदर धुंआ फैल गया। हालांकि सभी खिलाड़ियों व स्टाफ सदस्य जल्द ही बस से बाहर निकल आए। टीम के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और घटना में उन्हें कोई चोट नहीं आई है। बाद में टीम को दूसरी बस से भेजा गया।

खेल डायरी

टिम अगले आइपीएल सत्र के एक मैच से निलंबित

अहमदाबाद, प्रेट्र : रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टिम डेविड को सोमवार को आइपीएल के अगले सत्र के लिए एक मैच के लिए निलंबित कर दिया गया। गुजरात के विरुद्ध फाइनल मैच में उन्हें मैदान पर मौजूद अंपायर नितिन मेनन की ओर आक्रामक तरीके से आइस बैग फेंकने का दोषी पाया गया। यह घटना पहली पारी के 10वें ओवर में एक विकेट गिरने के समय हुई। उन पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया। 30 वर्षीय डेविड को अपने इस अपराध के लिए दो डिमेरिट अंक मिले। इससे उनके डिमेरिट अंक पांच हो गए हैं, जिस पर उन्हें एक मैच के लिए निलंबित कर दिया गया।

दिव्यांशी ने फीडर सीरीज जीत रचा इतिहास

प्रिस्टिना, प्रेट्र : 15 वर्षीय दिव्यांशी भौमिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। दुनिया की 211वीं रैंक वाली इस युवा भारतीय स्टार ने पांच गेम के रोमांचक फाइनल में चीनी ताइपे की ये यी-तियान (दुनिया की 38वीं रैंक) को 3-2 (8-11, 11-8, 11-5, 7-11, 11-7) से हराया। दिव्यांशी ने अपनी साथी भारतीय किशोरी सिंड्रेला दास के साथ मिलकर महिला डबल्स का स्वर्ण पदक भी जीता।

नार्वे शतरंज में चारों भारतीयों को मिली हार

ओस्लो, प्रेट्र : नार्वे शतरंज टूर्नामेंट में भाग ले रहे चारों भारतीय खिलाड़ियों का छठे दौर में प्रदर्शन निराशाजनक रहा और उन सभी को हार का सामना करना पड़ा। पिछले दौर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विश्व चैंपियन डी गुकेश अपना विजय अभियान जारी नहीं रख पाए, जबकि आर प्रगनानंद के बाद दिव्या देशमुख और कोनेरू हंपी भी हार गईं। भारतीय खिलाड़ियों को जहां निराशा हाथ लगी, वहीं मौजूदा चैंपियन और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने क्लासिकल में जीत दर्ज करके खुद को खिताब की दौड़ में शामिल कर दिया है। उन्होंने अलीरेजा फिरोजा को हराया। वेस्ली सो ने प्रगनानंद पर क्लासिकल गेम में जीत दर्ज की।

वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा यह सीजन

ट्राफियों के साथ वैभव सूर्यवंशी ● आइपीएल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : आइपीएल 2026 का खिताब भले ही आरसीबी ने जीता हो, लेकिन ये सीजन राजस्थान रायल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाएगा। वैभव ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से हर किसी को अपना मुरीद बना दिया। वैभव ने 16 मैच में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए, जिनमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं। वैभव ने कुल 72 छक्के लगाए और यूनिवर्सल बास क्रिस गेल का रिकार्ड तोड़ा। वह आरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बने।

इस सीजन में कैगिसो रबादा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह से लेकर तमाम दिग्गज तेज गेंदबाजों ने वैभव के विरुद्ध अलग-अलग प्लानों के साथ गेंदबाजी की, लेकिन किशोर बल्लेबाज ने ना सिर्फ हर किसी का डटकर सामना किया। बुमराह की पहली ही गेंद पर लगाया गया उनका छक्का उनकी सबसे अच्छी यादों में से एक रहेगा।

वैभव ने आरेंज कैप के अलावा मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी, इमर्जिंग प्लेयर आफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर आफ द सीजन और सुपर सिक्सेस आफ द सीजन का अवार्ड अपने नाम किया। वैभव को कुल 45 लाख रुपये की इनामी राशि और एक टाटा सिएरा कार मिली।

टेस्ट में खराब रोशनी के कारण खेल बाधित होने पर फ्लड लाइट में गुलाबी गेंद से पूरा हो सकता है मैच

अहमदाबाद, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने अहमदाबाद में हुई दो दिनों की वार्षिक बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। इनमें खराब रोशनी के कारण खेल बाधित होने की स्थिति में टेस्ट मैचों में ट्रायल के तौर पर गुलाबी गेंद के उपयोग की अनुमति दी है। इसके अलावा ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मुख्य कोच को मैदान पर जाकर खिलाड़ियों से रणनीति पर चर्चा करने की भी छूट दी गई है।

आइसीसी के अनुसार, यदि किसी टेस्ट मैच में खराब रोशनी के कारण खेल रुकने की आशंका हो तो दोनों टीमों की पूर्व सहमति से गुलाबी गेंद का उपयोग किया जा सकेगा। मैच की शुरुआत सामान्य लाल गेंद से होगी, लेकिन यदि दिन के अंतिम सत्र में रोशनी कम हो जाए तो फ्लडलाइट में गुलाबी गेंद से शेष ओवर पूरे कराए जा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी दिन 90 ओवरों में से 75 ओवर लाल गेंद से पूरे हो चुके हों और रोशनी कम होने के कारण अंतिम 15 ओवर प्रभावित होने की संभावना हो, तो उन ओवरों में गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि यह व्यवस्था तभी लागू होगी जब सीरीज शुरू होने से पहले दोनों टीमों के बीच इस पर सहमति बन जाए। आइसीसी ने खराब रोशनी की समस्या से निपटने के लिए नई प्रकाश तकनीक पर शोध को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना में आइसीसी और एमसीसी संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं विकास कार्यों को वित्तीय सहायता देंगे। खेल के नियमों में एक और बड़ा बदलाव करते हुए आइसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मुख्य कोच या उनके प्रतिनिधि को मैदान पर जाकर खिलाड़ियों से चर्चा करने की अनुमति दे दी है। यह व्यवस्था टी20 क्रिकेट के रणनीतिक टाइम-आउट की तर्ज पर लागू होगी। साथ ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 15 मिनट का निर्धारित अंतराल अनिवार्य किया गया है और बल्लेबाजों को खेल दोबारा शुरू होने पर तुरंत तैयार रहना होगा।

आइसीसी की वार्षिक बोर्ड बैठक में लिए गए अहम निर्णय, टेस्ट में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मुख्य कोच से बातचीत की अनुमति

अन्य प्रमुख निर्णय

- गेंदबाजों के संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन (चकिंग) पर निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए अब मैदानी अंपायरों को हाक आई डाटा तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इससे किसी गेंदबाज की गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलेगी।
- आइसीसी बोर्ड ने लेग-साइड वाइड्स के ट्रायल नियम को स्थायी रूप से अपनाने का भी फैसला किया है। सभी नए खेल नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे।

गुलाबी गेंद

महिला क्रिकेट की विंडो में बदलाव

महिला क्रिकेट से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में आइसीसी महिला चैंपियंस ट्राफी 2027 की विंडो बदलने का निर्णय शामिल है। अब यह टूर्नामेंट जून-जुलाई के बजाय 14 से 28 फरवरी 2027 के बीच आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आइसीसी ने महिला इमर्जिंग नेशंस ट्राफी 2026 को 10 टीमों वाले नए टूर्नामेंट के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें पांच पूर्ण सदस्य और पांच एसोसिएट सदस्य देश हिस्सा लेंगे।

आइसीसी ने क्रिकेट कनाडा को किया निलंबित

प्रशासनिक मामलों में आइसीसी ने गंभीर शासन संबंधी अनियमितताओं के कारण क्रिकेट कनाडा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हालांकि कनाडा की राष्ट्रीय टीमों को आइसीसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति बनी रहेगी। क्रिकेट कनाडा को आइसीसी फंडिंग नियंत्रित व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका उपयोग केवल राष्ट्रीय टीम के लिए किया जा सकेगा।

जोकोविक के बाद फोंसेका ने रूड को किया बाहर

पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे ब्राजील के युवा स्टार फोंसेका, कोबोली-बेरेटिनी ने भी अगले दौर में बनाई जगह

जोआओ फोंसेका ● एएफपी

पेरिस, रायटर : ब्राजील के 19 वर्षीय युवा स्टार जोआओ फोंसेका ने फ्रेंच ओपन में अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए दो बार के उपविजेता और 15वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड को हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फोंसेका ने चौथे दौर के मुकाबले में रूड को 7-5, 7-6 (8), 5-7, 6-2 से पराजित किया।

इस टूर्नामेंट में पहले ही नोवाक जोकोविक को बाहर का रास्ता दिखा चुके फोंसेका ने एक बार फिर साबित किया कि वह भविष्य ही नहीं, वर्तमान के भी बड़े दावेदार बन चुके हैं।

पेरिस के प्रतिष्ठित फिलिप चेट्रीर कोर्ट पर खेले गए मुकाबले में युवा ब्राजीलियाई खिलाड़ी ने दबाव के क्षणों में बेहतरीन खेल दिखाया और अपनी परिपक्वता से सभी को प्रभावित किया। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन फोंसेका ने 12वें गेम में सर्विस ब्रेक हासिल कर सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट में भी मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। दोनों खिलाड़ियों ने जोरदार शाट लगाए और सेट टाईब्रेक तक पहुंचा। यहां रूड के पास तीन सेट प्वाइंट थे, लेकिन वह उन्हें भुना नहीं सके और फोंसेका ने टाईब्रेक जीतकर मैच पर मजबूत पकड़ बना ली। तीसरे सेट में रूड ने वापसी करते हुए सेट जीत लिया और मुकाबले को जीवित रखा। हालांकि चौथे सेट में फोंसेका ने फिर अपना स्तर ऊंचा किया। उन्होंने दो बार सर्विस ब्रेक हासिल किए और फुटबाल जैसे जोशीले माहौल के बीच शानदार जीत दर्ज की।

पुरुष सिंगल्स के अन्य मुकाबले में 10वीं वरीयता प्राप्त इटली के फाबियो कोबोली ने अमेरिकी खिलाड़ी जेड स्वाजदा को 6-2, 6-3, 6-7 (7), 7-6 (5) से पराजित किया। वहीं नंबर वन खिलाड़ी जानिक सिनर को उलटफेर का शिकार बनाने वाले जुआन मैनुअल सेरुंडोलो का सफर चौथे दौर में थम गया। सेरुंडोलो को इटली के माटेओ बेरेटिनी ने 6-3, 7-6 (7), 7-6(8) से हराया। वहीं चौथी वरीयता प्राप्त कनाडा के फेलिक्स आगर एलियासेम ने एलेजांद्रो ताबिलो को 6-3, 7-5, 6-1 से हराया।

कालिंस्काया पहली बार क्वार्टर फाइनल में

पेरिस : रूस की एना कालिंस्काया ने शानदार संघर्ष का परिचय देते हुए पहली बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सोमवार को खेले गए चौथे दौर के मुकाबले में उन्होंने आस्ट्रिया की अनास्तासिया पोटापोवा को 6-4, 2-6, 7-6 (10-7) से हराया। निर्णायक सेट में पोटापोवा के पास मैच जीतने का सुनहरा मौका था, लेकिन वह दो बार सर्विस करते हुए मैच समाप्त नहीं कर सकीं। वहीं कालिंस्काया ने सुपर टाईब्रेक में 1-4 से पिछड़ने के बावजूद शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। विश्व रैंकिंग में 22वें स्थान पर काबिज कालिंस्काया के करियर का यह दूसरा ग्रैंडस्लैम क्वार्टर फाइनल है। इससे पहले वह 2024 आस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थीं। अन्य मुकाबलों में डायना श्नाइडर ने मेडिसन कीज को 6-3, 3-6, 6-0 से हराया।

जी ग्रुप करेगा फीफा विश्व कप का प्रसारण

फीफा वर्ल्ड कप 10 दिन शेष

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत में भी आखिरकार फीफा विश्व कप 2026 के प्रसारण का रास्ता साफ हो गया है। देश के फुटबाल प्रशंसकों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है कि इस मामले पर फीफा और जी ग्रुप के बीच सोमवार को करार हो गया। 11 जून से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट से ठीक 10 दिन पहले यह समझौता हुआ है। अब भारत में विश्व कप का सीधा प्रसारण जी एंटरटेनमेंट अपने नए लांच किए गए यूनाइट 8 स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए टेलीविजन पर करेगा, जबकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जी 5 ऐप पर उपलब्ध होगी। प्रसारण का यह समझौता सिर्फ 2026 के विश्व कप तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके तहत 2034 तक भारत के दर्शकों के लिए फीफा के कुल 39 बड़े टूर्नामेंट दिखाए जाएंगे।

फीफा से जी ग्रुप ने की डील, समझौते के तहत 2034 तक फुटबाल के 39 बड़े टूर्नामेंटों का भारत में होगा प्रसारण

इन प्रमुख टूर्नामेंटों का भी होगा प्रसारण

टूर्नामेंट	वर्ष
फीफा अंडर-17 विश्व कप	2026
फीफा अंडर-20 विश्व कप	2027
फीफा महिला अंडर-17 विश्व कप	2026
फीफा महिला अंडर-20 विश्व कप	2026
फीफा फुटसल विश्व कप	2028
फीफा इंटरकांटिनेंटल कप	2026

जर्मनी की टीम ● फाइल फोटो

दो विश्व कप में जल्द बाहर हुई जर्मनी टीम वापसी को बेताब

बर्लिन, एपी : 2018 और 2022 में लगातार दो फीफा फुटबाल कप से ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली जर्मनी टीम इस बार अपनी पुरानी बादशाहत को पाने के लिए बेताब है। 2014 सहित कुल चार बार की यह विश्व चैंपियन टीम 2022 के कतर विश्व कप में लगातार तीन हार के बाद शर्मनाक तरीके से बाहर हो गई थी। तब टीम की कमान संभाल रहे कोच हांसी फ्लिक को इस्तीफा देना पड़ा था। अब 2024 से टीम की कमान संभाल रहे कोच जूलियन नागेल्समैन को पूरा भरोसा है कि यह टीम फिर से अपनी खोई हुई शान वापस पा लेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार जर्मनी की टीम फिर से खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

सृजनात्मकता का रहस्य
विश्राम और जागरूकता

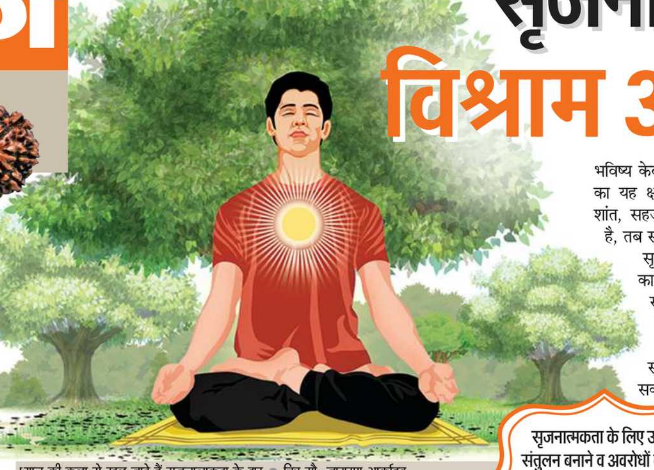

जीवन दर्शन

श्री श्री रवि शंकर
आर्ट आफ लिविंग के प्रणेता, आध्यात्मिक गुरु

धारणा है कि सृजनात्मकता के लिए अशांति और उद्विग्नता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह भ्रांति है। शांति और मौन में सृजनात्मकता सहज ही घटित होती है...

ध्यान की कला से खुल जाते हैं सृजनात्मकता के द्वार ● चित्र सौ.: जागरण आर्काइव

गहन मौन सृजनात्मकता का उत्प्रेरक है। जो व्यक्ति अत्यधिक व्यस्त, चिंतित, अति-महत्वाकांक्षी अथवा आलसी हो, उससे सृजन नहीं हो सकता। एक अशांत व्यक्ति आविष्कारक नहीं हो सकता। मन और शरीर विपरीत नियमों पर कार्य करते हैं। शारीरिक स्तर पर जितना अधिक प्रयास होगा, परिणाम उतना ही उत्तम होगा। जबकि मानसिक या सृजनात्मकता के स्तर पर, प्रयास जितना न्यून होगा, परिणाम उतना ही उत्तम होगा। जब मन विश्राम करना सीख जाता है, तब नए विचारों का आविर्भाव होता है। क्या आपने देखा है कि यदि आप कुछ भूल गए हैं, तो उसे याद करने का जितना अधिक प्रयास करते हैं, उसे याद करने में उतना ही अधिक समय लगता है? जब आप प्रयास को छोड़कर विश्राम करते है तब स्मरण स्वतः ही घटित होता है।

सामान्यतः यह धारणा है कि सृजनात्मकता के लिए अशांत व उद्विग्न होना आवश्यक है। माना जाता है कि बड़े सृजनात्मक काम करने वाले कुछ महान विचारक व विज्ञानी अशांत व उद्विग्न स्वभाव के थे, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। सृजनात्मकता का उत्स गहन मौन व शांत चित्त है। यदि आप किसी आविष्कार का सूक्ष्मता से अवलोकन करें, तो पाएंगे कि यह तब हुआ, जब आविष्कारक मानसिक थकावट के चरम बिंदु पर पहुंचकर पूर्णतः शिथिल हो गया। पूर्ण विश्राम के उस क्षण में सृजनात्मकता घटित हुई। यदि अशांति से सृजनात्मकता संभव होती तो विश्व के युद्धग्रस्त व अशांत क्षेत्र सृजनात्मकता में अग्रणी होते।

कुछ मिनटों का ध्यान व अंतर्मुख होना एक विराट परिवर्तन ला सकता है। संतुलित गतिविधि, विश्राम और योग, ये तीन आपके भीतर कौशल और सृजनात्मकता को प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आप ध्यान की कला जानते हैं तो सृजनात्मकता और आनंद का उपयोग कर सकते हैं।

जब आप भ्रमित हों, तो केवल विश्राम करें। अंतःप्रज्ञा तभी कार्य करती है, जब आपका मन पूर्णतः शांत हो। अन्वेषण और सृजनात्मकता हमारे भीतर प्रकट होते हैं और आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा का अध्ययन, उस स्रोत को प्राप्त करने की तकनीक है। हम स्वयं में जितना अधिक विश्राम करते हैं, उतना ही सृजनात्मकता व प्रसन्नता को बाहर लाते हैं। चेतना के प्रत्येक बिंदु पर सृजनात्मकता स्थित है और इसका आह्वान किया जा सकता है।

हमारा मन निरंतर अतीत की स्मृतियों या भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रहता है। अतीत और भविष्य के मध्य वर्तमान का क्षण विस्मृत हो जाता है। अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य केवल एक योजना मात्र है, पर वर्तमान का यह क्षण सदैव हमारे साथ है। जब मन शांत, सहज और वर्तमान क्षण में स्थित होता है, तब सृजनात्मकता खिल उठती है।

सृजनात्मकता के लिए उचित संतुलन बनाने व अवरोधों को दूर करने के लिए हमें अपने अस्तित्व की सात परतों शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार और आत्मा को समझना आवश्यक है।

सृजनात्मकता और उत्पादकता दोनों का जीवन में संतुलन आवश्यक है। सृजनात्मकता को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास स्वतंत्रता नहीं है तो आप सृजनात्मक व उत्पादक नहीं हो सकते। आपके मन में कोई महान विचार आ सकता है, परंतु उस विचार को फलीभूत करने के लिए अनुशासन आवश्यक होता है। अनेक युवाओं के पास उत्कृष्ट विचार तो होते हैं, किंतु उन्हें वास्तविकता में परिणत करने हेतु आवश्यक अनुशासन नहीं होता। वहीं कुछ लोग अत्यंत अनुशासित व कुशल प्रबंधक होते हैं, पर उनके पास नए विचारों और सृजनात्मकता के लिए समय नहीं होता। सृजनात्मकता के अभाव में जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना संभव नहीं हो पाता। तब मन में भय और अनिश्चितता का भाव बना रहता है। अतः जीवन में सृजनात्मकता व उत्पादकता दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सृजनात्मक जीवन के मार्ग में कुछ अवरोध भी है :

प्रथम अवरोध : हमारे अंतर्मन में सदैव एक आंतरिक संवाद चलता रहता है। हम अपने पूर्वाग्रहों के कारण केवल उन्हीं तथ्यों और कथनों को स्वीकार करते हैं, जिनसे हम पूर्व-परिचित हैं। जो हमारी पूर्व स्थापित धारणाओं के अनुकूल नहीं होते हैं, उन्हें हम अस्वीकार कर देते हैं। हमारे मन की यह प्रवृत्ति सृजनात्मकता के मुख्य अवरोधों में से एक है।

द्वितीय अवरोध : सृजनात्मकता का एक अन्य पक्ष 'कल्पना' है। अनेक अविष्कार किसी विशिष्ट कल्पना को वास्तविकता से जोड़ने के कारण संभव हुए है। यदि आप केवल वर्तमान समय की वास्तविकता के बारे में विचार करेंगे तो सृजनात्मक होना संभव नहीं है। यदि आप केवल कल्पनाओं में खोए रहेंगे, तब भी वास्तविक धरातल से संबंध न होने के कारण, सृजनात्मकता का अभाव होगा। सृजनात्मकता के लिए यथार्थ और कल्पना के मध्य संतुलन होना आवश्यक है।

सृजनात्मकता के अवरोधों को दूर करने के लिए हमें अपने अस्तित्व की सात परतों शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार और आत्मा को समझना आवश्यक है। अस्तित्व की इन सात परतों का थोड़ा-सा ज्ञान भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस ज्ञान के परिणामस्वरूप हम अधिक जीवंत और बच्चों जैसे बन जाते हैं। हम अपनी श्वास के प्रति सजग नहीं है, जबकि श्वास में जीवन के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। सृजनात्मकता हमारे भीतर से ही उत्पन्न होती है और योग व अध्यात्म उस स्रोत तक पहुंचने की एक तकनीक है।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

चिंतन धरोहर

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य

श्रेष्ठ जीवन के सूत्र

सादा जीवन उच्च विचार... हम बदलेंगे युग बदलेगा... ये वे सूत्र हैं, जिनकी आज अत्यधिक आवश्यकता है। इन्हें जीवन में उतारकर हम श्रेष्ठ जीवन को अपना सकते हैं...

मनुष्य का जीवन भौतिक सुख-सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मविकास, समाज सेवा और चरित्र निर्माण की महान यात्रा है। जीवन की वास्तविक सफलता धन, पद या आडंबर में नहीं, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता, व्यवहार की मधुरता और कर्तव्यनिष्ठा में निहित होती है। इसी कारण भारतीय संस्कृति ने सदैव सादा जीवन व उच्च विचार को आदर्श जीवन का मूलमंत्र माना है।

सादा जीवन का अर्थ अभावग्रस्त या निराश जीवन नहीं, बल्कि आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए संयम, संतुलन और सरलता के साथ जीवन जीना है। आज दिखावे और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में मनुष्य इतना उलझ गया है कि उसके जीवन से शांति और संतोष समाप्त होते जा रहे हैं। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करे, अनावश्यक खर्चों से बचे और सरलता अपनाए तो उसका जीवन सुखी, शांत और संतुलित बन सकता है। सादगी मनुष्य को विनम्र बनाती है और उसे दूसरों की पीड़ा को समझने की संवेदनशीलता प्रदान करती है।

इसके साथ ही उच्च विचार जीवन का वास्तविक आभूषण हैं। उच्च विचारों वाला व्यक्ति सत्य, ईमानदारी, करुणा, परोपकार और नैतिकता को जीवन में स्थान देता है। उसके लिए स्वयं का हित नहीं, समाज और राष्ट्र का हित सर्वोपरि होता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अनेक संतों ने सादा जीवन जीते हुए अपने उच्च विचारों से पूरे विश्व को प्रेरित किया। हिंसा, भ्रष्टाचार, स्वार्थ और नैतिक पतन का मूल कारण विचारों की अशुद्धि ही है। यदि मनुष्य अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाए, तो उसका आचरण स्वतः श्रेष्ठ बन जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उसके विचार समाज और मानवता के लिए कितने उपयोगी हैं।

वहीं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा... जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला महान सूत्र है। जब व्यक्ति अपने भीतर सुधार लाता है, तब परिवार सुधरता है, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति, सद्भाव और नैतिकता बढ़े तो इसका आरंभ स्वयं से करना होगा। दूसरों को बदलने की अपेक्षा स्वयं को बदलना अधिक आवश्यक है। हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में अनुशासन, श्रम, सदाचार और सेवा की भावना को अपनाए। अपने समय का सदुपयोग करे, अनाचार, नशा और दुर्व्यसनों से सदैव दूर रहे तथा शिक्षा और संस्कारों को महत्व दे। मनुष्य का जीवन सादगी, उच्च विचार और आत्मपरिवर्तन पर आधारित होना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर अच्छाई का दीप जलाएगा, तभी एक श्रेष्ठ समाज और श्रेष्ठ युग का निर्माण संभव होगा। सादा जीवन, उच्च विचार... और हम बदलेंगे, युग बदलेगा... का संदेश आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

अध्यात्म की अन्य सामग्री पढ़ने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

इस पेज पर आपकी सम्मति और सुझावों का स्वागत है- feature@jagran.com

गीता सार

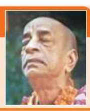

ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद

(अध्याय - आठ, श्लोक-12)

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च।
मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्।।

भावार्थ : समस्त ऐंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति अर्थात योगधारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित कर मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है।

तात्पर्य : इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रियभोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रियविषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों- नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रियतृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन अध्याय-छह में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यावहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्णभावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है।

जीवन प्रबंधन

आचार्य नारायण दास
भागवताचार्य, महंत, भरतमिलाप आश्रम, ऋषिकेश

सूर्य से सीखें अनासक्त रहना

श्रीमद्भागवत महापुराण में जीवन को उत्कृष्ट बनाने के सूत्र हैं। इसके एकादश स्कंध में भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 प्राकृतिक गुरुओं से प्राप्त शिक्षा का राजा यदु के समक्ष वर्णन किया है, जिसमें जीवन प्रबंधन के तत्व निहित हैं। आज जानते हैं दत्तात्रेय ने अपने सप्तम गुरु सूर्य से क्या शिक्षाएं ग्रहण कीं...

भारतीय आध्यात्मिक वांगमय में प्रकृति को भी गुरुतुल्य मानकर शिक्षा ग्रहण की गई है। पिछले अंकों में इस स्तंभ-श्रृंखला में भगवान दत्तात्रेय के छह गुरुओं से प्राप्त शिक्षा की व्याख्या हो चुकी है।

अब भगवान दत्तात्रेय अपने सातवें गुरु के रूप में भगवान सूर्य से ग्रहण की गई शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए राजा यदु को उपदेशित करते हैं, हे राजन! सूर्य देव भी मेरे गुरुसदृश हैं, जो न केवल अंधकार का नाश करते हैं, अपितु साधक को अनासक्ति और अद्वैत का भी उत्तम पाठ पढ़ाते हैं, जो सांसारिक मायाजाल को खंड-खंड करने के लिए अमोघ शस्त्र है।

हे राजन! मनुष्य को सूर्य की भांति परोपकारी होना चाहिए। संसार में सभी जीवों का जीवन सूर्य से ही चल रहा है, पर उसे इस बात का अहंकार नहीं है कि वह संसार का जीवनदाता है। सूर्य समय पर उदय होता और समय पर अस्त होता है। हे राजन! एक साधक को समय प्रबंधन सूर्य से सीखना चाहिए। सूर्य उदय के समय भी प्रसन्न है और अस्त होते समय भी। इसी प्रकार हम भी जब अपने कार्यस्थल आदि को प्रस्थान करें, तो प्रसन्नतापूर्वक करें और जब वापस लौटें तो भी पूर्व की भांति ही सानंदित हों। एक परमार्थी साधक को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अवसाद या उदासी उसके आध्यात्मिक जीवन को किसी भी प्रकार से प्रभावित न कर सके।

गुणैर्गुणानुपादत्ते यथाकालं विमुञ्चति।
न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः।।

सहस्त्र रश्मियों के स्वामी भगवान सूर्य ग्रीष्म ऋतु में अपनी प्रखर किरणों से पृथ्वी के जल का संचय करते हैं, किंतु उस जल की मलिनता से स्वयं को लिप्त नहीं होने देते। वे जल को अपनी शक्ति बनाते हैं और पुनः वर्षा ऋतु के आगमन पर उसे लोकोपकार हेतु जगत को लौटा देते हैं। हे राजन! इसी प्रकार, एक साधक भी अपनी इंद्रिय रूपी किरणों के माध्यम से समाज से आवश्यकता के अनुरूप जीविनोपयोगी वस्तु रूपी जल ग्रहण तो करता है, पर उसमें रचता-बसता नहीं। वह संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं होता। वह अपनी इंद्रियों का स्वामी है, दास नहीं। वह समय आने पर उन विषयों को अनासक्त भाव से त्याग देता है, जैसे सूर्य बादलों के माध्यम से अमृतमयी वर्षा कर रिक्त हो जाते हैं। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि उपभोग एक परमार्थिक मर्यादा मात्र हो, मोह या विलासिता का साधन नहीं।

हे राजन! आकाश के भाल पर चमकने वाला सूर्य तो केवल एक ही है, किंतु यदि धरती पर जल से भरे अनेक पात्र रख दिए जाएं, तो प्रत्येक पात्र में एक सूर्य दृष्टिगोचर होता है। वायु के वेग से जब जल चंचल होता है, तो सूर्य का प्रतिबिंब हिलता-डुलता, खंडित और अस्थिर दिखाई देता है। सत्संग वंचित, अल्पज्ञ और स्थूलबुद्धि वाले लोग भ्रमवश उन प्रतिबिंबों को ही वास्तविक सूर्य मान लेते हैं और उन्हें अनेक समझने की भूल कर बैठते हैं, किंतु ज्ञानी जानते हैं कि पात्र टूटे या जल हिले, वह मूल सूर्य तो निर्विकार और अखंड है। यही सत्य आत्मा का है। देह, मन और बुद्धि रूपी भिन्न-भिन्न उपाधियों के कारण ऐसा आभास होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग है। सत्य तो यह है कि वह परमात्मा रूपी सूर्य एक ही है, जो समस्त शरीरों में प्रतिबिंबित हो रहा है।

बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः।
लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत्।।

हे राजन! भेदात्मक दृष्टि अज्ञान का अंधकार है, जबकि अभेद दृष्टि आत्म-ज्ञान का परम प्रकाश है। सूर्य का जीवन एक निरंतर यज्ञ है। वह ग्रहण भी शुद्धि के लिए करता है और दान भी सृजन के लिए। यदि कोई भी मनुष्य सूर्य के इन दो सूत्रों अनासक्त कर्म और अद्वैत दृष्टि को अपने जीवन में उतार ले, तो वह संसार में रहते हुआ भी सदा जीवन मुक्ति का अनुभव प्राप्त करता है।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

अगले मंगलवार को पढ़ें
स्वामी मैथिलीशरण तथा मोरारी बापू का चिंतन

आज का भविष्यफल- 2 जून, 2026 मंगलवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया का राशिफल।

आज का राहुकाल : अपराह्न 03 बजे से 04 बजकर 30 मिनट तक।

आज का दिशाशूल : उत्तर

कल 3 जून, 2026 का पंचांग

कल का दिशाशूल : उत्तर

कल की भद्रा : प्रातः 08 बजकर 13 मिनट से रात्रि 09 बजकर 22 मिनट तक।

विक्रम संवत 2083 शके 1948 उत्तरायण, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु, अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया 21 घंटे 22 मिनट तक, तत्पश्चात चतुर्थी, पूर्वाआषाढ़ा नक्षत्र 25 घंटे तक तत्पश्चात उत्तराआषाढ़ा नक्षत्र, शुभ योग 08 घंटे 13 मिनट तक तत्पश्चात शुक्ल योग, धनु में चंद्रमा।

मेष : धार्मिक और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

वृष : आर्थिक मामलों में सुधार होगा। अपनों से ही तनाव मिलेगा। जीवनसाथी से मन अशांत रहेगा।

मिथुन : शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। स्थानांतरण या विभागीय परिवर्तन में प्रयास सार्थक होगा।

कर्क : संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा।

सिंह : आर्थिक प्रगति होगी। यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कन्या : व्यस्तता बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

तुला : पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक प्रगति होगी। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।

वृश्चिक : रुका कार्य संपन्न होगा। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

धनु : रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक सफलता मिलेगी।

मकर : व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। चल या अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी।

कुंभ : संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी।

मीन : निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे।

वर्ग पहेली-3353

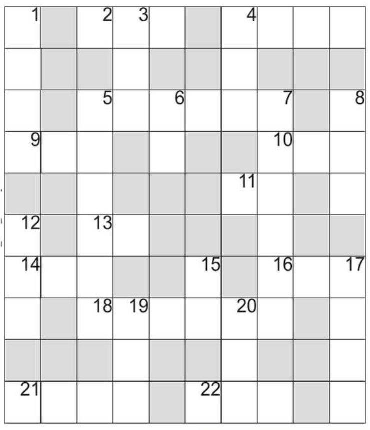

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं :
2. संकट, गुस्सा, आपत्ति (3)।
4. जलाने की वस्तु, ईंधन (4)।
5. अपनाना (3,3)।
9. समूह, झुंड (3)।
10. गुजरात का एक शहर, अक्स (3)।
11. धागा, सहारा (2)।
13. मानचित्र (2)।
14. गरजता हुआ बादल (3)।
16. आग की लपट (3)।
18. नियमबद्ध होना (2,2,2)।
21. अवैध माल जमा रखने वाला (4)। 22. नष्ट, बर्बादी (3)।

ऊपर से नीचे :
1. धरोहर रखने वाला, जमा करने वाला (4)।
3. पचा जाना (3)।
4. युग, काल, समय (3)।
5. बेइज्जती या अपमान करने वाला (6)।
6. स्त्री (2)।
7. बहुत दुख देना, छाती में ...... (3,3)।
8. मोटा का विपरीत (3)।
12. फल का कड़ा और कुछ बड़ा बीज (3)। 15. इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था (2)। 17. आहें भरना (4)।
19. अंधकार, अंधेरा (3)।
20. एक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रीक कवि (3)।

कल का हल

म	हा	ना	य	क		अ	न	ब	न
जे				ड़ा					वी
दा		झ	न	का	र		अ		क
र			वा		च	ल	न		र
		प	ह	ना	वा		म	र	ण
न	य	न		ब	ना	ठ	ना		
पुं		प	र	दा		ठे			अ
स		ना		न	ज	रा	ना		चा
क					ल				न
ता	म्र	व	र्ण		ज	ल	कं	ट	क

सुडोकू-3353

7		1		2		8		6
				8			9	
		2	6		9		1	
	3		2			7		5
		5		7	6		2	
2				5				4
1	5		4				7	
		8		1		2		
4			7		8			3

कल का हल

7	8	4	3	6	1	9	2	5
6	2	1	9	5	4	8	7	3
3	5	9	2	8	7	1	6	4
5	1	6	7	4	3	2	9	8
8	9	3	5	2	6	4	1	7
4	7	2	1	9	8	5	3	6
2	4	7	6	1	5	3	8	9
1	6	5	8	3	9	7	4	2
9	3	8	4	7	2	6	5	1

आनलाइन सट्टेबाजी के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हरदोई

▸ 2025 के दो मुकदमों की जांच में खुलीं परतें, मास्टरमाइंड समेत सात फरार

साइबर क्राइम थाना पुलिस ने देशभर में आनलाइन गेमिंग व सट्टेबाजी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का राजफाश किया है। पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरोह का मास्टरमाइंड व सात साथी अभी फरार हैं।

साइबर थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में साइबर ठगी के दो मामले दर्ज हुए थे। इन मुकदमों की कड़ियों को जोड़ते हुए जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तो पूरा नेटवर्क सामने आता गया। पुलिस टीम ने चार दिन पहले ठगी के शिकार मध्य प्रदेश के छतरपुर (लवकुशनगर) निवासी सौरभ सिंह तक पहुंची थी। सौरभ व अन्य से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने रजनीश और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। इनसे मिले सुराग पर गोमतीनगर के देव शर्मा तक पहुंची। वहीं, धरे गए रजनीश ने कुबूल किया कि इस पूरे नेटवर्क के आका जेएसके और सोनू भाई हैं। रजनीश और अभिषेक का काम लखनऊ में इनके गुर्गों के लिए कमरा और खाने-पीने का इंतजाम करना था।

चार टीमों में बंटा था ठगी का नेटवर्क : गिरोह ने कारपोरेट तर्ज पर चार अलग-अलग टीमें बना रखी थीं। इनमें टीम-वन फर्जी गेमिंग एप और वेबसाइट तैयार कर लोगों को मोटी कमाई का लालच देती थी। टीम-टू फर्जी पतों पर मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम, और इंटरनेट बैंकिंग के दस्तावेज जुटाती थी। तीसरी टीम जुटाए गए सिम और बैंक खातों/यूपीआइ आइडी को एक्टिवेट कर हैंडल करती थी। चौथी टीम क्यूआर कोड और आनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए सट्टेबाजी की रकम जमा कराकर उसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर (लेयरिंग) करती थी।

नहीं रहीं 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' गाने वाली गायिका सुमन कल्याणपुर

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ना ना करते प्यार तुम्हीं से, तुमने पुकारा और हम चले आए...., बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है... जैसे कई हिट गाने गाने वाली पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपुर का रविवार की रात लगभग आठ बजे निधन हो गया। उन्होंने 89 वर्ष की उम्र में अपने मुंबई स्थित घर में अंतिम सांस ली। उनके परिवार में उनकी बेटी चारु है।

पद्मभूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर ने लंबे समय तक हिंदी और मराठी संगीत जगत को कई यादगार गीत दिए। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि कई बार श्रोता इसे सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की आवाज समझ बैठते थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर शोक जताया है।

सुमन कल्याणपुर। फाइल

मेरी सहेली विख्यात गायिका सुमन कल्याणपुर जी के स्वर्गवास की खबर से मैं बहुत दुखी हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं।
- ऊषा मंगेशकर, गायिका

उनकी बायोग्राफी सुमन सुगंध लिखने वाली मंगला खाडिलकर ने बताया कि सुमन कल्याणपुर का रात करीब आठ बजे लोखंडवाला में उनके घर पर उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से वह अपने ही गाने सुन रही थीं।' उनका अंतिम संस्कार सोमवार को पवन हंस श्मशान केंद्र में किया गया। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका (तत्कालीन ब्रिटिश भारत, वर्तमान बांग्लादेश) में हुआ था। उनका मूल नाम सुमन हेम्माडी था। 1952 में आल इंडिया रेडियो के लिए पहली प्रस्तुति दी थी। उन्हें 1953 में रिलीज मराठी फिल्म शुक्राची चांदणी के लिए गाने का अवसर मिला। 1954 में रिलीज हुई मंगू के जरिये हिंदी सिनेमा में कदम रखा। 1958 में मुंबई के व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से विवाह किया। विवाह के बाद उनका नाम सुमन हेम्माडी से सुमन कल्याणपुर हो गया।

आंशिक कार्य दिवसों में वरिष्ठ वकीलों को दलीलें रखने की नहीं होगी अनुमति

▸ युवा वकीलों को अपने मामलों में दलीलें रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कदम

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि न्यायालय के आंशिक कार्य दिवसों के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न तो मामलों को तत्काल सूचीबद्ध कराने की अनुमति दी जाएगी और न ही सूचीबद्ध मामलों में दलीलें रखने की। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कदम सोमवार से 12 जुलाई तक न्यायालय के आंशिक कार्य दिवसों के दौरान युवा वकीलों को अपने मामलों में दलीलें रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

शीर्ष अदालत में ग्रीष्मावकाश को अब न्यायालय के आंशिक कार्य दिवस कहा जाता है। इस साल इस अवधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह तीन से चार पीठ सुनवाई करेंगी। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, "मेरी अदालत में किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को अनुमति नहीं दी जाएगी।" जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले का उल्लेख करने का प्रयास किया तो न्यायमूर्ति नाथ ने स्पष्ट किया कि इस अवधि के दौरान केवल युवा वकीलों और एडवोकेट-आन-रिकार्ड को दलीलें रखने की अनुमति होगी। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि जिन मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हो रहे हैं, उन्हें खारिज नहीं किया जाएगा और उन्हें सामान्य कार्यदिवस के बाद जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की एक अन्य पीठ ने भी कहा कि न्यायालय के आंशिक कार्य दिवसों के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मामलों का उल्लेख करने या दलीलें रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कनिष्ठ अधिवक्ता मामलों में दलीलें रखते हैं तो नोटिस जारी होने की संभावना अधिक है और यदि वरिष्ठ अधिवक्ता दलीलें रखते हैं तो मामला खारिज होने की संभावना अधिक है।

अमेरिका ने सर्वेयर-वन के साथ चांद पर रखा पहला कदम

1966 में आज ही नासा ने चांद पर अपना पहला यान सर्वेयर-वन लैंड कराया था। इसका उद्देश्य मानवयुक्त लैंडिंग की तैयारी के लिए चंद्र सतह की तस्वीरें लेना व वहां की मिट्टी की क्षमता की जांच करना था। इसकी सफलता के बाद 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा।

विज्ञान के शिखर रायल स्वीडिश एकेडमी आफ साइंसेज की स्थापना

1739 में आज ही प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था रायल स्वीडिश एकेडमी आफ साइंसेज की स्थापना हुई। देश-दुनिया में वैज्ञानिक गतिविधियों व अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित इस एकेडमी ने मानव विकास में विज्ञान के योगदान को प्रोत्साहित किया है।

नंदन नीलेकणि ने रखी आधार व्यवस्था की मजबूत नींव

भारत को आधार के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी विशिष्ट पहचान प्रणाली देने वाले नंदन नीलेकणि का जन्म 1955 में आज ही बेंगलुरु में हुआ। वर्ष 2009 में जब यूआइडीएआइ का गठन हुआ, तब नीलेकणि की दूरदर्शिता को देखते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले, 1981 में उन्होंने एनआर नारायणमूर्ति व पांच अन्य दिग्गजों के साथ मिलकर इन्फोसिस की नींव रखी थी, जो आज देश की दूसरी सबसे बड़ी आइटी कंपनी है। वर्तमान में वह सरकार की महत्वाकांक्षी ओएनडीसी परियोजना को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

पैंक्रियाटिक कैंसर के खिलाफ नई दवा बनी उम्मीद

बड़ा कदम ▶ नई दवा ने एडवांस पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित मरीजों को लंबे समय तक जीवित रहने में मदद की

म्यूटेटेड प्रोटीन ट्यूमर को रोकने का काम करती है नई दवा, कीमोथेरेपी से भी है ज्यादा कारगर

वाशिंगटन, एपी : कैंसर के सबसे खतरनाक और जानलेवा प्रकार में पैनक्रियाटिक कैंसर का नाम भी शामिल है, लेकिन हाल ही में हुआ एक शोध मरीजों के दिल में उम्मीद की नई किरण जगा रहा है। दरअसल, एक नई प्रयोगात्मक दवा ने एडवांस पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित मरीजों को लंबे समय तक जीवित रहने में मदद की है।

लास एंजिल्स के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डा. जेव वेनबर्ग का कहना है कि हालांकि यह दवा कैंसर को पूरी तरह ठीक नहीं करती, लेकिन यह इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।

दशकों पुरानी चुनौती का मिला समाधान : इस नई दवा का नाम डैराक्सोनरासिब है। दरअसल, 90% से ज्यादा पैनक्रियाटिक कैंसर के मामलों में एक म्यूटेटेड प्रोटीन ट्यूमर को बढ़ाने का काम करता है। दशकों से विज्ञानी इस प्रोटीन को रोकने का तरीका ढूंढ रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब यह नई दवा इसी म्यूटेटेड प्रोटीन को रोकने का काम करती है।

कीमोथेरेपी के मुकाबले दोगुना असरदार : यह रिसर्च न्यू इंग्लैंड जर्नल आफ मेडिसिन में प्रकाशित हुई है और हाल ही में शिकागो में अमेरिकन सोसाइटी फार क्लिनिकल आंकोलाजी की बैठक में इसे प्रेजेंट किया गया था।

प्रतीकात्मक

इस अध्ययन में 500 ऐसे मरीजों को शामिल किया गया था, जिनका कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुका था और जिन पर पिछला इलाज बेअसर हो चुका था। इन मरीजों को दो ग्रुप्स में बांटकर यह टैबलेट या फिर कीमोथेरेपी दी गई। नतीजों में सामने आया कि रोजाना ली जाने वाली इस टैबलेट ने मरीजों के जीवित रहने के समय को करीब दोगुना कर दिया। टैबलेट लेने वाले मरीज औसतन 13.2 महीने तक जीवित रहे, जबकि कीमोथेरेपी लेने वाले मरीज सिर्फ 6.7 महीने ही जी सके। इसके अलावा, कीमोथेरेपी की तुलना में इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स भी कम देखे गए। भले ही यह सुधार छोटा है, लेकिन कीमोथेरेपी के मुकाबले इतनी बड़ी बढ़त दिखाने वाली यह पहली दवा है।

दर्द में राहत और बेहतर जीवनशैली : हालांकि, समय के साथ इस दवा का असर कम होने लगता है, लेकिन मरीजों ने कीमोथेरेपी ग्रुप की तुलना में इसका इस्तेमाल काफी लंबे समय तक किया। इस टैबलेट की वजह से ट्यूमर का साइज छोटा हुआ, जिससे मरीजों को दर्द से राहत मिली और उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर हुई। डाटा विश्लेषण के बाद भी कई मरीज इस दवा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका मतलब है कि आगे चलकर जीवित रहने का यह अंतर और भी बढ़ सकता है।

क्या यह बनेगा इलाज का नया मानक? : विज्ञानी अब इस दवा का इस्तेमाल बीमारी के शुरुआती चरणों में करने की संभावना भी तलाशेंगे। वे देखना चाहते हैं कि क्या ट्यूमर का आकार छोटा होने से मरीजों में सर्जरी की संभावना ज्यादा होती है या नहीं। हालांकि, डा. ब्रायन वोल्पिन ने बताया कि इस टैबलेट के इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिनमें त्वचा पर रैशेज होना और मुंह में छाले पड़ना शामिल है।

भोलेनाथ का जलाभिषेक

ज्येष्ठ सोमवार के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करने की पुरानी मान्यता है। प्रयागराज में सोमवार को इसके लिए गंगाजल लेकर जाते श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। प्रेट्र

इधर-उधर

कभी दर्पण, कभी कांच बन जाता यह क्रिस्टल

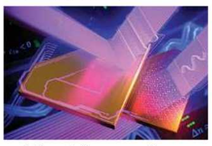

90 डिग्री घुमाते ही बदल जाता है रूप, विज्ञानी भी हैरान ● इंटरनेट मीडिया

सिंगापुर, एजेंसी : विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी खोज हुई है, जो किसी जादू से कम नहीं लगती। सिंगापुर, प्राग और टेक कंपनी एक्सपैनसीईओ के शोधकर्ताओं ने अनोखे क्रिस्टल की पहचान की है, जो एक ही समय में धातु और कांच दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, मालिब्डेनम आक्सीक्लोराइड नामक पतले क्रिस्टल में प्रकाश को मोड़ने की क्षमता पाई गई। खासियत यह है कि एक दिशा से देखने पर यह चमकदार दर्पण की तरह प्रकाश को परावर्तित करता है, लेकिन 90 डिग्री घुमाने पर कांच जैसा दिखाई देने लगता है।

कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता, बिना मास्क हो सकेगी रेडियोथेरेपी

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत ने कैंसर के इलाज के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के डाक्टरों ने भारत में पहली बार एआइ संचालित सरफेस गाइडेड रेडियोथेरेपी (एसजीआरटी) और एडेप्टिव रेडियोथेरेपी के अनूठे संयोजन का उपयोग करके सिर और गर्दन के कैंसर के मरीज का इलाज किया है। पारंपरिक रेडियोथेरेपी में मरीज के सिर को स्थिर रखने के लिए बेहद तंग प्लास्टिक मास्क पहनाया जाता है और सीटी सिमुलेशन स्कैन किया जाता है, जिसमें काफी समय लगता है, लेकिन इस तकनीक से डाक्टरों ने बिना किसी मास्क या सिमुलेशन सीटी स्कैन के सटीक रेडिएशन थेरेपी दी।

डाक्टरों के अनुसार, मुंह के कैंसर से पीड़ित रोगी पिछली सर्जरी और रेडियोथेरेपी उपचारों के असफल होने के बाद अस्पताल में आया था। ट्यूमर अत्यधिक बढ़ा हुआ था और लगातार

▶ भारत में पहली बार एआइ और उन्नत तकनीकों की मदद से किया कैंसर के मरीज का इलाज

प्रतीकात्मक

ब्लीडिंग हो रही थी। सिर और गर्दन के कैंसर के लिए पारंपरिक रेडियोथेरेपी रोगी की हलचल को रोकने के लिए तंग प्लास्टिक मास्क और सिमुलेशन सीटी स्कैन पर निर्भर करती है, डाक्टरों ने महसूस किया कि गंभीर रोगी उस प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। रक्तस्राव को रोकने के लिए आवश्यक विकिरण देने हेतु अस्पताल ने इस उन्नत तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया। मरीज पर इलाज का सकारात्मक परिणाम रहा और उसे 13 मई को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सर्फेस गाइडेड रेडियोथेरेपी तकनीक में मरीज की त्वचा को ट्रैक करने के लिए 3 डी कैमरा सिस्टम और एआइ का उपयोग किया जाता है। यदि मरीज हिलता है, तो रेडिएशन बीम अपने आप रुक जाती है, जिससे तंग मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एडेप्टिव रेडियोथेरेपी एआइ-संचालित सिस्टम हर दिन मरीज के शरीर और ट्यूमर के बदलते आकार को रियल टाइम में ट्रैक करता है और उसी अनुसार रेडिएशन की डोज को एडजस्ट करता है। सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के रेडिएशन आंकोलाजी विभाग के प्रमुख डा. प्रसाद राज दांडेकर ने बताया कि यह तकनीक उपचार को अधिक सटीक और प्रभावी बनाती है, जिससे मरीजों के इलाज के परिणाम बेहतर होते हैं।

वरुण धवन से जुड़े डीपफेक वीडियो हटाने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग वाली अभिनेता वरुण धवन की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने वरुण धवन से जुड़े डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश दिया है। डीपफेक में वरुण धवन को उनकी महिला को-स्टार्स के साथ गलत स्थितियों में दिखाया गया था। साथ ही कोर्ट ने वरुण धवन की अनुमति के बगैर उनके नाम पर सामान बेचने वाली सामग्री को भी ई-कामर्स वेबसाइट से हटाने को कहा है।

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया वरुण धवन के पक्ष में मामला बनता है और अगर उनके पक्ष में आदेश नहीं दिया गया, तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। कोर्ट ने ई-कामर्स प्लेटफार्म के साथ ही इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों को वरुण धवन के नाम, छवि, वीडियो सहित अन्य सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अश्लील सामग्री के प्रसार के साथ-साथ एआइ सृजित तस्वीरों पर सुरक्षा पाने के वरुण हकदार है।

बीमारियों से बचाएगी रोजाना कुछ समय तेज गति से शारीरिक गतिविधि

अनुसंधान

स्वस्थ रहने के लिए अच्छे खानपान के साथ ही व्यायाम बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते तो रोजाना कुछ समय के लिए तेज गति वाली शारीरिक गतिविधि के माध्यम से भी अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं। यह आपको कई तरह की बीमारियों से बचा सकता है। एक अध्ययन में सामने आया है कि प्रतिदिन कुछ मिनटों की तेज गति वाली शारीरिक गतिविधि से गठिया, हार्ट, लिवर व किडनी की बीमारी तथा डिमेंशिया सहित आठ प्रमुख बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।

यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चलता है कि बस पकड़ने के लिए दौड़ने जैसी तीव्र, सांस फूलने वाली छोटी-छोटी गतिविधियां बीमारियों और असमय मौत के जोखिम को कम करने में सहायक हैं। हालांकि, यह विशेष रूप से गठिया, गंभीर हृदय रोग (दिल का दौरा और स्ट्रोक) और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से बचाव करती हैं। चीन के सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के जियांग्या स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ की लेखिका मिनक्स्यू शेन ने कहा कि ब्रिटेन के बायोबैंक से 96,400 से अधिक लोगों के डाटा का विश्लेषण किया गया। उन्होंने बताया कि कलाई पर एक सप्ताह तक पहने गए एक्सेलेरोमीटर ने गतिविधियों को मापने में मदद की, जिसमें तेज गतिविधि वाले छोटे-छोटे दौर भी शामिल थे, जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं। " (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

रेंजर में अजय देवगन संग दिखेगी तमन्ना की जोड़ी। (@tamannaahspeaks)

21 साल का है तमन्ना का रिहर्सल

फिल्म स्त्री 2 का गाना आज की रात... हो या फिल्म जेलर का गाना कावाला... अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने इस फिल्मों में अपने डांस नंबर से खूब लोकप्रियता बटोरी। आज भी वह डांस नंबर के मामले में फिल्मकारों की सूची में शीर्ष पर आती हैं। हालांकि, तमन्ना के अनुसार, उन्हें यह लोकप्रियता रातों रात नहीं मिली। डांस नंबर्स को लेकर तमन्ना कहती हैं, 'सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि मैं कोई प्रशिक्षित डांसर नहीं हूं। दरअसल, मुझे कभी ट्रेनिंग का मौका ही नहीं मिला। हालांकि, मुझे डांस करना पसंद है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज अच्छा करने का करने का यही तरीका है कि उससे प्यार करना शुरू कर दो। डांस के साथ तो मैं पहले ही प्यार में पड़ गई थी। मुझे एक लोकप्रिय गाने तक पहुंचने में सिर्फ 21 साल ही तो लगे। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आज की रात गाने के रिहर्सल में कितना समय लगा? मैं उनसे कहती हूं सिर्फ 21 साल। मुझे लगता है कि जब हम कोई ऐसी परफार्मेंस देते हैं, जिन्हें लोग आइटम नंबर कहने से भी डरते हैं, वो तो कलाकार के स्टारडम व आस पास के आभा का जश्न होता है। जब मैं कोई भी गाना करती हूं, तो उसे एक पात्र की तरह ही निभाने की कोशिश करती हूं। जिससे हर गाने में कुछ अलग करने में मदद मिलती है। मुझे सच में गाने करने में मजा आता है। मैं यह हमेशा करती रहूंगी।'

आलिया भट्ट से झगड़े को लेकर बोले बाबी, लोग खाली बैठे हैं

अफवाहों पर विराम लगाना जरूरी है, जो हाल ही में किया अभिनेता बाबी देओल ने। बाबी और अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म अल्फा में साथ काम कर रहे हैं। पिछले दिनों खबरें आई थीं कि अल्फा के सेट पर बाबी और आलिया के बीच अनबन हो गई थी। इन अफवाहों ने इंटरनेट मीडिया पर जोर पकड़ा, जिसके बाद अब बाबी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि सेट पर ऐसी कोई समस्या कभी नहीं हुई थी। एक इंटरव्यू में बाबी ने कहा कि मुझे मेरे एक दोस्त ने इन अफवाहों का स्क्रीनशाट भेजा था। मैं भी हैरान हो गया। लोग इतने वेल्ले (खाली, बिना काम के) हैं कि कुछ भी लिखकर बना देते हैं। आगे बाबी ने आलिया की सराहना करते हुए कहा कि वह बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और बेहद पेशेवर हैं। वह अपने काम के लिए बहुत मेहनत करती हैं। उन्होंने फिल्म में अपने सभी फाइट सीक्वेंस के लिए भी पूरी तैयारी की थी। मुझे समझ नहीं आया कि किसने क्या सोचकर ये सारी अफवाहें फैलाई हैं। मैं हर किसी को जाकर सफाई नहीं दे सकता, इसलिए साफ कर देना चाहता हूं कि यह सच नहीं है। लोग इंस्टाग्राम से बहुत प्रभावित रहते हैं, लेकिन वहां की 90 प्रतिशत कहानियां सही नहीं होती हैं।

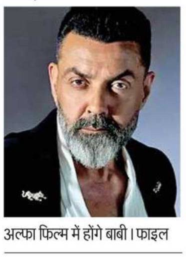

अल्फा फिल्म में होंगे बाबी। फाइल

गानों के रीमिक्स चलन पर बोले संजय, 2046 में क्या रीमिक्स करेंगे?

पिछले कुछ वर्षों से पुराने हिट गानों को रीक्रिएट या रीमिक्स करके नई फिल्मों में प्रयोग करने का चलन खूब चल रहा है। वरुण धवन अभिनीत आगामी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में तो प्रयोग हुए चुनरी चुनरी.. गाने के रीक्रिएटेड वर्जन को लेकर दो निर्माताओं वासु भगनानी और रमेश तौरानी के बीच अधिकारों की लड़ाई चल रही है। बता दें कि चुनरी चुनरी.. गाना वासु भगनानी के प्रोडक्शन में बनी फिल्म बीवी नं 1 का है। वहीं अक्षय कुमार की आगामी फिल्म वेलकम टू द जंगल का ऊंचा लंबा कद.. गाना जारी किया गया। जो वेलकम फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म के इसी नाम के गाने का रीक्रिएटेड वर्जन है। इस बीच फिल्म निर्देशक संजय गुप्ता ने गानों के रीक्रिएशन और रीमिक्स चलन पर तंज कसा है। एक्स पर लिखा, '2026 में फिल्मों का संगीत : 20 साल पहले के सभी सुपरहिट गाने रीमिक्स किए जा रहे हैं और रिलीज किए जा रहे हैं। ऐसे में चिंता यह है कि वो 2046 में क्या रीमिक्स करेंगे?' बता दें कि संजय ने भी साल 2016 में प्रदर्शित हुई फिल्म काबिल में हसीनों का दीवाना... तथा किसी से प्यार हो जाए... इन दो गानों को रीमिक्स कर प्रयोग किया था।

कांटे और मुसाफिर फिल्मों से निर्देशक हैं संजय। फाइल

गुजराती फिल्मों में काफी काम कर रहे हैं वत्सल। इंस्टाग्राम (@vatsalsheth)

इन शर्तों के साथ प्रोजेक्ट पर काम करते हैं वत्सल

कलाकार को अभिनय दिखाने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश होती है। फिर वह मौके उसे अलग-अलग भाषाओं में डिजिटल प्लेटफार्म पर मिले या फिर फिल्मों में, उससे उन्हें दिक्कत नहीं होती है। हिंदी फिल्म टारजन : द वंडर कार, मलंग, आदिपुरुष में अभिनय कर चुके अभिनेता वत्सल सेठ इन दिनों गुजराती फिल्मों में खासे सक्रिय हैं। वह हिंदी में काम करने को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। उनकी अपनी कुछ शर्ते हैं, जिसके मुताबिक वत्सल काम करना पसंद करते हैं। हिंदी फिल्मों में अभिनय को लेकर वह कहते हैं कि मैं हमेशा से चूजी रहा हूं। मेरे लिए किसी भी प्रोजेक्ट को करते समय उसकी कहानी और उसमें मेरा रोल सबसे अहम है। वह नहीं मिलता, तो मैं काम करने के लिए उत्सुक नहीं होता हूं। कुछ दिलचस्प मिलेगा, तो करूंगा। बाकी मेरी एक गुजराती फिल्म रिलीज होगी, एक और गुजराती फिल्म को लेकर बातचीत भी हो रही है, वह भी जल्द शुरू होगी। मुझे ऐसे रोल चाहिए, जो बतौर कलाकार मुझे चुनौती दें। मैं फिलहाल काफी व्यस्त भी चल रहा हूं। दो बच्चों का पिता हूं। अपने बच्चों और पत्नी इशिता (अभिनेत्री इशिता दत्ता) के साथ समय बिता रहा हूं। ब्रेक लिया है, देख रहा हूं कि आगे और क्या करना है।

@vishaljethwa06

अब एक्शन मोड में आए विशाल जेठवा

फिल्म मर्दानी 2 में अभिनेत्री रानी मुखर्जी के सामने खलनायक की भूमिका निभाकर अभिनेता विशाल जेठवा ने खूब प्रशंसा बटोरी थी। हालांकि, उसके बाद उन्होंने फिल्म सलाम वेंकी हो या होमबाउंड अलग-अलग जानर की फिल्मों को प्राथमिकता दी। आगामी दिनों में वह अभिनेत्री शालिनी पांडे के साथ फिल्म शक्ति शालिनी में नजर आएंगे। उन्होंने अपनी अगली फिल्म की तैयारी भी शुरू कर दी है। उनकी अगली फिल्म एक एक्शन फिल्म है, जिसके लिए उन्हें काफी शारीरिक तैयारी करनी पड़ेगी। फिल्म के लिए उन्हें करीब 12 किलो वजन बढ़ाना है। चूंकि विशाल हमेशा से दुबले पतले शरीर वाले रहे हैं, तो इसके लिए विशाल ने अपने योग अभ्यास तथा खानपान की आदतों में भी बदलाव किया है। विशाल ने बताया कि जब आप किसी खास प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी दिनचर्या का हर पहलू मायने रखता है।

'3 इडियट्स' का सीक्वल : जहां अंत, वहीं से शुरुआत

फिर साथ दिखेंगे राजकुमार व आमिर ● इंटरनेट मीडिया

कुछ दिनों पहले अभिनेता आमिर खान ने फिल्म 3 इडियट्स की सीक्वल बनने को लेकर पुष्टि की थी। खबरें हैं जल्द ही राजकुमार हिरानी और आमिर 3 इडियट्स की सीक्वल की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप देने के लिए एक फाइनल मीटिंग करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीक्वल को लेकर आमिर और राजकुमार के बीच नियमित तौर पर बातचीत हो रही है। इस फिल्म को लेकर उनके बीच करीब छह बैठकें हो चुकी हैं। अब जल्द ही दोनों के बीच सातवीं बैठक होगी। उसके बाद फिल्म पर आगे का काम शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है सीक्वल की कहानी वहीं से शुरू होगी, जहां पर मूल फिल्म की कहानी खत्म हुई थी। मूल फिल्म उस पड़ाव पर खत्म हुई थी, जहां रैंचों के दोस्तों फरहान और राजू को लद्दाख में पता चलता है कि रैंचो का असली नाम फुंगसुक वांगडू है।

इसलिए सुरेश ने रखा फिल्म का नाम मां बहन

शीर्षक दमदार हो, तो फिल्म की ओर ध्यान खींचना आसान हो जाता है। इसी उद्देश्य के साथ निर्देशक सुरेश त्रिवेणी अपनी फिल्मों का शीर्षक तय करते हैं। तुम्हारी सुलू और जलसा जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके सुरेश की अगली फिल्म मां बहन चार जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस शीर्षक को रखने के पीछे के कारण और जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हुए सुरेश कहते हैं कि मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हों, मेरे लिए शीर्षक हमेशा से बहुत मायने रखता आया है। इस फिल्म की कहानी मां रेखा और उसकी दो बेटियों जया और सुषमा की है, तो मेरे लिए बेहद आसान था कि मैं इसका शीर्षक मां बहन रख दूं। इससे बेहतर क्या हो सकता था। मैं विज्ञापन जगत से आता हूं, मेरे लिए शीर्षक को दिलचस्प और आकर्षक बनाना आदत का हिस्सा है। जब मैंने कहानी लिखी, तो आसान था यह शीर्षक रखना। तुम्हारी सुलू शीर्षक भी ऐसे ही आया था।

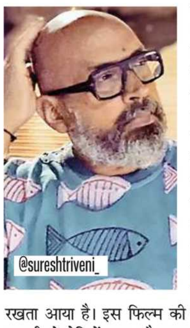

@sureshtriveni_

फोन किया तब पता चला की मिल गई है तेरे मेरे सपने: चंद्रचूड़ सिंह

आज भले भी आडिशन की प्रक्रिया व्यवस्थित हो गई हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तभी तो अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह को रोल मिल भी गया था और उन्हें पता भी नहीं चला था। उन्होंने फिल्म तेरे मेरे सपने (1996) से अभिनय में कदम रखा था। आडिशन के दिनों की बात करते हुए वह बताते हैं कि मैं पहले आज की तरह कास्टिंग एजेंसी नहीं थी। पता चलता था कि कहीं आडिशन हो रहा है, तो चला जाता था। कई बार वहां रिजेक्ट हो जाता था। दिल भी टूटता था। धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि आपका समय भी सही होना चाहिए। जब मैंने तेरे मेरे सपने फिल्म के लिए आडिशन दिया था, तो उसी दौरान फिल्म की स्क्रिप्ट दी गई थी। जया बच्चन, अमिताभ बच्चन व सचिन पिलगांवकर ने मेरा आडिशन लिया था। जब आडिशन के बाद कोई फोन नहीं आया, तो मुझे लगा की मुझे फिल्म नहीं मिली। दस दिन बाद मैंने ही सामने से काल किया, तो उन्होंने कहा कि माफ कीजिए बताना भूल गए थे, आपको यह फिल्म मिल गई है।

हमेशा से हीरो वाले रोल ही करना चाहते थे चंद्रचूड़ ● इंटरनेट मीडिया

मनोरंजन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

JOIN OUR PAID SERVICE – 2026

Daily PDF Access | Editorial Bonus | Almost All Editions

ENGLISH NEWSPAPERS

The Hindu, Indian Express, Hindustan Times, Business Line, Business standard, The Live Mint, Times of India, Telegraph, New Indian Express, Asian Age, Statesman, Tribune, Pioneer, Financial Express, The Economic Times, Mid-Day, Deccan Chronicle, Employment News, Free Press Journal, Hans India, Deccan Herald, Lokmat Times, Mirror, Telangana Today

HINDI NEWSPAPERS

दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, बिज़नेस स्टैण्डर्ड, राजस्थान पत्रिका, हरी भूमि, लोकसत्ता , पायनियर , दैनिक ट्रिब्यून , द हिन्दू, राष्ट्रीय सहारा , नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, जनसत्ता, देशबंधू, प्रभात खबर, दैनिक नवज्योति, आईनेक्स्ट लाइव, लोकमत, नव भारत, नई दुनिया

Bonus Included :

- The Hindu Analysis
- Editorial Complation
- The Hundu in Hindi

Bonus Included :

- The Hindu Analysis
- Editorial Complation
- The Hundu in Hindi

Full Package : All in One Plan

The Hindu Plan

(Starter) 1 Month = ~~199~~ ₹99
(Popular) 6 Month = ~~599~~ ₹349
(Best Value) 1 Year = ~~999~~ ₹549

Special Offer

You will Get

- 20+ Hindi Newspapers
- 22+ English Newspapers
- THE Hindu, BL,IE,TOI,ET, etc..
- Dainik Jagran, NBT, DB, Etc..
- Editorial Complation (En & Hi)
- The Hindu Analysis

You Get All Editions of These Premium Newspapers

The Hindu, BL, IE, NIE Plan

The Hindu Plan

(Starter) 1 Month = ~~149~~ ₹69
(Popular) 6 Month = ~~499~~ ₹269
(Best Value) 1 Year = ~~799~~ ₹399

Special Offer

You will Get

- The Hindu (TH)
- Business Line (BL)
- Indian Express (IE)
- New Indian Express (NIE)
- Editorial Complation
- The Hindu Analysis

You Get All Editions of These Premium Newspapers

Order Now

LIMITED TIME OFFER

Telegram Access Available

→ CLICK HERE & JOIN NOW